Binod Ranjan Prasad
NOTARY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण,पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष,

(कोलकाता)

मूल आवेदन संख्या - 107/2025

(पूर्व मूल आवेदन संख्या 206/2025 मुख्य बेंच, नई दिल्ली) के मामले में:

मंटू सोनी..आवेदक

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य..............प्रतिवादी

<u>अनुलग्नक</u>

Sl. No	Particular	enclose	Page No.
1.	प्रतिवादी 03,04 एवं 06 का	प्रतिउत्तर	1-43
2.	अनुलग्नक 01,	विधानसभा,झारखंड जवाब	44
3.	अनुलग्नक 01 A	office memorandum (EC)	45
4.	अनुलग्नक 01B	सड़क मार्ग से परिवहन का अभिलेख उपलब्ध नहीं से सम्बंधित सूचना	46
5.	प्रतिवादी का 01C	F.C शर्त 9 उल्लंघन रिपोर्ट	47-58
6.	अनुलग्नक 01D.	अंतरिम जांच रिपोर्ट	59-61
7.	अनुलग्नक 02,	क्षेत्र में वन्य जीवों की सूची।	62-68
8.	अनुलग्नक 02A	वन मंजूरी स्टेज 2 (FC)	69-71
9.	अनुलग्नक 02B	पर्यावरणीय मंजूरी (EC)	72-77
10.	अनुलग्नक 03	सुप्रीम कोर्ट आदेश C.A 6249/2021	78-79
11.	अनुलग्नक 03 A	सुप्रीम कोर्ट आदेश miscellaneous application No 1824/2023	80-84

मन्टु सोनी उर्फ़ रवि नाथ

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

12.	अनुलग्नक 03B	पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) 10 वीं संशोधन	85-94
13.	अनुलग्नक 04	वन्य जीव प्रबंधन प्रतिवादी 04 संदर्भ में रिपोर्ट	95
14.	अनुलग्नक 05	एनटीपीसी ट्रांसपोर्टेशन/ओबी से मौत का पेपर कटिंग	96-98
15.	अनुलग्नक 05	वन्य जीव नुकसान का आंकड़ा	99
16.	अनुलग्नक 07	वन्य जीवों के कारण जान माल,फसल,अनाज नुकसान और दिया गया मुआवजा विवरण	100-103
17.	अनुलग्नक 08	क्षेत्र में संचालित परियोजनों द्वारा वन्य जीव पर प्रबंधन की स्थिति रिपोर्ट	104
18.	अनुलग्नक 09	प्रतिवादी 04 द्वारा FC उल्लंघन रिपोर्ट	105-106
19.	अनुलग्नक 10.	प्रतिवादी 04 द्वारा EC शर्त उल्लंघन रिपोर्ट	107-109
20.	अनुलग्नक 11	प्रतिवादी 3 द्वारा गलत रिपोर्ट बनाने पर अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड का रिपोर्ट	110-116

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Binod Ranjan Prasad
NOTARY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण,पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष, (कोलकाता)

मूल आवेदन संख्या - 107/2025

(पूर्व मूल आवेदन संख्या 200/2025 मुख्य बैंच, नई दिल्ली) के मामले में:

मंटू सोनी..आवेदक

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य..............प्रतिवादी

आवेदक के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (कोलकाता) मूल आवेदन संख्या 107/2025 के प्रतिवादी 03 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखंड,रांची,प्रतिवादी 04 NTPC Ltd. PAKRI BARWADIH COAL MINING PROJECT एवं प्रतिवादी संख्या, 06 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, झारखंड के उत्तर का संयुक्त प्रतिउत्तर.

1. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत,पिता श्री राजेश कुमार बड़कागांव,जिला हजारीबाग (झारखंड) पिन कोड - 825311 द्वारा किया गया है । जो संविधान के अनुच्छेद 51 (A) (g) के तहत आवेदक का अधिकार/कर्तव्य है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र/याचिका दिनांक 23.01.2025 के द्वारा उपरोक्त मूल आवेदन दाखिल किया गया था । माननीय प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 08.05.2025 के आदेश के माध्यम से मामले में नोटिस जारी करने के बाद माननीय न्यायाधिकरण की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता को स्थानांतरण किए जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 04 NTPC Ltd.PAKRI BARWADIH COAL MINING PROJECT ने दिनांक 14.07.2025 को हलफनामा दायर दिया एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण पूर्वी क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 17.07.2025 के आदेश के आलोक में

प्रतिवादी संख्या 03 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड एवं प्रतिवादी संख्या 06 , वन्य जीव प्रतिपालक,रांची झारखंड के द्वारा दिनांक 22.07.2025 को माननीय न्यायालय में हलफनामा दायर किया गया था। इसके उपरांत माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 24.07.2025 के आदेश के आलोक में क्षमा सहित प्रतिउत्तर दे रहा हूं.

2. यह कि आवेदक द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष भारत सरकार (MOEF & Cc) द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 जिसके कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का अनिवार्य शर्त था,(किसी प्रकार के सड़क मार्ग एवं कन्वेयर संचालन/भार क्षमता/पैमाना का जिक्र नहीं, जिससे प्रयोक्ता अभिकरण को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति लिए जाने का प्रावधान का जिक्र नहीं) ,का उल्लंघन पश्चिमी वन प्रमण्डल हज़ारीबारा के अधिकारियों की मिलीभगत और निजी लाभ प्राप्त कर उक्त शर्त का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से बाणादाग तक एनटीपीसी द्वारा कंवेयर सिस्टम और सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने एवं सड़क मार्ग से कोयला परिवहन को लेकर अब तक दर्जनों आम नागरिकों की मौत एवं अति संरक्षित,संरक्षित एवं सामान्य वन्य जीवों का संतुलन एवं आवागमन प्रभावित होने वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी में घुसने के कारण मानव जीवन के जान माल, कृषि को नुकसान को लेकर आवेदन दिया गया था।

3. यह कि आवेदक द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से शर्तों में छूट/संशोधन का आदेश लेकर तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग/गलत व्याख्या कर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन किया/करवाए जाने का उल्लेख किया था। जबकि FOREST CLEARANCE और ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) दो

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 396/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

अलग-अलग विषय/कानून है,और दोनों डिवीजन के अलग-अलग मानकों के अनुसार शर्तों का पालन करना अनिवार्य किए जाने का उल्लेख किया गया था।

4. यह कि आवेदक द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 17 अगस्त 2024 को मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार को 12 अगस्त 2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड को शिकायत किए जाने के बाद वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के श्री सुनित भारद्वाज के पत्र दिनांक 08/09/2024 के आलोक में प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री जलज कुमार के द्वारा दिनांक 07/10/2024 को प्रतिवादी 06 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड से शिकायत के विषयवस्तु पर जांचोपरांत यथाशीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। एवं उसी पत्र में पूर्व में आवेदक के शिकायत पर विभागीय पत्रांक 1174, दिनांक 29/03/2023, विभागीय पत्रांक-2043 दिनांक 02/06/2023, विभागीय पत्रांक 2661 दिनांक 14/07/2023, पत्रांक 251 दिनांक- 25/01/2024, विभागीय पत्रांक 835 दिनांक 11/03/2024 एवं पत्रांक 3615 दिनांक 06/08/2024 एवं दिनांक 07/10/2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-IFC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन के संबंध में जांच प्रतिवेदन का मांग किए जाने का जिक्र किया गया था ।

प्रतिवादी 03, 04 एवं 06 ने आपसी तालमेल कर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(कोलकाता) से न्याय को प्रभावित करने एवं गुमराह करने के लिए तथ्यों को छुपाया,झूठा हलफनामा दायर किया और प्रतिवादी 01 और 05 के द्वारा हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

NOTARY R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

5. प्रतिवादी 03 एवं 04 द्वारा एक ही विषय पर अलग अलग और विरोधाभाषी तथ्य पेश किया जाता है :- यह कि प्रतिवादी संख्या 03 एवं 06 के तरफ से वन प्रमंडल पदाधिकारी,पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग श्री मौन प्रकाश एवं प्रतिवादी संख्या 04 की तरफ से AGM श्री बीरेंद्र कुमार ने माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दायर हलफनामा में कहा है कि,उनके द्वारा प्राप्त जानकारी एवं न्यायहित में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उनकी जानकारी में शपथपत्र दायर किया जा रहा है। परंतु उनके द्वारा जानबूझकर निजी लाभ के लिए **(विवरण/कारण कंडिका 22A,22B में वर्णित)** न्याय को प्रभावित करने एवं माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह एवं भ्रमित करने के लिए तथ्यों को छुपाया गया है और अपनी सुविधानुसार तथ्यों को छुपाते हुए हलफनामा दायर किया गया है। इसके पूर्व भी उनके द्वारा दायर वाद में उठाए विषयों के संदर्भ में **माननीय विधानसभा झारखंड एवं सूचनाधिकार में अलग- अलग तथ्य प्रस्तुत किया गया है । जिसे माननीय न्यायाधिकरण से छुपाते हुए न्याय को प्रभावित करने के लिए भिन्न और विरोधाभाषी तथ्य प्रस्तुत कर हलफनामा दायर किया गया है**,प्रतिवादी 01 एवं 05 द्वारा हलफनामा दायर नहीं किया गया है ।

6. **प्रतिवादी 03 एवं 04 ने माननीय विधानसभा झारखंड को दिया झूठा जवाब जिसे माननीय न्यायाधिकरण से भी छुपाया :-** यह कि तत्कालीन माननीय विधायक श्री लोबिन हेंब्रम द्वारा झारखंड विधानसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 2 में यह पूछा गया था कि "क्या यह बात सही है कि Forest clearance के शर्तों का उल्लंघन कर कन्वेयर बेल्ट बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई के लिए वन विभाग एनटीपीसी को Transit permit अभी तक जारी करते आ रही है के सवाल पर वन विभाग की तरफ से प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी से

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 395/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

पूछकर विधानसभा झारखंड में यह जवाब दिया गया कि "मुख्य महाप्रबंधक, पंकरी बरवाडीह एनटीपीसी लिमिटेड ने (प्रतिवादी 04) अपने पत्रांक 23 दिनांक 10 फरवरी 2023 से सूचित किया है कि विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि व्यवस्था के चलते अभी तक कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है, फलस्वरुप उनके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक दिनांक 27/29. 10. 2020 के प्रावधान (जो EC के लिए मान्य था,FC के लिए नहीं जिसका विवरण अगले कंडिका में वर्णित) के आलोक में तत्काल सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है । उपरोक्त परिपेक्ष्य में trasit permit निर्गत किया जा रहा है "

- उपरोक्त जवाब से प्रतिवादी 03 एवं प्रतिवादी 04 द्वारा माननीय झारखंड विधानसभा को कन्वेयर सिस्टम के पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होने की बिना दस्तावेज टेक्निकल रिपोर्ट के गलत और भ्रामक जानकारी दी गई थी।
- क्योंकि FC शर्त संख्या 9 में कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का शर्त दिया गया था,उसमें कन्वेयर कार्यरत होने या नहीं होने,एवं इसका पैमाना आदि का कोई उल्लेख नहीं किया किया गया था। जिससे उसे सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की छूट प्रदान किया जाता ।
- विधानसभा झारखंड में पूछे गए सवाल का जवाब प्रतिवादी 03 को विभागीय अभिलेख के अनुसार देना चाहिए था ।लेकिन उनके द्वारा प्रतिवादी 04 से पूछकर विधानसभा में जवाब भेजा गया।
- उपरोक्त से यह साबित होता है प्रतिवादी 03 और प्रतिवादी 04 में निजी स्वार्थ लिए आपस में गहरी सांठगांठ है । **(विवरण/कारण कंडिका 22A,22B में वर्णित)** दोनों प्रतिवादियों के द्वारा विधानसभा झारखंड में पूरी तरह से झूठा जवाब दिया गया था।
- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दिया गया जवाब/अभिलेख को माननीय न्यायाधिकरण कोलकाता को अपने हलफनामा में छुपाते हुए पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादियों के आपसी सांठगांठ से हलफनामा दायर कर तथ्यों को छुपाते हुए गलत और भ्रामक जवाब दिया गया है

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 से पूछकर जो जवाब विधानसभा झारखंड में दिया उस दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के त्रिपुरारी सिंह एवं अन्य मामले में सिविल अपील नंबर C.A 6249/2021 पर दिनांक 08.08.2022 के आदेश में अक्टूबर 2023 तक या उससे पहले कन्वेयर कंस्ट्रक्शन पूर्ण करने का दिया गया आदेश प्रभावी था। (कंडिका 17,अनुलग्नक 03) लेकिन उक्त आदेश को दोनों प्रतिवादियों ने जानबूझकर विधानसभा झारखंड में प्रस्तुत नहीं किया ।

(अनुलग्नक - 01)

6.A) दस्तावेजों का गलत व्याख्या कर FC शर्त 09 के उल्लंघन का बचाव विधानसभा झारखंड में सिर्फ EC के लिए मान्य 0FFICE MEMORANDUM से किया:- यह कि (कंडिका 06,अनुलग्नक 01) से यह स्पष्ट होता है कि माननीय विधानसभा झारखंड में पूछे गए सवाल का जवाब प्रतिवादी 03 द्वारा सरकारी अभिलेखों से नहीं देकर प्रतिवादी 04 से पूछकर दिया गया था । माननीय विधायक लोबिन हेंब्रम द्वारा सवाल FOREST CLEARANCE (FC) के उल्लंघन को लेकर पूछा गया था और उसका जवाब सिर्फ ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के लिए मान्य 0FFICE MEMORANDUM का हवाला देकर दिया गया । विधानसभा को दिए जवाब में भारत सरकार के पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक दिनांक 27/29. 10. 2020 के 0FFICE MEMORANDUM को आधार बनाते हुए सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने को बताया गया था । जबकि उसी अधिसूचना के कंडिका 4 में यह स्पष्ट किया गया था कि यह अधिसूचना सिर्फ ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के लिए ही मान्य होगा। उपरोक्त तथ्य/साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि निजी लाभ के लिए (विवरण/कारण कंडिका 22A,22B में वर्णित) प्रतिवादी 03 और 04 ने माननीय विधासभा झारखंड में दस्तावेजों का गलत व्याख्या करते हुए झूठा,गलत और भ्रामक जवाब दिया गया था।

(अनुलग्नक- 01 A)

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
398/2010
GOVT. OF JHARKHAND

7. **प्रतिवादी 03 ने सूचनाधिकार के तहत जवाब में बताया कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/नहीं करने संबंधी अभिलेख कार्यालय में नहीं है :-** यह कि आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत द्वारा सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07/10/2022 को पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग कार्यालय में पूछे गए सूचना संख्या 3 जिसमें "एनटीपीसी (प्रतिवादी 04) के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग़ रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का परिवहन/वन विभाग का विभागीय आदेश निर्गत है,तो उसकी शर्तों के साथ विभागीय आदेश कॉपी का विवरण उपलब्ध कराया जाए" के जवाब में दिनांक 02/11/2022 को कहा गया था कि "एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग़ रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/नहीं करने से संबंधी कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है"। उपरोक्त जवाब माननीय न्यायाधिकरण को न्याय प्रभावित एवं गुमराह करते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने हलफनामा में छुपा लिया है।

- उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 02/11/2022 तक कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन/नहीं करने का कोई अभिलेख प्रतिवादी 03 के पास नहीं था, तो वर्तमान में माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी ने सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने से सम्बंधित अपने हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख/पक्ष दिया है, वह कब और किस माध्यम से प्राप्त हुआ ? FC शर्त 9 के उल्लंघन के मामले में इस अभिलेख को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी 03 से बार बार जांच प्रतिवेदन मांगे जाने के बाद क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।
- माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी 03 ने अपने हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख/पक्ष/तर्क दिया है। आवेदक द्वारा FC शर्त 9 के उल्लंघन से संबंधित शिकायत पर वन पर्यावरण एवं

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के श्री सुनित भारद्वाज के पत्र दिनांक 08/09/2024 के आलोक में प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री जलज कुमार के द्वारा दिनांक 07/10/2024 से पूछे गए जांच प्रतिवेदन को (प्रतिवादी 03) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड से शिकायत के विषयवस्तु पर जांचोपरांत यथाशीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त पत्र का जवाब भारत सरकार को अब तक नहीं दिया गया है।

- उक्त पत्र में ही आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए शिकायत पर विभागीय पत्रांक 1174,दिनांक 29/03/2023,विभागीय पत्र -2043 दिनांक 02/06/2023, विभागीय पत्रांक 2661 दिनांक 14/07/2023, पत्रांक 251 दिनांक- 25/01/2024, विभागीय पत्रांक 835 दिनांक 11/03/2024 एवं पत्रांक 3615 दिनांक 06/08/2024 एवं दिनांक 07/10/2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखंड प्रतिवादी 03 ने झारखंड सरकार और भारत सरकार को **निजी लाभ के लिए उपलब्ध नहीं कराया।**
- उपरोक्त पत्राचार को आवेदक ने याचिका के मूल आवेदन के (ANNEXURE 3) में अनुलग्नक के रूप में वर्णित किया है।

(अनुलग्नक 01 B)

8. प्रतिवादी 02 के स्थल निरीक्षण में FC शर्त 9 के उल्लंघन की हुई पुष्टि :- यह कि प्रतिवादी 02 भारत सरकार के पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय हरमू,रांची के पत्रांक- 717 दिनांक 25/11/2022 को श्री चरणजीत सिंह वैज्ञानिक ' डी' (FC Division) (MOEF &Cc) भारत सरकार को भेजी गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के पेज नंबर 6 में यह उल्लेखित है कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी कन्वेयर सिस्टम के साथ- साथ सड़क मार्ग से भी कोयला परिवहन कर रहा है। जो FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का आंशिक उल्लंघन करता है। इस रिपोर्ट को भी सभी प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण से छुपाते हुए अपने हलफनामा में नहीं बताया है।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

इससे भी प्रमाणित होता है कि प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण को न्याय से गुमराह करने के लिए निजी स्वार्थ में पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए अपने हलफनामा में जिक्र नहीं किया ।(विवरण/कारण कंडिका 22A,22B में वर्णित)

- इससे यह पुष्टि होता है कि दिनांक 25.11.2022 के पूर्व कन्वेयर सिस्टम चालू हो गया था और प्रतिवादी 04 के द्वारा FC शर्त संख्या 9 का उल्लंघन किया जाता रहा । जिसपर अन्य प्रतिवादियों ने निजी लाभ के पूर्ति के लिए अब कोई कार्रवाई नहीं किया और माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी 03 ने अपने हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख/पक्ष/तर्क दिया है वह न्याय को प्रभावित करने के लिए गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किया है।

(अनुलग्नक 01 C)

9. प्रतिवादी 03 के दो सदस्यीय जांच रिपोर्ट में FC शर्त 09 के उल्लंघन कि हुई पुष्टि,पांच महीने तक दबाया,माननीय न्यायाधिकरण से भी छुपाया:- यह कि आवेदक के द्वारा FOREST CLEARANCE के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन के मामले में शिकायत के आलोक में वन संरक्षक,प्रादेशिक अंचल हजारीबाग के पत्रांक - 1892 दिनांक 29/11/2024 को दो सदस्यीय जांच कमिटी का गठन किया गया था। जांच कमिटी ने दिनांक - 27/02/2025 को वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,हजारीबाग को अंतरिम जांच प्रतिवेदन सौंप दिया था। जांच टीम ने अपने मंतव्य में लिखा कि, प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का निर्ममता से उल्लंघन कर रही है। वन्य जीवों के आवागमन (विशेषकर हाथी) बाधित नही होने के जिस मूल उद्देश्य से यह शर्त लगाया गया था, उसका उल्लंघन अब तक किया जा रहा है। जिसके कारण वन्य जीवों (विशेषकर हाथी) का आवागमन बाधित हुआ और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी वाले इलाकों में आकर आम नागरिकों के जानमाल/कृषि का नुकसान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले बाणादाग रेलवे साइडिंग व हज़ारीबाग़ शहर के नजदीक खिरगांव तक हाथी भटक कर आ गए थे। सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन के कारण दुर्घटनाओं में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बात

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND

Scanned by Scanner Go

सत्य है कि एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्त में संशोधन लेकर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। जिसका FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 से कोई संबंध नहीं है। ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) और FOREST CLEARANCE दो अलग-अलग पार्ट है। दोनों के द्वारा लगाई गई शर्तो का मानक और उद्देश्य अलग-अलग होता है।लेकिन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्तो में संशोधन लेकर FOREST CLEARANCE के शर्तो का अनुपालन नहीं कर रहा है। परिवादी मंटु सोनी उर्फ शनि कांत को जन सूचना पदाधिकारी द्वारा उचित सूचना भी उपलब्ध नही कराया गया है। इसलिए भवदीय से FOREST CLEARANCE स्टेज 2. F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का अनुपालन सख्ती से करवाने की अनुसंशा जांच कमिटी द्वारा किया जाता है। उक्त शर्त के पालन की जिम्मेवारी वन विभाग का कर्तव्य/दायित्व होता है। इसका उल्लंघन FOREST CONSERVATION ACT 1980 एवं WILD LIFE PROTECTION ACT 1972 के तहत आता है।

- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन 27.02.2025 को दे दी गई थी।लेकिन प्रतिवादी संख्या 03 ने माननीय न्यायाधिकरण में दिनांक 22.07.2025 के हलफनामा में छुपाते हुए उपलब्ध नहीं कराया है।
- प्रबल आशंका है कि उक्त रिपोर्ट को प्रतिवादी 04 से सांठगांठ कर निजी लाभ के लिए साजिश के तहत दबाया गया था और उसे माननीय न्यायाधिकरण से जानबूझकर छुपाया गया और इस रिपोर्ट को दबाने,छिपाने के लिए प्रतिवादी 03 द्वारा कोई भी प्रयत्न/साजिश किया जा सकता है।जिसकी सूचना आवेदक द्वारा झारखंड सरकार को पूर्व में दिया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि माननीय न्यायाधिकरण को भी दिया गया था।
- उपरोक्त रिपोर्ट प्रतिवादी 03 के लिए हलफनामा दायर करने वाले पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मौन प्रकाश के खिलाफ के विरुद्ध शिकायत में जांच की पुष्टि हुई थी। इसलिए जानबूझकर उनके द्वारा अपने हलगनामा में उक्त रिपोर्ट को नहीं दिया और

मन्टु सोनी उर्फ शनिकांत

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 398/2010
U.T. OF JHARKHAND (INDIA)

हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख/पक्ष/तर्क दिया वह भिन्न और गलत है।

(अनुलग्नक 01 D)

10..माननीय न्यायाधिकरण में गलत,भ्रामक और झूठा हलफनामा दायर किया गया :- यह कि (कंडिका 6 से 09 अनुलग्नक 1 से 1D तक) को प्रतिवादी संख्या 03,04 एवं 06 ने उपरोक्त तथ्यों, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को माननीय न्यायाधिकरण में दायर अपने हलफनामा में कहीं भी जिक्र नहीं किया है । जो उनके अधीन आधिकारिक विभागीय दस्तावेज में था। यह उनके कपटपूर्ण मानसिकता से FC शर्त 9 के उल्लंघन का संरक्षण देने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग जवाब/सूचना देने की भी पुष्टि करता है। और जानबूझकर पद का दुरुपयोग करते हुए कपट पूर्ण मानसिकता से निजी लाभ के लिए माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह,न्याय प्रक्रिया को भ्रमित कर प्रभावित करने के लिए भ्रामक एवं अधूरा साक्ष्य प्रतिवादियों ने अपने शपथपत्र में दिया है ।

11.यह कि MOEF &CC भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लगाई गई शर्तो का पालन करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार को होती है और **संविधान के अनुच्छेद 48 (ए)** के तहत कर्तव्य का दायित्व भी राज्य सरकार को है। परंतु प्रतिवादी 03 वन विभाग और प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा EC शर्त संशोधन लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 को FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन किया/करवाया जा रहा है । इसके लिए निजी लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त FC शर्त 9 का उल्लंघन के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग तथ्यों पर आधारित सूचना/जवाब दिया जाता रहा है। जो प्रतिवादियों के गलत मानसिकता और भूमिका को प्रदर्शित करता है।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 193/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

12.अदालतों में झूठा,तथ्यों को छुपाते हुए गलत और भ्रामक जवाब दिए जाने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश:-

यह कि (कंडिका 6 से 9,अनुलग्नक 1 से 1D तक) वर्णित तथ्यों/साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी संख्या 03,04 एवं 06 ने उपरोक्त तथ्यों, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को माननीय न्यायाधिकरण में दायर अपने हलफनामा में कहीं भी जिक्र नहीं किया है । जिसे जान बूझकर आपसी सांठगांठ कर निजी फायदे के लिए छुपाया गया । इस तरह से सम्बंधित मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SUO-MOTU CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.3 OF 2021 के दिनांक 11.07.2022 के आदेश में यह कहा है कि.

The Supreme Court observed that the tendering of affidavits and undertakings containing false statement would amount to contempt of court. A person who makes a false statement before the Court and makes an attempt to deceive the Court, interferes with the administration of justice and is guilty of contempt of Court, the bench comprising Justices UU Lalit and PS Narasimha observed.

While considering this case, the court noticed an earlier decision on the question whether tendering of affidavits and undertakings containing false statement would amount to criminal contempt or not Referring to ABCD v. Union of India, the court said:

"It is thus well settled that a person who makes a false statement before the Court and makes an attempt to deceive the Court, interferes with the administration of justice and is guilty of contempt of Court. The extracted portion above clearly shows that in such circumstances, the Court not only has the inherent power but it would be failing in its duty if the alleged contemnor is not dealt with in contempt jurisdiction for abusing the process of the Court."

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार विभिन्न मामलों में माना है कि झूठा हलफनामा दाखिल करना और भौतिक तथ्यों को छिपाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है और इस प्रकार यह न्यायालय की आपराधिक अवमानना है,
- प्रतिवादियों द्वारा दायर हलफनामा न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 का उल्लंघन के अंतर्गत भी आता है।
- प्रतिवादियों का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 एवं 236 का भी उल्लंघन करने के दायरे में आता है।

प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) **के शर्त में संशोधन के तथ्यों को छुपाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने एवं अपने बचाव करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा माननीय एन.जी.टी को गुमराह किया गया है ।**

13.परियोजना अंतर्गत क्षेत्र में वन्य जीवों का घनत्व :- यह कि हजारीबाग वन परिक्षेत्र अंतर्गत शेड्यूल एक के वन्य जीव जो अति संरक्षित श्रेणी (लुप्त प्राय श्रेणी) में आते हैं, शेड्यूल दो जो संरक्षित श्रेणी में आते हैं एवं शेड्यूल तीन एवं चार कैटगरी के वन्य जीवों का घनत्व है। वन्य जीवों के सुगम आवागमन एवं संरक्षण के लिए ही प्रतिवादी 04 को FOREST CLEARANCE के शर्त संख्या 09 में कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का अनिवार्य शर्त लगाया गया था। इस प्रकार उक्त शर्त में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी लागू होता है। वन्य जीवों की सूची संलग्न है।

(अनुलग्नक:- 02)

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

14.वन अधिनियम 1980 के तहत मिले वन मंजूरी की शर्ते:- यह कि झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के पहले पैरा में यह उल्लेखित है कि.

I am directed to refer to the State Govt. letter no. 3/Vanl3humi-75/2009/2458/VP dated 06.08.2009 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principle approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 11.05.2016) subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Govemment to grant final approval.

उसके शर्त संख्या 09 जिसमें वन्य जीवों, खासकर हाथियों के सुगम आवागमन हेतु कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किए जाने का शर्त लगाया गया था। जिसमें स्पष्ट यह उल्लेख है कि

"9.The coale evacuation will be done through high speed conveyer of 20 meter width running at n height sufficient to allow all tall wild animals including elephants.The installation of such system will be undertaken under the supervision of the CWLW of the State"

- इसमें किसी प्रकार के सड़क या कन्वेयर की लोडिंग क्षमता या सुचारू रूप से संचालन का पैमाना का जिक्र नहीं है,जिससे उसे सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की छूट दिया जा सके ।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 39/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- उपरोक्त विवरण यह स्पष्ट करता है कि उक्त शर्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भी लागू होता है क्योंकि वन्य जीवों के सुगम आवागमन के लिए कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन का शर्त दिया गया था।
- प्रतिवादी 03,06 ने उपरोक्त शर्त के उल्लंघन के बचाव में माननीय न्यायाधिकरण को दायर हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 तथा प्रतिवादी 04 ने कंडिका H में जो पक्ष /विवरण दिया है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के शर्तो के अधीन है। जिसके कंडिका 5 में स्पष्ट किया हुआ है कि उक्त शर्तो में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत शर्तो के प्रभावी होने का उल्लेख नहीं है।

(अनुलग्नक:- 02 A)

15. **प्रतिवादी 03.04, एवं 06 द्वारा FC शर्त संख्या 09 के उल्लंघन में EC के शर्त संख्या 2A (ix) को गलत व्याख्या कर बचाव किया लेकिन EC के शर्त संख्या 5 को माननीय न्यायाधिकार से छुपाया गया :-** यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (EZ) कोलकाता के वाद संख्या OA no - 107/2025 में प्रतिवादी 03 एवं 06 की ओर से वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मौन प्रकाश पश्चिमी वन प्रमंडल,हजारीबाग के हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 एवं प्रतिवादी संख्या 04 ने अपने हलफनामा के कंडिका H में यह स्वीकार किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन लेकर किया जा रहा है जिसमें अब तक 10 वीं संशोधन लिया गया है। इसमें निम्नवत उल्लेखित है ।

- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall

NOTARY B. P. PRASAD HAZARIBAG GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation_from.CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System.

- (किसी प्रकार के सड़क या कन्वेयर की लोडिंग क्षमता या सुचारू रूप से संचालन का पैमाना का जिक्र नहीं है, जिससे सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की अनुमति मिल सके)
- विशेष रूप से यह भी उल्लेख करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के कंडिका 5 में वर्णित तथ्यों को माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादियों द्वारा जानबूझकर छुपा लिया गया है । जो वर्णित है।
- The above conditions shall be governed by, among others, the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि EC के उक्त शर्त में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लगाए गए शर्तो पर प्रभावी नहीं है और उसपर लागू नहीं होता है ।

(अनुलग्नक 02 B)

NOTARY
B. S. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
.../2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

16.यह कि कंडिका 14 एवं 15 में वर्णित विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी 03,04(एनटीपीसी) एवं 06 द्वारा माननीय न्यायाधिकरण को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मिले स्टेज 2 वन मंजूरी (FC) दिनांक 17.09.2010 के शर्त 9 का उल्लंघन ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) के शर्त में संशोधन लेकर किया जा रहा है । जबकि उसी EC के कंडिका 5 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मिले स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 पर प्रभावी नहीं होता है। जिसे जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण से न्याय को प्रभावित करने के लिए निजी फायदे के लिए प्रतिवादियों द्वारा छुपाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 04 एनटीपीसी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी किया गया गुमराह और किया जा रहा है अवमानना

17.माननीय न्यायाधिकरण ने तीन महीने में प्रतिवादी 04 को दिया था कन्वेयर बेल्ट बनाने का आदेश,सुप्रीम कोर्ट से दो साल का लिया समय :- यह कि प्रतिवादी संख्या 04 एनटीपीसी को माननीय न्यायाधिकरण कोलकाता ने त्रिपुरारी सिंह बनाम रेलवे मंत्रालय 0A no 61/2019/EZ में दिनांक 06.01.2021 के आदेश में प्रयोक्ता अभिकरण को तीन महीने में कन्वेयर बेल्ट बनाने का आदेश दिया था। उक्त फैसले के विरुद्ध प्रतिवादी 04 ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE दिनांक 19.05.2009 के पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन लेने के लिए (जो FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 393/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 से संदर्भित नहीं है) अपील दायर किया। प्रतिवादी ने त्रिपुरारी सिंह एवं अन्य मामले में सिविल अपील नंबर C.A 6249/2021 किया। उपरोक्त अपील पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 08.08.2022 के आदेश में अक्टूबर 2023 तक या उससे पहले कन्वेयर कंस्ट्रक्शन पूर्ण करने का आदेश दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी 04 द्वारा EC शर्त में संशोधन लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लिया और FC शर्त संख्या 09 (कंडिका 15 अनुलग्नक 02 A) जो वन्य जीवों के सुगम आवागमन को लेकर कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का अनिवार्य शर्त था। को माननीय सुप्रीम कोर्ट से छुपाते हुए उसपर कोई संशोधन या छूट मंत्रालय से भी नहीं लिया । और उसका उल्लंघन अभी तक करते आ रहा है ।

(अनुलग्नक 03)

18. प्रतिवादी 04 ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित समय से पहले कन्वेयर सिस्टम बनाया :- यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरारी सिंह एवं अन्य मामले में सिविल अपील नंबर C.A no 6249/2021 दिनांक 08.08.2022 के आदेशानुसार **(अनुलग्नक 03)** अक्टूबर 2023 के पहले प्रतिवादी 04 एनटीपीसी ने कन्वेयर सिस्टम बना लिया था। जिसकी पुष्टि (कंडिका अनुलग्नक 01B) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्रांक 3643 दिनांक 2/11/2022 के सूचना संख्या एक और दो से होती है। जिसमें यह जानकारी मांगी गई थी कि "एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट और ट्रक से कोयला परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया कर रहा है ?हां या नहीं ? उपरोक्त दोनों सूचना के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया था कि "एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट और ट्रक से कोयला परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है" इससे स्पष्ट होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 6249/2021 के आदेश के आलोक (कंडिका 17 अनुलग्नक 3) में अक्टूबर 2023 से पहले दिनांक 2/11/2022 तक कन्वेयर सिस्टम बनकर तैयार हो गया था । और वह सुचारू रूप से संचालित था। इसके साथ कन्वेयर सिस्टम बन जाने की पुष्टि भारत सरकार के पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय हरमू चौक रांची के पत्रांक 717 दिनांक 25/11/2022 से भी होती है । जिसके पेज नंबर

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 93/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

6 में यह उल्लेखित है कि प्रयोक्ता अभिकरण कन्वेयर सिस्टम के साथ सड़क मार्ग से भी कोयला परिवहन कर रहा है। जो FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का आंशिक उल्लंघन का पुष्टि (कंडिका 9 अनुलग्नक 01C) से भी होता है,जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया था । जो प्रमाणित करता है कि दिनांक 25.11.2022 के पहले कन्वेयर सिस्टम बन चुका था ।

19.कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद भी प्रतिवादी 04 ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर आदेश लिया:- यह कि (कंडिका 8 अनुलग्नक 01B) एवं (कंडिका 9 अनुलग्नक 01C) से यह प्रमाणित करता है कि कन्वेयर सिस्टम नवंबर 2022 में चालू हो गया था। जिसके लिए वन विभाग अनुज्ञा परमिट जारी कर रही है। उसके बाद भी प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी के द्वारा पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 दाखिल किया एवं माननीय न्यायालय को गुमराह किया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दिनांक 20.10.2023 को यह अंतरिम आदेश दिया ।

a) Allow the present application; and.

b) Extend the timeline for completion of the entire Coal Conveying System facilities /CHP [from mine to Railway siding] at Appellant's Pakri Barwadih Coal Mine Project, Barkagaon, Hazaribag, until 31st December, 2024"

Earlier, this Court by its order on 08.08.2022 had extended the timeline for completion of the construction of the conveyor belt till 31.10.2023.

इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर माननीय सर्वोच्च से दिनांक 29.01.2024 के आदेश में 31 दिसम्बर 2024 तक दुबारा कन्वेयर सिस्टम पूर्णतः बनाने का आदेश लिया गया।

(अनुलग्नक 03 A)

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट मे गुमराह करने वाला हलफनामा दायर कर अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर 2024 तक निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का आदेश निर्गत करवाया । जबकि कन्वेयर सिस्टम नवम्बर 2022 में चालू हो गया था । जिसकी पुष्टि (कंडिका 8 अनुलग्नक 01B) एवं (कंडिका 9 अनुलग्नक 01C) से होती है।

20.माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समयावधि पूरा होने के बाद प्रतिवादी 04, MOEF &Cc से EC शर्त संशोधन लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कर रहा अवमानना :- यह कि प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 दाखिल करके माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2024 के आदेश से 31 दिसम्बर 2024 का आदेश लिया। (कंडिका 19 अनुलग्नक 3A) के उपरोक्त आदेश की समयावधि पूर्ण होने के बाद प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2009 के पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में दसवां संशोधन ले लिया गया और सड़क मार्ग से कोयला परिवहन कर रहा है।

- जो माननीय सर्वोच्च न्यायलय का अवमानना एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को जानबूझ कर गुमराह करने का प्रयास है।
- इसके बाद भी उपरोक्त संशोधन लेकर प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा खनन स्थल से लेकर रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है ।
- जिसके कारण उस उद्देश्य की पूर्ति और पालन नहीं हो रहा है। जिसके लिए कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का FC स्टेज 2 शर्त संख्या 9 लगाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29.01.2024 को आदेश दिया था।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- प्रतिवादी 04 को EC के शर्त में संशोधन लेने के लिए जो कारण बताया गया था,वहां से सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना चाहिए था ।
- **परंतु प्रतिवादी 04 द्वारा खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक प्रतिवादी 01, 02,03,04,05,06 के सहयोग से निजी लाभ लिए सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है।**

(अनुलग्नक 0 3B)

21.मानननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादी 04 ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 को FOREST CLEARANCE स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 को छुपाया और गुमराह किया :- यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी 04 एनटीपीसी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 को FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को त्रिपुरारी सिंह एवं अन्य मामले में सिविल अपील संख्या C.A. No. 6249/2021 एवं Miscellaneous Application No. 1824/2023 (अनुलग्नक 3 और 3A) मे जानबूझकर छुपाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह भी किया गया । जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) के समतुल्य शर्त था।

- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approSpecific Condition No.- 2A (ix) के समतुल्य शर्त था।
- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation_from.CHP to Railway

NOTARY R. PRASAD HAZARIBAG Regn. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System ach roads and haul roads. Mineral transportation_from.CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System

- FC शर्त संख्या 9 में वन्य जीवों के आवागमन हेतु कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का अनिवार्य शर्त दिया गया था । जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रभावी होता है। जो वनों,वन्य जीवों और मानव- वन्य जीव द्वंद को ध्यान में रखकर अनिवार्य शर्त लगाया गया था। परंतु प्रयोक्ता अभिकरण ने इसका कोई परवाह नहीं किया और निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु बार बार माननीय न्यायालयों को गुमराह एवं उनके आदेश का अवमानना किया गया।

FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 09 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान भारी गड़बड़ीयों को छुपाते हुए प्रतिवादी संख्या संख्या 03 ,04 और 06 ने OA (EZ) 107/2025 के मूल आवेदन के महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं साक्ष्यों पर माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने हेतु भ्रामक जवाब अपने हलफनामा में दिया ।

22. वन भूमि में पेड़ काटकर सड़क मार्ग से कोयल परिवहन करने के मामले में आवेदक के शिकायत पर प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 पर दर्ज किया वनवाद पर कार्रवाई नहीं और न्यायाधिकरण को जवाब नहीं दिया :-

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- यह कि प्रतिवादी 04 ने अपने हलफनामा के कंडिका F में यह कहते हैं कि,उनके द्वारा राज्य राजमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। जो वन भूमि से बाहर है। वहीं OA (EZ) 107/2025 के मूल आवेदन के ANNEXURE 2 के कंडिका 8 में वर्णित एवं संलग्न साक्ष्यों पर प्रतिवादी 03,04 एवं 06 के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है ।
- जिसमें प्रतिवादी 04 के अधिकारियों एवं उनके एजेंसियों पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दर्ज वनवाद जिसमें प्रतिवादी 04 के लिए माननीय न्यायधिकरण में हलफनामा दायर करने वाले श्री बीरेंद्र कुमार भी नामजद आरोपी है ।
- जिसका जवाब प्रतिवादियों ने अपने हलफनामा में नहीं दिया है। प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी (प्रतिवादी 04) एवं उसके अधीन कार्य कर रही ट्रांसपोर्टर एजेंसियां पर आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत के शिकायत पर पेड़ों को काटकर जंगल के रास्ते सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करने एवं पेड़ों को काटने तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनयम 1980 का उल्लंघन करने के मामले में कंप्लेन केस नंबर 29/2021 दिनांक 30.12.2020 एवं कंप्लेन केस 33/2021 दिनांक 24/12/2020 एवं कंप्लेन केस 35/2021 दिनांक 27/12/2020 सभी में भारतीय वन अधिनियम 1927 बिहार संशोधन 1989 की धारा 33 का उल्लंघन का आरोप है ।
- इसके अलावे वन विभाग द्वारा कंप्लेन केस 3192/2020 दिनांक 20/11/2022 भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33,52 तथा कंप्लेन केस 3221/2022 दिनांक 23/11/2022 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख)(ग़) धारा 63(ग) और पांच हजार सखुआ लकड़ी का पोल काटने के मामले में वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 4812 दिनांक 18/09/2024 भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33,52 के तहत दर्ज वनवाद पर अब तक प्रतिवादी 06 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है।
- उपरोक्त मामले के प्रति वन विभाग प्रतिवादी 03 की तरफ से शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है या जानबूझकर कार्रवाई नहीं किया गया है । एवं प्रतिवादी 03 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को पद का दुरुपयोग एवं निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अवैध कार्य करने में नियमों/कानूनों,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन एवं अवमानना करते हुए

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

संविधान के अनुच्छेद 48 ए का भी अवहेलना करते हुए सहयोग किया जा रहा है।

22 A. प्रतिवादी 04 द्वारा सड़क मार्ग से टू- थी वाहनों से कोयला परिवहन में गड़बड़ियों पर प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण को अपने हलफनामा में जवाब नहीं दिया :-

- यह कि प्रतिवादी संख्या 03,04 एवं 06 ने OA (EZ) 107/2025 में आवेदक के मूल आवेदन के ANNEXURE 2 के कंडिका 6 एवं 7 का वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों को अपने हलफनामा में नहीं दिया.
- जिसमें निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 2549/एम० रांची दिनांक 09/10/2018 द्वारा JIMMS प्रणाली के द्वारा जांच में कोयला के ई परिवहन चालान द्वारा एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह खनन परियोजना से बाणादाग साइडिंग तक टू-थ्री मोटर पैसेंजर व मोटर कार से कोयला परिवहन (चालान और वाहन नम्बर सहित) किए जाने की जानकारी देते हुए जिला खनन कार्यालय हज़ारीबारा को पत्र लिखा गया था।
- जिसके बाद जिला खनन पदाधिकारी (हज़ारीबारा) श्री नितेश गुप्ता ने पत्रांक 27/खनन, दिनांक 07 जनवरी 2019 एवं पत्रांक 248/ खनन दिनांक 05/03/2019 को बड़कागांव थाना में फर्जी वाहन/चालान से कोयला परिवहन किए जाने से संबंधित व्यक्तियों/कंपनियों पर सुसंगत नियमों एवं धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
- परंतु छह साल बीत जाने के बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के W.P (Cr) 68/2008 एवं Cri Misc पिटीशन संख्या 1844/2008 ललिता कुमारी एवं उत्तर प्रदेश एवं अन्य के मामले में दिए आदेश का उल्लंघन और अवमानना करते हुए अब तक मामला दर्ज नही किया गया है ।

22 B.प्रतिवादी 04 के खिलाफ प्रतिवादी 03 द्वारा trasit permit में गड़बड़ियों का जवाब प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण को नहीं दिया : - यह कि वन विभाग प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 एनटीपीसी के कोयला ट्रांसपोर्टिंग में काफी गड़बड़ियां को पकड़ा था। जो सिर्फ एक बार के औचक निरीक्षण में पकड़ा

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 208/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

गया था।(अगर बराबर जांच किया जाता तो कई गड़बड़ी समाने आती)हज़ारीबाग पश्चिमी वन पमंडल पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 3659 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक कोयला प्रेषण विभाग को पत्र लिखा था। जिसमें एनटीपीसी द्वारा निर्गत किए गए परिवहन अनुज्ञा पत्र की द्वितीय पति (counter filo) का दिनांक 30 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 के कुछ पतियों के औचक निरीक्षण में बहुत प्रकार की विसंगतियों को पकड़ा था, जो इस प्रकार है।

(क) परिवहन अनुज्ञा पत्र JHAA112501 से JHAA1125700 तक काटे गए परिवहन अनुज्ञा पत्र आपके पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से प्राधिकृत किया गया कोई भी स्पेसिमेन हस्ताक्षर नही मिलता जो आपके द्वारा लिखे पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को अवैध ठहराता है इस प्रकार के कृत्य वन अपराध के श्रेणी में आता है।

(ख) परिवहन अनुज्ञा पत्र के लोडिंग प्वाइंट से डिस्टीनेसन प्वाइंटस की अधिकतम दूरी 30 कि. मी है। इस दूरी के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र मान्य रहने का अधिकतम समय 6 घन्टा होना चाहिए। जबकि कुछ अनुज्ञा पत्रों में अनुज्ञा पत्र मान्य का समय 24 घन्टा से 30 घन्टा तक दिया गया है जो सही नही है। निम्नलिखित अनुज्ञा पत्रों के परिवहन पत्र संख्याJHAA1125667, JHAA1125669 से लगातार JHAA115686 एवं परमिट संख्या JHAA1125692 तक सभी मे 24 घंटा से 30 घन्टा का मान्य समय दिया गया है। जो नियमानुसार सही नही है।

(ग) परिवहन अनुज्ञा पत्र कंडिका 8 में किस प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र काटा गया उसका उल्लेख नही होना भी नियमानुकूल नहीं है।

(घ) अनुज्ञा पत्र JHAA1125501 से JHAA115550 में परमिट संख्या JHAA1125501 से JHAA1155528 तक दिनांक 31 अगस्त 2021 को 11:16 AM में काटना एवं बाद के परमिट संख्या JHAA1125528 से 550 तक मे दिनांक 31 अगस्त 2021 को ही 05:04 बजे से काटना विधि सम्मत नही है।

- एक ही तिथि को वाद के परिवहन अनुज्ञा पत्र में पहले का समय देने का औचित्य को बताने को कहा गया था। वन विभाग द्वारा कोई भी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह की गंभीर गड़बड़ीयों के विरुद्ध कभी कोई औचक निरीक्षण,विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई है।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 388/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- जो प्रतिवादी 03 वन विभाग का प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी से निजी स्वार्थ हेतु मिलीभगत की पुष्टि करता है। यही कारण है कि प्रयोक्ता अभिकरण के साथ साथ वन विभाग द्वारा भी माननीय न्यायाधिकरण में भ्रामक एवं गलत हलफनामा दायर किया गया है।

22C. माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी 03.04 एवं 06 ने वन्य जीव प्रबंधन योजना पर वन्य जीवों के नुकसन को छुपाने के लिए अधूरा और न्याय को प्रभावित करने के लिए माननीय न्यायाधिकरण अधूरा जवाब दिया:-

- यह कि प्रतिवादी 04 अपने हलफनामा के कंडिका E में यह कहते हैं कि उनके द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना के लिए CAMPA खाते में 135.67 करोड़ रुपए जमा किया है।
- प्रतिवादी संख्या 03 एवं 06 ने भी अपने हलफनामा के कंडिका 15 के अंतिम पैरा में प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा विभाग को CAMPA खाते में जमा किया गया है।
- **प्रतिवादियों द्वारा बहुत चालाकी से माननीय न्यायाधिकरण को अधूरा और भ्रामक जवाब दिया गया है । क्योंकि उपरोक्त वर्णित राशि कब जमा किया गया है और उसपर क्या- क्या योजना लागू किया गया है,वह माननीय न्यायाधिकरण से छुपा लिया गया है। उनके द्वारा इस तथ्य को जानबूझ कर छिपाने का प्रयास किया गया है** जो निम्न है ।
- प्रतिवादी 03,04 एवं 06 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कार्य किए खनन कार्य 2016 में चालू कर दिया गया और वर्ष 2023 में प्रतिवादी 04 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना के लिए CAMPA खाते में 135.67 करोड़ रुपए जमा किया है।
- इससे संबंधित तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी,पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 21/12/2023 को एक पत्र लिखा गया था,जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण के बारे में यह लिखा गया है कि,

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0): वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज-11 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।

(अनुलग्नक 4)

22 D. प्रतिवादी 04 electrification and signalling work is बताकर संशोधन किया और पूरे रास्ते कर रहा कोयला ट्रांसपोर्टेशन : - यह कि प्रतिवादी 04 ने हलफनामा के कंडिका G यह कहा है कि उनके पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 02.01.2025 के अधिसूचना के आलोक में सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों से कोयला परिवहन किया रहा है। लेकिन उन्होंने इस तथ्य को छिपा दिया कि उक्त संशोधन में उनके द्वारा यह कारण बताते हुए संशोधन लिया गया कि.

- 4. The construction of siding se being done by railways,
- consists of seven nos. of rail tracks out of which 3 are ready, also, the electrification and signalling work is under progress. It is likely that yard augmentation work
- by railways shall be completed by 31.01.2025. After yard augmentation and RLS completion, it shall require three months of time (till 31.03.2025) to synchronize
- the system with railways which is knowns as "Integrated commissioning". In other words, it may take three months for both RLS streams to reach its rated capacity of 15 MT.

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- प्रतिवादी 04 द्वारा जो कारण बताया गया है उसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को जहां तक उसका निर्माण कार्य अधूरा है,वहां तक ही सड़क मार्ग से कोयला करना चाहिए था।
- परंतु उसके द्वारा खनन स्थल से लेकर सड़क साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन किया जा रहा है। जो उक्त शर्त संशोधन का दुरुपयोग है और माननीय न्यायाधिकरण को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया जा रहा है ।
- जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के शर्त संख्या Specific Condition No.- 2A (ix) एवं वन मंजूरी (FC) के शर्त संख्या 9 में कन्वेयर सिस्टम से ही कोयला परिवहन करने का शर्त है। इसमें लोडिंग क्षमता,खनन क्षमता बढ़ाने,उत्पादन क्षमता बढ़ाने या किसी अन्य कारणों के आधार पर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का कोई आधार नहीं दिया गया है।

22 E. प्रतिवादी 04 के द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान ग्रामीणों की मौत पर माननीय न्यायाधिकरण को झूठा हलफनामा दायर किया-

- यह कि प्रतिवादी संख्या 04 के द्वारा अपने हलफनामा के कंडिका L में इस बात का झूठा दावा किया है कि एनटीपीसी के द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान दुर्घटना में किसी की मौत रो सीधा इनकार किया है ।
- जबकि आवेदक के द्वारा OA (EZ) 107/2025 के मूल आवेदन के ANNEXURE 2 के कंडिका 9 में संलग्न राष्ट्रीय दैनिक अखबार "दैनिक भास्कर" के दिनांक 02.12.2022 में छपी खबर जिसमें खबर की शुरुआत में ही त्रिवेणी सैनिक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो एनटीपीसी के एमडीओ है। के हाइवा के चपेट में आने से परियांजना क्षेत्र के चेपाकला निवासी सुनील भुइया की मौत एवं दिनांक 02.11.2022 के खबर जिसमें सड़क दुर्घटना में मौत पर एनटीपीसी कि सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक द्वारा मृतक के परिजन को नौकरी एवं 6 लाख का मुआवजा देने का उल्लेख किया गया है।
- इस विषय में भी प्रतिवादी 04 द्वारा हलफनामा में झूठा हलफनामा प्रस्तुत कर माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया गया है ।
- एक अन्य घटनाक्रम में दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 09.02.2023 को छपी खबर में "कोयला चुनने गई महिला का ओबी में दबकर मौत" शीर्षक से छपी खबर की पुष्टि करता है कि प्रतिवादी 04 के कारण महिला की मौत हुई थी।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 39/2010 GOVT. OF JHARKHAND INDIA

(अनुलग्नक 5)

22 F. प्रतिवादी 04 द्वारा बिना आधार,सत्यता एवं MOEF- Cc के निर्देशों, गलत तथ्यों को बताते हुए माननीय न्यायाधिकरण में पक्ष रखकर गुमराह किया गया एवं साक्ष्य को छुपाया का प्रयास किया गया है -

- यह कि प्रतिवादी 04 द्वारा अपने हलफनामा के कंडिका F से J में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का बिना अधिकृत दस्तावेजों का स्वयं के अवधारणा से परिकल्पित तथ्यों का जिक्र कर हलफनामा दायर किया गया है। जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है।
- एक तरफ प्रतिवादी 04 द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं MOEF - Cc से कन्वेयर सिस्टम,रेलवे ट्रैक आदि विधि व्यस्था का झूठा हवाला देकर शर्तो में संशोधन लिया जाता रहा है। वही माननीय न्यायाधिकरण में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का बिना कोई विभागीय दस्तावेज के स्वयं के परिकल्पित अवधारणा से प्रेरित दे रहा है। जिससे उनकी नियति परिलक्षित होती है।
- किसी भी कोयला खनन परियोजना को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन का मानक,नियमावली और उसका आकलन निर्धारण MOEF &Cc के तकनीकी दक्ष अधिकारियों के निरीक्षण और अनुसंशा पर केंद्रीय बोर्ड बैठक में तय किया जाता है,लेकिन प्रतिवादी 04 स्वयं से मनगढ़ंत तर्क पेश कर माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है ।
- **प्रयोक्ता अभिकरण को बीस साल के लिए FC स्वीकृति और EC शर्त में मिले स्वीकृति में 14 साल तक शर्तो को पूरा नहीं किया एवं खुद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का कार्य,कभी अधूरा कन्वेयर सिस्टम,तो कभी कन्वेयर पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होने,तो कभी रेलवे ट्रैक नहीं बनने एवं विधि व्यस्था, भूमि अधिग्रहण आदि नहीं**

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 998/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

होने का हवाला देकर निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु वन विभाग से मिलकर शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

- जबकि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का पर्यावरणीय स्वीकृति या वन मंजूरी के शर्तों में करने का आदेश कहीं भी किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया गया है । इसलिए उनका उक्त तर्क निजी लाभ की पूर्ति के लिए माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह और न्याय को प्रभावित करने लिए अनाधिकृत, अव्यवहारिक और गैरजिम्मेदाराना तर्क देना प्रतीत होता है।

22 G. प्रतिवादी 03 एवं 06 ने FC शर्त संख्या 9 एवं EC के शर्त 5 वर्णित तथ्य को छुपाते हुए अधूरा और भ्रामक तथ्य माननीय न्यायाधिकरण में दिया. जिसकी विवरण निम्न है।

- यह कि प्रतिवादी 03 एवं प्रतिवादी 06 की तरफ से माननीय न्यायाधिकरण में हलफनामा दायर करने वाले श्री मौन प्रकाश ने अपने हलफनामा के कंडिका 9 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के कांडिका 6 में उल्लेखित "The approval under the forest Conservation Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986." का जिक्र किया है।
- उनके द्वारा लिखा गया उक्त बिंदु FC शर्त 9 में लागू होगा या नहीं वह स्पष्ट नहीं किया गया हैं और किस संदर्भ में लिखा गया है,वह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। क्योंकि FC शर्तें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन लागू होती है और EC, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन लागू होता है। दोनों के मानक और पैमाना अलग - अलग होता है। चूंकि उक्त शर्त वन्य जीवों के सुगम आवागमन एवं संरक्षण हेतु लगाया गया था तो उस स्थिति में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी उल्लंघन लागू होता है।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- प्रतिवादी 03 एवं 06 के तरफ से श्री मौन प्रकाश द्वारा माननीय न्यायाधिकरण में दायर हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में सड़क में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का बचाव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में 10 वीं संशोधन को लेकर किया है।
- **विशेष रूप से यह भी उल्लेख करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के कंडिका 5 में वर्णित तथ्यों को माननीय न्यायाधिकरण में श्री मौन प्रकाश द्वारा जानबूझकर छुपा लिया गया है । जो वर्णित है।**
  - The above conditions shall be governed by, among others, the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
  - उसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि उक्त शर्त में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लगाए गए शर्तों पर प्रभावी नहीं है और उसपर लागू नहीं होता है । जब EC के कंडिका 5 में स्पष्ट किया गया है कि उसका शर्त किस कानून में लागू होगा जो यह स्वतः स्पष्ट करता है कि प्रतिवादियों द्वारा गलत तरीकें से उक्त कंडिका को छुपाया गया है । EC शर्त का व्याख्या और उसका दुरूपयोग किया जा रहा हैं (कंडिका 15,अनुलग्नक 2AB में वर्णित)

पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत संचालित प्रतिवादी 04 एनटीपीसी के सहित अन्य कोल परियोजनाओं को निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन किए बिना खनन

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

कार्य हेतु खोल दिया गया जिसके कारण वन्य जीवों,मानव जीवन, कृषि एवं प्रास्थितिकी का भारी नुकसान हुआ

23.यह कि हजारीबाग वन परिक्षेत्र अंतर्गत शेड्यूल एक के वन्य जीव जो अति संरक्षित श्रेणी (लुप्त प्राय श्रेणी) में आते हैं, शेड्यूल दो जो संरक्षित श्रेणी में आते हैं एवं शेड्यूल तीन एवं चार कैटगरी के वन्य जीवों का घनत्व है और उक्त क्षेत्र में बिना वन्य जीव प्रबंधन के कार्य के प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा खनन कार्य चालू करवाने से हुए नुकसान एवं आपत्तियों के मद्देनजर एक विवरण और तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी के रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।जो निम्न है।

23.A .यह कि सूचनाधिकार अधिकार के माध्यम से दिनांक 13.03.2020 के कंडिका 3 में यह बताया गया कि "पिछले दस वर्षो में जंगली जानवरों द्वारा जान माल की क्षति होने से संबंधित अब तक 1422 मामले में प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया गया है" ।

- जिससे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन के चलते प्रभाव की पुष्टि एवं निजी लाभ के प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कार्य नहीं होने के बाद हुए नुकसान की पुष्टि करता है और वन्य जीवों के प्रास्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण को पुष्टि करता है ।

(अनुलग्नक 6)

23.B. यह की वन प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक 5813 दिनांक 11.10.2023 के एक रिपोर्ट में वर्ष 2019 से 2024 तक पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत जंगली हाथियों द्वारा मृत एवं घायल व्यक्तियों से संबंधित मुआवजा राशि का विवरण दिया गया है।

- जिसमें कुल 32 मृत लोगों के लिए 10000000.00 एवं °7 घायलों के लिए 530000.00 कुल 10530000.00 रुपया दिया गया ।
- वहीं वर्ष 2019 से 2024 तक जंगली हाथियों द्वारा फसल भंडारी अनाज मकान एवं पशु क्षति से संबंधित मुआवजा राशि का विवरण दिया गया है । फसल छति के कुल 1560 मामले जिसमें 228.8 हेक्टेयर भूमि पर 557120 क्विंटल का 4340772.00 राशि का भुगतान किया गया ।

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
208/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- भंडारित अनाज के 290 मामले में 618.44 क्विंटल के लिए 98950.00 रुपए एवं मकान क्षति के कुल 576 मामले में कुल 10110000.00 रुपए तथा पशु क्षति के कुल 23 मामले 18000 क्विंटल के लिए 314000.00 रुपए का आंकड़ा दिया गया है।
- जिससे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन के चलते प्रभाव की पुष्टि एवं निजी लाभ के लिए प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कार्य नहीं होने के बाद सरकारी राजस्व, मानव जन जीवन,कृषि एवं वन्य जीवों के हुए नुकसान की पुष्टि करता है और वन्य जीवों की प्रास्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण की भी पुष्टि करता है।

(अनुलग्नक 7)

24.यह कि हजारीबाग वन परिक्षेत्र अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी की तीन कोल ब्लॉक परियोजना क्रमशः पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना,चट्टी बरियातू कोल परियोजना एवं केरेडारी कोल ब्लॉक परियोजना सहित सीसीएल सहित अन्य कंपनियों के कोल ब्लॉक संचालित है। जिन्हें वर्ष 2009 से लेकर 2013 के बीच वन अनापत्ति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। परंतु वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। जिसमें प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता एनटीपीसी द्वारा वन संरक्षण पर स्पष्ट उल्लेख है।

- यह की वन्य जीव प्रबंधन योजना के संबंध में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी,पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 21/12/2023 को लिखे एक पत्र में वैसी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू कर लिया गया है । जिसकी विवरणी निम्नवत् है ।
- मेसर्स एन०एम०डी०सी० लिमिटेड (पूर्व आवंटी मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड के टोकीसूद नार्थ सब ब्लॉक) 374.87 हे0 :- वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.2011 द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3145 दिनांक 09.07.2014 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि को विमुक्त किया जा चुका है। जबकि

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

स्टेज-1 के शर्त संख्या-09 एवं स्टेज-1 के शर्त संख्या-14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को Conservation Plan का कार्यान्वयन करना था जो अभी तक नहीं हुआ है। जिसका विवरण नीचे की कंडिका में वर्णित है।

- एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0): वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज-11 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति पधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।
- चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत मगध ओ०सी०पी० परियोजना (96.72 हे0) :- इस परियोजना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2010 से अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है तथा राज्य सरकार के पत्रांक 3276 दिनांक 22.06.2015 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि विमुक्त की गई है।
- इस परियोजना के शर्त संख्या-18 "The user agency to bear the cost of implementation of conservation plan to be prepared in consultation with the CWLW of the State for the Hazaribagh National Park and its buffer zone adjoining CCL mining zone." में उल्लेखित है।
- उक्त शर्त का अनुपालन खनन कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद लंबित था। जब सी०सी०एल० द्वारा मगध ओ०सी०पी० के नयी परियोजना 192.36 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई जिसमें तीन बिन्दु मगध ओ०सी०पी० 96.72 हे0 के WLMP से संबंधित था।
- तब जाकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर समर्पित की गई जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या 39, ज्ञापांक 1473 दिनांक 29.11.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि खनन कार्य 2016 से ही जारी है।

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

- उपरोक्त रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि अनुभव के आधार पर यह Site Inspection Report में उल्लेख किया गया है। क्योंकि Mining Start हो जाने में वन्यप्राणियों पर दुष्प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है एवं Soil Erosion भी होने लगता है। विलम्ब से Wildlife Plan/CAT Plan के लागू होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी के मद्देनजर यह मंतव्य दिया गया है कि Mining के साथ Wildlife Plan/CAT Plan का कार्य भी प्रारम्भ करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

(अनुलग्नक 8)

प्रतिवादी संख्या 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा FOREST CLEARANCE और ENVIRONMENT CLEARANCE के शर्तों को 20 वर्षों के लिए मिले खनन पट्टा में 14 वर्षों तक निजी लाभ के लिए विभिन्न भ्रामक कारणों को बताकर पूरा नहीं करना एवं उसका निर्ममता से उल्लंघन करना

25. यह कि प्रतिवादी 04 एनटीपीसी द्वारा FOREST CLEARANCE (FC) वर्ष 2010 जो और ENVIRONMENT CLEARANCE EC) वर्ष 2009 में मिल चुका था। परंतु अब तक लगभग 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा निजी लाभ के पूर्ति के लिए विभिन्न भ्रामक कारणों का बहाना बनाकर शर्तों का पालन नहीं किया गया और उसका निर्ममता से उल्लंघन किया जा रहा है । जो क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,हजारीबाग के पत्रांक 1210 दिनांक 23.06.2025 को वन प्रमंडल पदाधिकारी,हजारीबाग को लिखा गया पत्र से होता है । जिसका विवरण इस प्रकार है ।

- यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2 के शर्त संख्या 2.b के संदर्भ में 3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अबतक safety zone क्षेत्र का पूर्ण घेरान नहीं किया गया है बल्कि मात्र 6000 मी॰ एक घेरान barbed wire से एक स्तरीय किया गया है। इसमें safety zone का द्विस्तरीय fencing किया जाना चाहिए।

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

safety zone का द्विस्तरीय fencing नहीं होने के कारण इसका regeneration भी नहीं हो पा रहा है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लगभग 37000 पौधे safety zone में लगाने की बात कही गई परन्तु उनके फोटोग्राफस से regeneration की स्थिति दयनीय प्रतीत होता है। प्रयोक्ता अभिकरण को संपूर्ण safety zone क्षेत्र में द्विस्तरीय Fencing Chain Link fence से करवाकर इस बरसात में इस क्षेत्र में गहन वृक्षारोपण हेतु निदेश दिया गया था। परन्तु इस संबंध में कोई अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अबतक नहीं भेजा गया। प्रस्तुत द्वारा परियोजना लागत से सुरक्षा क्षेत्र की बाड़बंदी, सुरक्षा और पुनर्जनन का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना लागत से ही, अन्यत्र चयनित की जाने वाली क्षतिग्रस्त वन भूमि पर, सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल के डेढ़ गुना क्षेत्रफल पर वनरोपण भी किया जाएगा। 2.बी. अतः आप स्वयं अथवा सहायक वन संरक्षक के माध्यम से इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर इस शर्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था।

- यह कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2 के शर्त 8.i के संबंध जिसमें पकवा एवं खुर्रा नाला के किनारे 50 मीटर ग्रीन बेल्ट बनाने का शर्त दिया गया था। उसके संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा इसके अनुपालन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि इसका अनुपालन लंबित है। उन्हें पकवा एवं खोर्स नाला के दोनो ओर 50 मी ग्रीन बेल्ट बनाने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिया जा चुका है।
- यह कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2 के शर्त 19 के आलोक में प्रयोक्त्ता अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई पूराने तालाबो का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबो के निमार्ण की बात कही गई परन्तु उनके द्वारा कोई सूची प्रस्तुत नहीं किया गया। Disiltation किये गये तालाबो की सूची उनसे माँगा गया था जो अबतक अप्राप्त है। आप प्रयोक्ता अभिकरण से पूरी सूची प्राप्त कर उसका अपने स्तर से जाँचोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने को लिखा गया है ।

सत्य प्रतिलिपि

(अनुलग्नक 9)

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 396/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

26. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 एनटीपीसी को ENVIRONMENT CLEARANCE(EC) वर्ष 2009 में स्वीकृति मिलने के बाद अब तक कई महत्वपूर्ण शर्तो को पूरा नहीं किया गया है। जो सार्वजनिक जनहित,वन्य जीव हित,सुरक्षा और जनकल्याण से संबंधित है,इसके बावजूद प्रतिवादी 04 द्वारा निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु विभिन्न भ्रामक कारणों का हवाला देकर उन शर्तो को लगभग 14 वर्ष के बाद भी पूरा नहीं किया गया है ।जिसको लेकर MOEF &CC के compliance & monitoring division -I.A Division के साइंटिस्ट "ई "श्री मुन्ना कुमार शाह में दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को प्रतिवादी 04 को पत्र लिखा जिसमें प्रमुख बिंदु निम्न है।

"3. The monitoring report submitted for the project by RO, Ranchi has been examined in the Ministry and following are observed non-compliances with respect to said EC letter on the basis of review of IRO's report:

- i. Violation/non-compliance of the provision of Forest Clearance Act. (Specific Condition: II)
- ii. Necessary fund for construction of road upto the Monolith and park around to the state Govt. yet has not been released. (Specific Condition: III)
- Siltation ponds, gabions have not been constructed in South West direction, Siltation pond has not been properly maintained, grassing, vegetation, plantations has not been developed near Lathorwa nallah, gabions has not been developed in between slope and nallah, no embankment between dump D of eastern quarry and pakka nallah has been constructed (Specific Condition: IV)
- iv. Catch drains and siltation ponds have not been constructed for other portion of top soil dump. (Specific Condition: V)
- v. Grassing and vegetation on the slopes of the OB dump has not been developed properly also, the slope of the section has not been submitted. (Specific Condition: VI)

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 3/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

मंटू सोनी अधिवक्ता

- vi. Catch drains and siltation ponds at many places as specified by IRO has not been constructed and maintained. (Specific Condition: VII)
- vii. Retaining wall at the toe of the OB dump has not constructed at many places as specified by IRO. (Specific Condition: VIII)
- viii. 3-tier avenue plantation has not been developed as per the EC condition. Transportation of Coal has is not being done as per the EC conditions dust emission has not been controlled effectively (Specific Condition: IX)
- ix. Inadequate Dust control system to control the dust emission. (Specific Condition: XII)
- X. Development of Rainwater harvesting structure wherever feasible. (Specific condition: XIII)
- xi. Maintenance of Oil & grease trap and operational status of STP. (Specific Condition: XV) (General condition; VII)
- xii. Completion of Plantations in some portions (as specified by IRO) of OB dumps (Specific Condition: XVI)
- xiii. Status and completion of R&R Plan (Specific Condition: XIX)
- xiv. Implementation of the report of Department of Forestry, wildlife & Environmental Sciences, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh (Specific Condition: XXI)
- Date till which eastern quarry of the project was operational. (General Condition: 1) xv.
- Nstallation of CAAQMS near Mining operations area in consultation with JSPCB officials. (General condition: III) xvi.
- xvii. Fugitive dust emission from all sources has not been controlled properly. Water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, and dump truck has not been adequately maintained. (General Condition: IV)

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 198/2010 GOVT. OF JHARKHAND

Scanned by Scanner Go

- xviii. Submit the details of proper collection and treatment of Industrial wastewater. (General Condition: VII)
- xix. Details of whether funds earmarked for environmental protection measures have been kept in separate accounts. (General Condition: XII)

"4. In view of the foregoing, the Project proponent (PP) is hereby directed to submit the clarification/Action Taken Report (ATR) for observed non-compliance within the next 30 days from the date of issuance of this letter. It may be noted that, if no satisfactory reply is received within the prescribed time frame, the Ministry will be constrained to take necessary action as deemed fit and appropriate in the circumstances of the case which inter-alia include issuance of Show-Cause Notice under the provision of section (5) of the Environment (Protection) Act, 1986.

(अनुलग्नक 10)

27. यह कि प्रतिवादी 04 ने अपने हलफनामा में आवेदक पर जितने भी आरोपों/मुकदमों को जिक्र किया है,वह अधूरा,भ्रामक और जान बूझकर तोड़ मरोड़ के बिना ठोस साक्ष्य के वर्तमान स्टेटस के जानकारी के अभाव में दुर्भावना से ग्रसित होकर लिखा है। क्योंकि उनमें से सभी मुकदमें झारखंड के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।जिसमें से कुछ मुकदमें फर्जी साबित हुए,कुछ में रिहा हुआ हूं । यहां यह उल्लेखित करना है कि प्रतिवादी 04 ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर मेरे सहित अन्य प्रभावितों को फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर फंसाने का कार्य किया जाता रहा है, ताकि वह परियोजना क्षेत्र अंतर्गत हो रहे अनियमितता को दबाने,कुचलने में सफल रहे और निजी स्वार्थ की पूर्ति करता रहे ।प्रतिवादी 03 एवं प्रतिवादी 04 के मिलीभगत और निजी लाभ को अपराध अनुसंधान विभाग के रिपोर्ट के उक्त तथ्यों से समझा जा सकता है।

- यह विशेष उल्लेखनीय है कि मेरे द्वारा प्रतिवादी 04 के अवैध कार्यों की शिकायत किए जाने के बाद प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 के अधीन खनन कार्य कर रहे कंपनी त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के

NOTARY R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND INDIA

अधिकारी ने प्रलोभन देकर आवेदक(मुझे) मैनेज करने का प्रयास किया गया था।

- जिसकी पुष्टि मेरे शिकायत पर प्रतिवादी 03.प्रतिवादी 04 के विरुद्ध शिकायत पर अपराध अनुसंधा विभाग ,रांची ने झारखंड सरकार को कार्रवाई हेतु भेजे गए अपने जांच प्रतिवेदन में किया है ।
- अपराध अनुसंधान विभाग ने झारखंड सरकार को कार्रवाई के लिए भेजे अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवादी 03 एवं प्रतिवादी 04 के मिलीभगत से परियोजना अंतर्गत 20 से 30 मीटर औसत चौड़ी दुमुहानी नाला को खनन पट्टा के FC शर्तो के विपरीत उल्लंघन करते हुए अवैध खनन कर उसकी चौड़ाई महज चार से पांच मीटर कर दिया गया और उसके प्रवाह को अभी तक बाधित कर रखा गया है। और उसके बचाव के लिए निजी लाभ प्राप्त कर आपसी सांठगांठ कर प्रतिवादी 03 द्वारा फर्जी रिपोर्ट बनाए जाने की पुष्टि झारखंड सरकार को कार्रवाई के लिए अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भेजे गए रिपोर्ट में किया गया है ।
- अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच रिपोर्ट में प्रतिवादी 04 को बचाने के लिए प्रतिवादी 03 ने अपने पहले रिपोर्ट को बदलकर दूसरी रिपोर्ट दिया था।
- अपराध अनुसन्धान विभाग के रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि किया गया था कि प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 को संरक्षण देने के लिए झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के शर्तो के बिंदुओं को भी छिपाकर गलत व्याख्या करते हुए रिपोर्ट बनाया था।

(अनुलग्नक 11)

28. यह कि प्रतिवादी 04 एनटीपीसी स्वयं को भारत सरकार की कंपनी कहती है और देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए कोयला का रिकॉर्ड उत्पादन करने के लिए स्वयं को नंबर एक कंपनी बताती है। वहीं उपरोक्त तथ्यों,सबूतों और साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि एनटीपीसी भारत सरकार के MOEF&Cc के तहत अनिवार्य शर्तो जो कि मानव कल्याण,वन्य प्राणी कल्याण एवं प्रास्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखकर लगाया गया था,को हरेक स्तर पर अलग-अलग असत्य तथ्यों का सहरा लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित माननीय न्यायाधिकरण एवं अन्य संस्थाओं को भी गुमराह करने का कार्य अपनी निजी स्वार्थ के लिए स्थानीय

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regn. No. 032/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

जिला प्रशासन एवं वन विभाग से मिलकर सतत रूप में किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त दिए गए विवरणों से स्दतः स्पष्ट है।

29.माननीय न्यायाधिकरण की अनुमति से क्षेत्र में प्रतिवादी 04 के वर्तमान सहित अन्य कोयला परियोजनाओं में हो रही अनियमितताओं,फर्जी दस्तावेजों का निर्माण कर MOEF &Cc से अनापति प्रमाण पत्र लेने एवं वनाधिकार अधिनियम के लिए फर्जी दस्तावेज को प्रस्तुत कर प्रतिवादी 03 ने माननीय न्यायाधिकरण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर आदेश लेकर उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया गया है। वो,न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध एवं नैसर्गिग न्याय के खिलाफ है। इससे सम्बंधित माननीय न्यायाधिकरण के आदेशानुसार अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूंगा।

30.यह कि उपरोक्त सभी वर्णित विवरण साक्ष्य मेरी जानकारी में सत्य एवं प्रामाणिक हैं । जिसे मैं माननीय न्यायाधिकरण में पूरी जिम्मेवारी से सम्मानजनक एवं न्याय के भाव से प्रस्तुत कर रहा हूं।

31.यह प्रति उत्तर शपथ पत्र सद्भावना पूर्ण और न्याय के हित एवं लोक हित में प्रस्तुत किया जा रहा है आपसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रति शपथ पत्र में अनजाने में थोड़ी विधिसम्मत त्रुटि/भूल चुक हो गई हो, तो उसे मानव कल्याण,वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी कल्याण के दिशा में किया गया प्रयास समझ कर क्षमा कर स्वीकार करने की कृपा करें ।

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No. 398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

आवेदक

मंटू सोनी उर्फ शनिकांत
15/09/2025

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत
पिता श्री राजेश कुमार
बड़कागांव, जिला-हजारीबाग(झारखंड)
पिन कोड - 825311
मो० 9504268699
Email- shanikant699@gmail.com

Identified the deponent who has signed/put L.T.I. in my presence

Pawan Kr. Yadav
Adv
15/09/25
ADVOCATE

Solemnly affirmed/declared on oath before me by Sri.....Mantu Soni @ Shanikant.....
Who has been identified by Shri.......
.....Pawan Kumar Yadav.....Advocate
who is personally know to me.

NOTARY
15/9/25

भारत सरकार
Government of India

शनि कान्त
Shani Kant
जन्म तिथि / DOB : 05/06/1985
पुरुष / Male

3510 2988 3792

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
आत्मज: राजेश कुमार, 645, रेंज ऑफिस के पास, बड़कागाओं, हजारीबाग, बड़कागांव, झारखण्ड, 825311

Address:
S/O: Rajesh Kumar, 645, near range office, Barkagaon, Hazaribagh, Barkagaon, Jharkhand, 825311

3510 2988 3792

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मन्टु सोनी उर्फ शनि कान्त

NOTARY
B. R. PRASAD
HAZARIBAG
Regd. No.
398/2010
GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

267

Affidavit

अधिवक्ता कल्याण कोष
पन्द्रह रुपये ₹15 झारखंड
FIFTEEN RUPEES JHARKHAND
ADVOCATE WELFARE FUND

अधिवक्ता कल्याण कोष
पन्द्रह रुपये ₹15 झारखंड
FIFTEEN RUPEES JHARKHAND
ADVOCATE WELFARE FUND

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

Binod Ranjan Prasad
NOTARY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

HAZARIBAG BAR ASSOCIATION • HAZARIBAG •

सत्यमेव जयते

NOTARY B. R. PRASAD HAZARIBAG Regd. No. 398/2010 GOVT. OF JHARKHAND (INDIA)

22574
15/9/20

Joint Secretary
Library
Bar Association, Hazaribag

(Suman Kumar Singh)
General Secretary

Sl. No. C 1307

Signature of Executive Member

Scanned by Scanner

(अनुलग्नक 01)

5

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० द्वारादिनांक–28.02.2023 कोपूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–वन–10 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत एन०टी०पी०सी० के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए Forest Clearance भारत सरकार द्वारा हाथियों के आवागमन को बाधित नही होने के लिए बानादाग रेलवे साइडिंग तथा कोयला ढुलाई के लिए कन्वेयर बेल्ट इस्तेमाल करने का शर्त दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि Forest Clearance के शर्तों का उल्लंघन कर कन्वेयर बेल्ट बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई के लिए वन विभाग एन०टी०पी०सी० को Transit Permit अभी तक जारी करते आ रही है;	मुख्य महाप्रबंधक, पकरी बरवाडीह एन०टी०पी०सी० लिमिटेड ने अपने पत्रांक–23 दिनांक–10.02.2023 से सूचित किया है कि विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि–व्यवस्था के चलते अभी तक कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है फलस्वरूप उनके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक–27/29.10.2020 के प्रावधान के आलोक में तत्काल सड़क मार्गों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में Transit Permit निर्गत किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि सड़क मार्ग से अवैध कोयला ढुलाई के दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है और त्रिवेणी सैनिक कंपनी ने उक्त दोनों के परिजनों को मुआवजा भी दिया है;	इस संबंध में उपायुक्त, हजारीबाग से सूचना की मांग की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, हजारीबाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त, नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० तारांकित प्रश्न–21/2023–743 व०प०, दिनांक–27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–198, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(अनुलग्नक 01 A)

F.No. J-13012/91/2008-IA.II (T)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

3rd Floor, Vayu Block,
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road,
Aliganj, New Delhi-110003

Dated: 27.10.2020
29

Office Memorandum

Sub: Clarification regarding coal transportation by Thermal Power Plants in line with Ministry's Gazette Notification vide S.O. 1561(E) dated 21.05.2020- reg.

The Ministry vide Gazette Notification S.O. 1561(E) dated 21.5.2020 has prescribed certain conditions on coal transportation.

2. The Ministry has been receiving several representations from various power plant operators to issue a clarification on coal transportation in light of the said Notification dated 21.05.2020.

3. It is reiterated that the Ministry's Notification dated 21.5.2020 aims at achieving coal transportation by railway wagons and/or belt conveyors from delivery point of coal mine to thermal power plant and it is the responsibility of power plant operators to set up such infrastructure pertaining to rail or conveyor belt system. Therefore, the condition in the Environmental Clearance, as regards setting up rail infrastructure or conveyor belt system shall remain operative. However, till such time infrastructure regarding rail/conveyor system is not established, coal may be transported by road **with tarpaulin covered trucks.**

4. The said Notification also clarifies that the existing conditions in the Environmental Clearance stand modified so as to make the above conditions operative. Therefore, the project proponents need not approach the Ministry to seek temporary permissions for road transportations subject to transportation through tarpaulin covered trucks.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Dr. S. Kerketta)
Director

To

1. *All Power Plant Operators who were granted Environmental Clearance*
2. *All Chairmen and Members of SPCBs/UTPCCs/CECB/EACs/SEACs/SEIAAs.*

Copy to:

1. Sr.PPS to Secretary
2. Sr. PPS to AS (RA) & AS (RSP)
3. Sr. PPS to JS (GM) & JS (SKB)
4. Guard file/Website of MoEF&CC

Director, IA.I

(अनुलग्नक 01 B)

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222330, Email- dfohazaribaghwest@gmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक: 3543 दिनांक: 02/11/2022

सेवा में,

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत,
ग्राम – गोन्दे + थाना– बड़कागांव,
जिला हजारीबाग
मो0 नं0 9504269699

विषय:– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका आवेदन दिनांक 07-10-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा मांगी सूचना की जानकारी निम्नवत है :–

01	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साईडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है? हां या नहीं ?	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साईडिंग तक कन्वेयर बेल्ट/ ट्रकों से परिवहन हेतु वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है।
02	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है? हां या नहीं?	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साईडिंग तक कन्वेयर बेल्ट/ ट्रकों से परिवहन हेतु वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है।
03	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग रेलवे साईडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का परिवहन/वन विभाग का विभागीय आदेश निर्गत है तो उसके शर्तों के साथ विभागीय आदेश कॉपी का विवरणी उपलब्ध कराया जाए।	एन0टी0पी0सी0 के पकरीबरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साईडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/ नहीं करने संबंधी कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(अनुलग्नक 01 C)

265

804570/2022/RO-ECZ

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office
पताः द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

निसिल सं0 FP/JH/min/38798/2019/717 दिनांक 25.11.2022

सेवा में,

श्री चरणजीत सिंह,
वैज्ञानिक 'डी' (FC Division)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः पकरी–बरवाडीह कोल माईन नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट, मेसर्स नेशल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड जिला हजारीबाग स्थित का स्थल निरीक्षण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा किए जाने के संबंध में।

सन्दर्भः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8–56/2009–एफ.सी-(vol) दिनांक 07/07/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् के संदर्भित पत्र के आलोक में परियोजना से संबंधित वांछित स्थल निरीक्षण किया जाकर तैयार प्रतिवेदन को मार्गदर्शिका के पारा 1–21-(III) के आलोक में विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत क्षेत्रीय सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करा उनकी संस्तुति के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथा उक्त

भवदीय

25/11/22

(शशि शंकर)
सहायक वन महानिरीक्षक
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

804570/2022/RO-ECZ

Site Inspection Report for Pakri-Barwadih Coal Block of M/s NTPC.

An application for diversion of 331.198 Ha of Forest land in Barkagaon Range of Hazaribagh West Forest Division is under consideration as proposal no. FP/JH/Min/38798/2019. This proposal is for coal-mining by M/s NTPC within its lease area of 4695 Ha. A Forest area of 1026.438 Ha within the lease has already been diverted (Proposal No. FP/JH/Min/693/2009; Stage-II vide letter dated 17/9/2010) and mining is happening there since 2016.

The extant case is proposed North-West extension of the existing quarry.

According to the FC Rules, the Integrated Regional Office, Ranchi was requested by ministry to vide its letters dated 23/2/2022 & 7/7/2022 to inspect the lease area, proposed diversion area & CA area involved in the proposal. Ministry also asked IRO Ranchi to assess the status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 17/9/2010, granted towards the area of 1026.438 Ha in light of para 1.21 (iii) of the FCA Handbook.

Accordingly, the team of IRO Ranchi, comprising its AIG, visited the site on 28/10/2022.

During the site inspection among others following representatives of state Forest Department and project proponents were present along with the visiting team: -

1. Shri R.N. Mishra, DFO Hazaribagh West
2. Shri Shailendra Kumar, IFS, Hazaribagh West
3. Shri Satyam Srivastava, Head of Project, NTPC
4. Shri Birendra Kumar, AGM (Environment), NTPC

The site inspection was preceded by an on-site presentation made by NTPC officials to give on overview of the extant fresh proposal and the status of S-II compliance towards already diverted 1026.438 Ha forest area.

FC Proposal No. FP/JH/Min/38798/2019 for diversion of 331.198 Ha forest area towards Pakri-Barwadih (North-West) Coal Mining Project: -

In this fresh proposal for diversion of 331.198 Ha, the proposed forest-area is located in the North-Western side of the already diverted area (1026.438 Ha; S-II vide letter dated 17/9/2010, as depicted in the following imagery: -

It is seen that the proposed forest area is contiguous to the already diverted area. The area has fairly good vegetative density and undulating terrain. The forest officials present there apprised that occasional movement of elephant herds too is reported in the area.

The proposed area (331.198 ha; FP/JH/Min/38798/2019) is separated from the existing mines (1026.438 Ha area; FP/JH/MIN/693/2009) by a

tributary of the Khora Nala which constitutes the western boundary of the lease area (as depicted below).

The total lease hold of the North-West Project is 485.16 Ha which includes 113.56 Ha of tenancy land, 19.71 Ha of GM Land and 351.189 Ha Forest land which includes 20.692 Ha already diverted forest land 9from 1026.438 Ha) apart from the applied 331.198 Ha forest land.

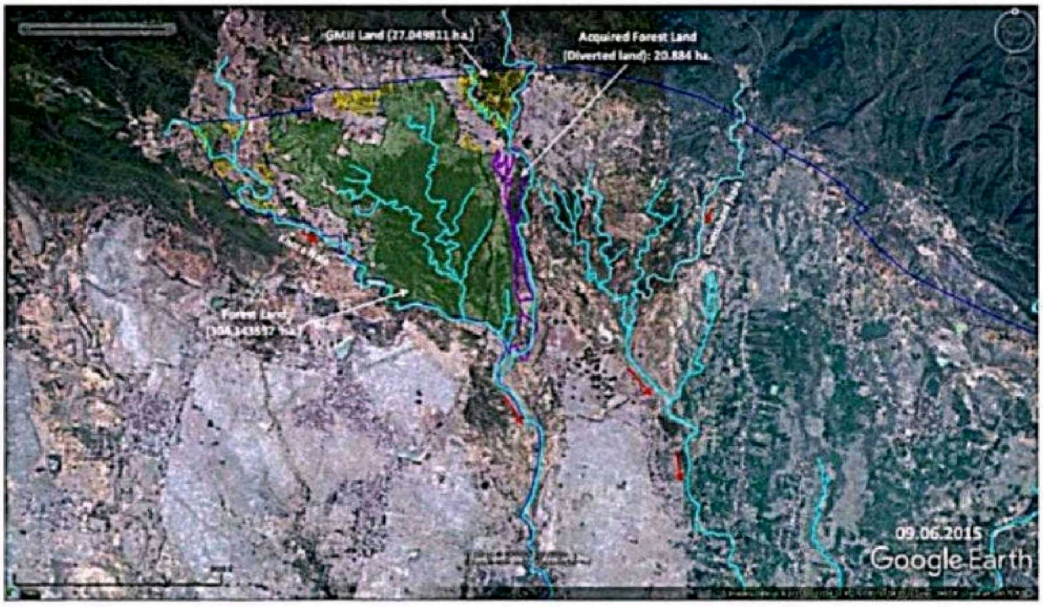

The total coal bearing area is 471.06 Ha which has mineable reserve of 138.96 MT. with a production capacity of 3 MTPA, the total project life is planned for 52 years.

The project proponent has emphasized that the 15 mtr. safety zone at the boundary of proposed and existing area has been incorporated in the mining plan and therefore 33.18 MT of mineral reserve shall be kept as Barrier & Batter. The trapezoid form of the earth below the undisturbed surface accounts for such staggering occluded minable mineral resource – about 30% of total. Upon further enquiry on the matter, the representatives of user agency apprised that this trapped mineral shall be mined in 2[nd] phase of project – some 40 years later.

User agency, in attempt to capitalize the discussion, tried to justify the violation of condition No. 8 imposed in final approval of 1026 Ha area.

The condition No. 8 of the final approval dated 17/09/2010 for 1026.438 Ha (adjacent forest area, to same user agency) demanded, *"User agency will take up programme for at least 50m greenbelt along the sides of the Pakwa Nallah and Dumuhani Nallah from the initial years under the supervision of the State Forest Department."*

The situation of Pakwa Nallah & Dumuhani Nalla (Khora Nalla too) is shown in the imagery below.

User agency tried to explain that since Dumuhani Nalla was running almost through the middle of the project area, leaving 50m belts on both sides of it would have resulted in unviable mining operation as massive reserve would have left unutilized. Therefore, they resorted to mining there too.

The inspecting team of IRO asked the project proponent that if such massive was the implication why appropriate representation in time was not made by user agency considering the fact that conditions under S-II were issued in 2010 whereas actual mining started six years later in 2016.

Situation portray least botheration of user agency towards the compliance of conditions mentioned in final approval of Forest clearance while implementing the project.

Further project proponent apprised that Dumuhani nalla was to be diverted as per the approved mine plan (Chapter 5.2.11) of CWPRS Pune. Even then U/A gave consent to develop greenbelt around it for sake of processing hurried Forest clearances. (Stage-I issued on 11/5/2010, S-II on 17/9/2010).

They also informed that user agency has procured required permission to divert the Nallah from water Resource Department, Govt. of Jharkhand vide letter dated 19.3.2013. State Forest Department officials were asked to clarify whether or not the water Resources department is empowered to accord such permission in forest area or not; the officials responded in negative.

In such a scenario it is evident that user agency's prime concern was revenue generation only with least care towards the compliance of conditions by which the very approval of mining in the area was conveyed.

The drainage system of Dumuhani Nalla prior to mining operation commencement (in 2015) and post mining operation (2019) are shown in the below two satellite imageries.

From the two satellite imagers it is quite clear that the mining operation has destroyed the very region from where the Dumuhani Nalla was rising/originating. Since the source region itself is completely dug out, the nalla course now receivers almost no water in itself.

The following photo shows the amount of water in Nalla at Point 'A' at the time of visit.

Therefore, it becomes hence clear that user agency has not complied with the condition no. 8 of final FC approval.

Further condition No. 9 demands that coal evacuation should be done through high speed conveyor of 20 m width. During site inspection it was found that coal is being transported through conveyor partially, coal was seen being transported by road too. This apparently tantamount to partial violation of condition no. 9.

User agency has done considerable compliance related to soil, moisture and water conservation in the area including other conditions imposed in the final approval of 1026.438Ha.

Site inspection to proposed CA (DFL) area:-

The proposed CA in Degraded Forest Land (DFL) for the extant proposal is proposed over 665.237Ha of Degraded Forest land in Barkatha Forest Range, Hazaribagh (West) Forest Division. During the visit to the proposed CA DFL area, the following officials/representative were present:

- Sh. Shailendra Kumar, IFS, Hazaribagh (West) Forest Division
- Sh. Kamalesh Singh, Range Officer of Barhi/Barkatta.
- Sh. Rajendra Kumar, SBO.
- Sh. Deb Chand Mahto Kumar, SBO.
- Sh. Pavan V. Khandwe, Addl. General Manager (Mining), PB, NTPC Ltd.
- Sh. Birendra Kumar, Addl. General Manager (Envt. Mgmt.) PB, NTPC Ltd.

The CA DFL area is constituted/identified in 7 patches spread across 8 villages. Most of the area was found suitable for raising compensatory afforestation. Few patches were found to have considerable amount of vegetation and the forest officials and the representatives of user agencies were asked to deduct the dense areas from the net workable extents. Considering the huge spatial extent of the patches, it may be difficult to completely replace the patches, hence gross area and net area consideration was asked for incorporation. Absence of existing boundary pillars, kuccha/pakka encroachments and less staff in position were few ubiquitous impediments observed which officials ensured to take care off.

The entire proposed CA (DFL) is situated in 8 villages, the details provided in the following table:

Name	Area in ha.	Observation (During Site Visit)
Patch 1	36.459	-
Patch 2	126.282	-
Patch 3	119.112	-
Patch 4	92.011	Encroachment small (village) has been observed
Patch 5	39.856	-
Patch 6	68.433	-

Patch 7	183.082	Encroachment (small village at Pandanatanr & Brick kiln at Bero) has been observed.

Assessment of Violation in context with para 1.21 of FC Handbook:-

Since the user agency has violated the condition No. 8 of final FC approval for approved 1026.438 Ha forest land in the lease, the para 1.21 (III) is applicable to assess the violation.

Further, as the violation has been done by way of mining in the otherwise greenbelt, the situation of *fait-accompli* has been created and hence now user agency can not comply with the condition anyways.

This fait-accompli situation is the result of user agency's urge to extract more mineral & hence revenue generation.

As per condition no. 8, user agency was supposed to maintain greenbelt of 50 meters width on the both sides of the stream (Nalla). Considering the total length of the Nalla, 12KM (12000 meters) within the lease area, and average width of 30 meters, the user agency was supposed to establish & maintain greenery (and not mining) in 12000X130= 1560000 m^2 or 156 Ha area.

Considering the Angle of Repose (AoR) of a relaxed 45^0, and average depth of mining as 300meters;

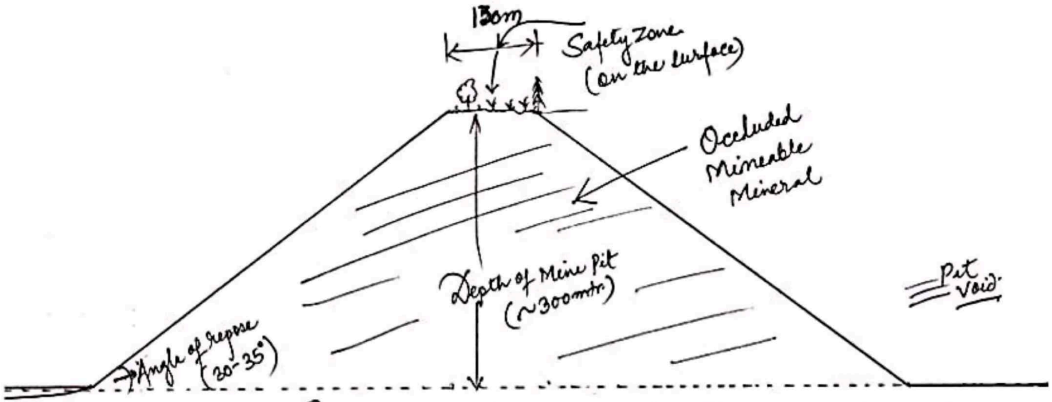

-: Representative diagram showing the cross-sectional view:-

Considering a more relaxed AOR of 45°; and Average stream bed width = 30mtr

Cross-sectional Area = $\frac{130+730}{2} \times 300$

$= 129000\ m^2$

A Total Earth of 129000 m^2 X12000m = 1548 million m^3 would have left undistributed throughout the course of Dumuhani Nalla within the lease (as depicted in the symbolic diagram below).

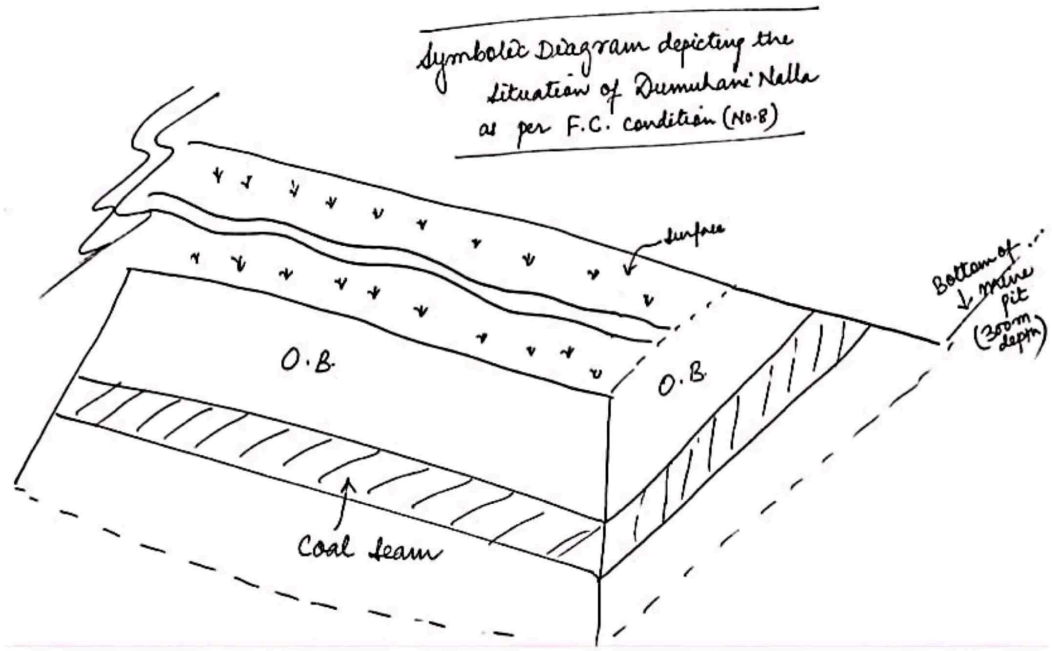

Considering a minimal 10% of total earth as useful mineral, the volume of Coal would be 154.8 million m^3.

Therefore, considering the specific gravity of 1.8 for these coal, the total amount of Coal mined by violating the FC Condition is 278MT.

Hence, for mining this staggering amount of mineral the user agency has violated the condition of FC and the area involved in violation is 156 Ha.

Also, by mining in the otherwise postulated green area, the user agency has saved itself upon the cost of Afforestation too which was expected on the violated land.

Therefore, in assessment of the quantum of violation, the following points are considered (in accordance to the ministry's guideline dated 1/8/2017): -

1. Penal NPV: - 2 times of the Normal NPV as per para 1.21(iii) of the FC Guidelines Handbook.
2. Loss of Eco-system services that the green belt would have provided: - Equal to the NPV.
3. The greenbelt along the Nalla would have served as a good Habitat for avian fauna and other several biodiversity. Therefore, 50% of NPV is accounted for Habitat Destruction as per the guideline dated 1/8/2017.
4. Compensatory afforestation and soil moisture conservation cost that the user agency should have borne as per the laid condition. Since afforestation was to be done in linear patches, considering the increased fencing the rate of Afforestation is considered as Rs 5 Lakh per Ha.

Therefore, the Penalty assessed for the Fait-accompli violation is:

156 X (3.5 times NPV+ Afforestation cost)

=156 X (3.5X1357110+500000) Eco class-III, Density=.8

=Rs 818982060/-.

804570/2022/RO-ECZ

Recommendations of IRO Ranchi:

The extant case was discussed in the REC meeting in light of the violation done by the user agency in the adjacent/contiguous area of the same mining lease.

REC members took serious note of the apathetic attitude of project proponent towards the conditions on which the very Forest Clearance was accorded towards the mining in forests.

Therefore, REC unequivocally recommended that the extant proposal of project proponent in the same lease area should only be considered after the penalty of Rs 818982060/- (Rupees Eighty One Crore Eighty Nine Lakh Eighty Two Thousand and Sixty only) is realized from user agency for violating the FC conditions and creating fait-accompli situation at the site against the guidelines of Hon'ble Supreme Court of India also.

25/11/22

Shashi Shankar

AIGF, IRO Ranchi.

Santosh Tewari

Dy. DGF, IRO Ranchi.

अंतरिम जाँच प्रतिवेदन (अनुलग्नक 01 D)

सेवा में

वन संरक्षक,हज़ारीबाग

विषय- आपका पत्रांक 1892 दिनांक 29/11/2024 के आलोक में जांच रिपोर्ट समर्पित करने के संबंध में।

संदर्भ- मंटु सोनी उर्फ शनि कांत,ग्राम+पोस्ट - बड़कागांव, जिला-हज़ारीबाग का परिवाद वाद पत्र दिनांक 14/10/2024

पत्र संख्या I.P.P.D. दिनांक 01/03/2025 हजारीबाग (झारखंड)

महाशय

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में परिवादी मंटु सोनी उर्फ शनि कांत,ग्राम+पोस्ट - बड़कागांव, जिला-हज़ारीबाग का परिवाद वाद पत्र दिनांक 14/10/2024 में यह आरोप लगाया गया था कि झारखंड राज्य के हज़ारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से शर्तों में छूट/संशोधन का आदेश लेकर तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग/गलत व्याख्या कर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से जंगल/आम।सड़क के रास्ते से बाणादाग रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन किया जा रहा है। जबकि FOREST CLEARANCE के शर्त में वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किए जाने का शर्त लगाया गया था। इसके बावजूद एनटीपीसी द्वारा कंवेयर सिस्टम और सड़क मार्ग दोनों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। जिसके कारण सबसे ज्यादा वन्य जीव प्रभावित हो रहे है ,उनके आवागमन प्रभावित हो रहे हैं और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी में घुस जा रहे हैं और मानव जीवन के जान माल,कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उपरोक्त तथ्य पर परिवादी मंटु सोनी ने दिनांक 12 अगस्त 2024 को पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, हज़ारीबाग को शिकायत किया था। जिसका स्क्रीन शॉट भी आवेदन के साथ लगाया गया है । साथ ही परिवादी मंटु सोनी उर्फ शनि कांत के शिकायत पर भारत सरकार के सहायक वन महानिरीक्षक श्री सुनीत भारद्वाज द्वारा दिनांक 08/09/2024 को हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 10/09/2024 को प्रधान सचिव(वन) रांची को क़ानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था। जिसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक,रांची,नोडल अधिकारी रांची वन विभाग को भी दी गई थी।

जांच टीम परिवादी मंटु सोनी उर्फ शनि कांत द्वारा उपरोक्त शिकायत एवं संलग्न साक्ष्यों का विवरण,तथ्य और अन्य सबूतों का अवलोकन किया। जिसमें यह बात सामने आई है कि एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 में प्रयोक्ता एजेंसी को हाथियों एवं अन्य वन्य जीवो के सुगम आवागमन के लिए बाणादाग रेलवे साइडिंग तक कंवेयर सिस्टम से कोयला ले जाना था। लेकिन एनटीपीसी विभिन्न कारणों का हवाला देकर ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्त में संशोधन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 6249/2021 में दिनांक 29/01/2024 के आदेश में एनटीपीसी को दिनांक 31.12.2024 तक कंवेयर CHP के साथ साइडिंग RLS कंप्लीट करने का अंतिम मौका दिया था। परन्तु एनटीपीसी ने उपरोक्त तिथि के बाद RLS के रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण और सिग्नलिंग के अधूरे काम को पूरा करने के नाम पर पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट नही जाकर ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) 19/05/2009 के शर्त संख्या 2 A (ix) जिसमें ये "Environmental laboratory shall be established with adequate number and type of pollution monitoring and analysis equipment in consultation with the State Pollution Control Board." कहा गया है,के आधार पर ENVIRONMENT CLEARANCE (EAC) से संशोधन प्राप्त सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन कर रहा

Checked by
15/3/2025
Asstt. Conservator of Forest
Hazaribag West Forest Division

अ.व.स.-ह.
27/02/2025

27/02/2025

है। परंतु एनटीपीसी द्वारा रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण और सिग्नलिंग का अधूरा काम बताया गया है । अगर ऐसी कोई समस्या थी तो एनटीपीसी को पुनः सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे अंतिम मौका दिया गया था। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट नही जाकर EAC से अनुमति प्राप्त किया है,तथा जहां तक कंवेयर सिस्टम बन चुका है वहाँ से भी सड़क मार्ग से कोयला परिवहन कर रहा है । जबकि उसके द्वारा रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण और सिग्नलिंग का अधूरा बता कर अनुमति लिया गया है तो उसे वहीं तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना चाहिए था जहां तक उसने अधूरा कार्य बताकर अनुमति लिया है। एनटीपीसी द्वारा ऐसा करने से FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का पूर्णत उल्लंघन हो रहा है। जबकि उपरोक्त शर्त में अब तक कोई संशोधन नही हुआ है और उक्त शर्त वन्य जीवों के सुगम आवागमन के उद्देश्य के लिए दिया गया था,उसका पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और वन्य जीवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। विदित हो कि उक्त वन क्षेत्र में शेड्यूल एक जो अतिसंरक्षित वन्य प्राणी होते है और शेड्यूल दो,तीन और चार तक वन्य जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार एनटीपीसी ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्त में संशोधन लेकर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर रहा है। जबकि FOREST CLEARANCE (FC) वन संरक्षण अधिनियम 1980 और ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से सम्बंधित है। दोनों का अलग-अलग विषय है और दोनों के अलग अलग कानून हैं और दोनों का डिवीजन भी अलग-अलग मानकों के अनुसार शर्त लगाता और उसका पालन करना अनिवार्य करता है। एनटीपीसी को ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) 19/05/2009 के शर्त संख्या 2 A (ix) जिसमें ये "Environmental laboratory shall be established with adequate number and type of pollution monitoring and analysis equipment in consultation with the State Pollution Control Board." के नाम पर शर्त संशोधन ले रही है और जो सिर्फ EAC के लिए मान्य है । इसमें कहीं भी FOREST CLEARANCE (FC) के शर्त को विलोपित नही किया गया है। क्योंकि ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) 19/05/2009 के शर्त संख्या 5. The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up के लिए ही मान्य है। जिससे स्पष्ट है कि एनटीपीसी FOREST CLEARANCE (FC) का उल्लंघन कर रही है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आता है और इसके उल्लंघन के कारण वन्य जीवों का भी नुकसान हो रहा है। जिससे जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का भी उल्लंधनन हो रहा है।

अतः जांच टीम यह मंतव्य देती है कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का निर्ममता से उल्लंघन कर रही है। वन्य जीवों के आवागमन (विशेषकर हाथी) बाधित नही होने के जिस मूल उद्देश्य से यह शर्त लगाया गया था,उसका उल्लंघन अब तक किया जा रहा है । जिसके कारण वन्य जीवों (विशेषकर हाथी) का आवागमन बाधित हुआ और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी वाले इलाकों में आकर आम नागरिकों के जानमाल/कृषि का नुकसान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले बाणादाग रेलवे साइडिंग व हज़ारीबाग़ शहर के नजदीक खिरगांव तक हाथी भटक कर आ गए थे। सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन के कारण दुर्घटनाओं में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । यह बात सत्य है कि एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्त में संशोधन लेकर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। जिसका FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-

Attested by
15/5/2025
Asstt. Conservator of Forest
Hazaribag West Forest Division

27/02/2025

27/02/2025

56/2009-FC के शर्त संख्या 9 से कोई संबंध नही है। ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) और FOREST CLEARANCE दो अलग-अलग पार्ट है। दोनों के द्वारा लगाई गई शर्तों का मानक और उद्देश्य अलग-अलग होता है। लेकिन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्तो में संशोधन लेकर FOREST CLEARANCE के शर्तो का अनुपालन नही कर रहा है। परिवादी मंटु सोनी उर्फ शनि कांत को जन सूचना पदाधिकारी द्वारा उचित सूचना भी उपलब्ध नही कराया गया है। इसलिए भवदीय से FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का अनुपालन सख्ती से करवाने की अनुसंशा जांच कमिटी द्वारा किया जाता है। उक्त शर्त के पालन की जिम्मेवारी वन विभाग का कर्तव्य/दायित्व होता है। इसका उल्लंघन FOREST CONSERVATION ACT 1980 एवं WILd LIFE PROTECTION ACT 1972 के तहत आता है।

भवदीय
जांच कमिटी

ए० के० परमार
सहायक वन संरक्षक
पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

27/02/2025
अरुण कुमार सिन्हा
सहायक वन संरक्षक
पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

Attested by
15/12/2025
Asstt. Conservator of Forest
Hazaribag West Forest Division

(अनुलग्नक 02)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक [illegible] / दिनांक [illegible]

सेवा में,

श्री अंकित राज
हुरहुरू रोड,
नियर डगर चौक,
हजारीबाग,
मो० 9199106958

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 08.04.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में मांगी गयी सूचना निम्नवत इस पत्र के साथ संलग्न कर दी जा रही है।

	प्रश्न	उत्तर
1	एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह कोल माइंस, चट्टी बरियातू कोल माइंस एवं केरेडारी कोल माइंस में कुल कितने वन भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहित वन भूमि के अन्तर्गत कितने पेड़ पौधों एवं जंगल की कटाई एवं नुकसान की हुई है/ हो सकती है। उसकी भरपाई के लिए कितने जमीन में कहां–कहां कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसका पूर्ण विवरणी अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध कराई जाए।	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण एन०टी०पी०सी० केरेडारी कोल खनन परियोजना के पक्ष में वनभूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। एन०टी०पी०सी० पकरीबरवाडीह कोल खनन परियोजना एवं एन०टी०पी०सी० चट्टीबरियातू कोल खनन परियोजना में अधिग्रहित / विमुक्त वन भूमि का विवरण निम्नवत दिया जा रहा है :–

क्र० सं०	परियोजना एवं प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित अधिसूचित वन भूमि का रकबा (हे० में)	
		अधि० निर्गत वन भूमि का रकबा (हे०में)	अधि० प्रतिस्थापित वन भूमि का रकबा (हे०में)
1	2	3	4
1	एन०टी०पी०सी० लि० पकरीबरवाडीह कोल खनन परियोजना	519.00	289.775
2	एन०टी०पी०सी० लि० चट्टी बरियातु कोल खनन परियोजना	61.70	47.07

एन०टी०पी०सी०लि० द्वारा अधिग्रहित वन भूमि के एवज में कुल 13304 वृक्षों के पातन की अनुमति दी गई है। एन०टी०पी०सी० पकरीबरवाडीह कोल खनन परियोजना के तहत कुल 2093 हे० अवक्रमित वनभूमि पर वनरोपण किया जाना है, जिसमें से 1323 हे० वन भूमि पर वनरोपण कार्य कराया जा चुका है, 500 हे० वन भूमि पर अग्रिम

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>वनरोपण कार्य वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित किया गया है तथा शेष 230 है0 पर वनरोपण अगले वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जायेगा। एन0टी0पी0सी0 पछी बरियातु कोल खनन परियोजना के तहत कुल 258 है0 पर वनरोपण कार्य किया जाना है, जिसमें से 100 है0 वन भूमि पर वनरोपण कार्य कराया जा चुका है, 158 है0 वन भूमि पर अग्रिम वनरोपण कार्य वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न है (Anx-1)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>उक्त तीनों कोल माइंस में Forest Notification किस आधार एवं शर्त पर कब से कब तक है /था, उसका पूर्ण विवरणी उपलब्ध करायी जाए।</td>
<td>एन0टी0पी0सी0 पकरीबरवाडीह एवं पछीबरियातु कोल खनन परियोजनाओं को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 8-56/ 2009 FC dated 17.09. 2010 एवं F.No. 8-42/ 2010 FC dated 25.11. 2011 (छायाप्रति संलग्न) (Annex-2) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2 के तहत वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है , जो स्वतः स्पष्ट है।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>उक्त तीनो कोल माइंस परियोजनाओं में अधिसूचित कितने भूमिहीनों, रैयती, आदिवासीयों को वन पट्टा दिया गया है, अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायी जाए।</td>
<td>वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड वन क्षेत्र अन्तर्गत पिछले पन्द्रह सालो में जंगली जानवरों से कितने घर, फसल व जानमाल का नुकसान हुआ है। इससे प्रभावित कितने पीड़ितों को कितना मुआवजा मिला है एवं कितने लोग अभी तक मुआवजा से वंचित हैं।</td>
<td>बड़कागांव प्रक्षेत्र अन्तर्गत जंगली जानवरों द्वारा की गई जान माल की क्षति एवं मुआवजा भुगतान की विवरणी निम्नवत है :–

वर्ष 2015–16
<table>
<tr><th>मामल सं0</th><th>मकान क्षति</th><th>फसल भंडारित अनाज</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>149</td><td>670000/–</td><td>595338/–</td><td>1265338/–</td></tr>
</table>

वर्ष 2014–15
<table>
<tr><th>मामल सं0</th><th>मकान क्षति</th><th>फसल भंडारित अनाज</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>206</td><td>733500/–</td><td>334425/–</td><td>1067925/–</td></tr>
</table>

वर्ष 2013–14 – शुन्य
वर्ष 2012–13 – शुन्य
वर्ष 2011–12–घायल सं0 02 मुआवजा राशि–66666/–
वर्ष 2010–11–घायल सं0 01 मुआवजा राशि–33333/–
वर्ष 2009–10 – मृत सं0 01 मुआवजा राशि–100000/–</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>उक्त जंगली क्षेत्रों में कितने जीव जन्तु जानवर पाये जाते हैं।</td>
<td>हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत पाये जाने वाले जीव जन्तु की सूची संलग्न है। (Annex-3)</td>
</tr>
</table>

	अब तक कितने जानवर भटकते हुए आबादी वाले क्षेत्रों में आ गये है। जिसे पकड़ा गया है। उसकी पूर्ण सूची एवं विवरण अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायी जाए।	ऐसी कोई सूचना वनमण्डलीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

प्रभारी,
FCA शाखा

प्रभारी,
वन्यप्राणी शाखा

प्रभारी,
बिक्री शाखा

प्रधान लिपिक

आस्था तिवारी
जन सूचना अधिकारी
-एवं-
सहायक वन संरक्षक
[illegible] [illegible] वनमण्डल

Annex.3

LIST OF COMMON ANIMAL AND BIRDS OF HAZARIBAGH WEST FOREST DIVISION.

English Name	Zoological Name
Mammals	
Common Langur	*Presbytis entellus*
Rhesus Monkey	*Macaca mulatta*
Leopard or Panther	*Panthera pardus or leo*
Jungle Cat	*Felis chaus*
Indian Wild Dog	*Cuon alpines*
Wolf	*Canis lupus*
Indian Wild Boar	*Sus scrofa*
Striped Hyena	*Hyaena hyaena*
Sambhar	*Cerus elaphus*
Chital (Spotted deer)	*Axis axis*
Common Deer	*Cervus Nippon*
Barking Deer	*Muntiaecus sps.*
Nilgai or Blue Bull	*Boselaphus tragocamelus*
Sloth Bear	*Melursus ursinus*
The Indian Elephant	*Elephus maxius*
Hog Badger	*Arctonyx connaris*
Ratel	*Mellivora opensis*
Smooth Indian Otter	*Lutra lutra*
Common Mangoose	*Herpestes edwardsi*
Small Indian Mangoose	*Herpestes auropunetatus*
Small Indian Cevet	*Viverricula Indica*
Common palm Cevet	*Paradoxurux hermaphroditus*
Jackal	*Canis aureus*
Indian Fox	*Vulpes bengalensis*
Indian Hare	*Lepus nigricollis*
Indian Pangolin	*Manis crassicaudata*
Indian Porcupine	*Hystrix indica*
Three-striped Palm Squirrel	*Funambulus palmarum*
Indian Giant Squirrel	*Ratufa indica*
Fulvous Fruit Bat	*Rousettus leschenaultia*
Indian Flying Fox (Bat)	*Pteropus giganteus*
Indian Field Mouse	*Mus booduga*
Indian Bush Rat	*Golunda elliotl*
Bandicoot Rat	*Bandicota indica*
REPTILES	
SNAKES :	*Bungarus fasciatus*
Karait, Banded	*Bungarus caeruleus*
Karait, Common	*Naja naja*
Cobra	*Vipra ruselli*
Russel'viper	*Pylas mucosus*
Rat Snake	*Python molurus*
Python, Indian	*Ahaefulla nasutus*
Harhara	
LIZARDS :	*Chamelion calcarata*
Chamelion	*Varanus monitor*
Lizard, Monitor	*Hemidactylus flaviviridus*
Gecko, Indian House	*Agama tuberculatus*
Lizard, Rock	

English/ Common Name	Zoological Name
Hornbill, Common Grey	*Tockus birostris*
Ibis, Black	*Pseudibis papillosa*
Lora	*Aegithina tiphia*
Kingfisher, Pied	*Ceryle rudis*
Kingfisher, Small Blue	*Alcedo atthis*
Kingfisher, White-breasted	*Halcyon smyrnensis*
Kite, Common Pariah	*Milvus migrans*
Koel	*Eudynamys scolopacea*
Lapwing, Redwattled	*Vanellus indicus*
Lark, Black-bellied Finch	*Eremopterix grisea*
Lark, Crested	*Galerida cristata*
Lorikeet	*Loriculus vernalis*
Minivet, Scarlet	*Pericrocotus flammeus*
Minivet, Small	*Pericrocotus cinnamomeus*
Munia, Black-headed	*Lonchura Malacca*
Munia, Green	*Estrilda Formosa*
Munia, Spotted	*Lonchura punctulata*
Myna, Bank	*Acridotheres ginginianus*
Myna, Brahmini or Black Headed	*Sturnus pagodarum*
Myna, Indian	*Acridotheres tristis*
Myna, Jungle	*Acridotheres fuscus*
Myna, Pied	*Sturnus contra*
Nightjar, Common Indian	*Caprimulgus esiaticus*
Oriole, Black-headed	*Oriolus xanthornus*
Oriole, Golden	*Oriolus oriolus*
Owl, Barn or Screech	*Tyto alba*
Owl, Brown Fish	*Bubo zeylonensis*
Owl, Indian great horned	*Bubo bubo*
Owlet, Barred Jungle	*Glaucidium radiatum*
Parakeet, Alexandrine or Large Indian	*Psittacula eupatria*
Parakeet, Blossom-headed	*Psittacula cyanocephala*
Parakeet, Roseringed	*Psittacula krameri*
Parakeet, Black	*Francolinus francolimus*
Patridge, Grey	*Francolinus pondiserianus*
Peafowl, Common	*Pavo cristatus*
Pheasant, Crow or Coucal	*Centropus siensis*
Pie, Tree	*Dendrocitta vagabunda*
Pigeon, Common Green	*Treron phoenicoptera*
Pitta, Indian	*Pitta brachyuran*
Quail, Common or Bluelegged Bustard	*Turnix suscitator*
Quail, Common or Grey	*Coturnix coturnix*
Robin, Indian	*Saxicoloides fulicata*
Robin, Magpie	*Copsychus saularis*

FISHES :	
Bata	*Labeo bata*
Bokwa	*Eutropichtys baoche*
Garai	*Channa punctatus*
Katla	*Catla catla*
Mangoor	*Clarious batrachus*
Mirgal	*Cirrhina mrigala*
Pothia	*Punctius ticta*
Rohu	*Labeo rohita*
Zebra	*Danio rerio*

BIRDS :

English/ Common Name	Zoological Name
Babbler, Common	*Turdoides caudatus*
Babbler, Jungle	*Turdoides striatus*
Barbet,Crimson-breasted or Coppersmith	*Megalaima haemacephala*
Bee-eater, Blue-tailed	*Merops philippinus*
Bee-eater, Small Green	*Merops orientalis*
Bird, Tailor	*Orthotomus sutorius*
Bittern, Little Green	*Butorides striatus*
Bulbul, Red-vented	*Pycnonotus cafer*
Bulbul, Red-whiskered	*Pycnonotus jocosus*
Crow, House	*Corvus splendens*
Crow, Jungle	*Corvus macrorhynchos*
Cuckoo, Common Hawk or Brainfever Bird	*Cuculus varius*
Dove, Little Brown	*Streptopelia senegalensis*
Dove, Ring	*Streptopelia decaocto*
Dove, Spotted	*Streptopelia chinensis*
Drongo, Black or Kind Crow	*Dicrurus adsimilis*
Drongo, Racket Tailed	*Dicrurus paradiseus*
Eagle, Crested Hawk	*Spizaetus cirrhatus*
Eagle, Crested Serpent	*Spilornis cheela*
Egret, Cattle	*Bubulcus ibis*
Egret, Little	*Egretta garzetta*
Flowerpecker, Thick-billed	*Dicaeum agile*
Flycatcher, Grey-headed	*Culicicapa ceylonensis*
Flycatcher, Paradise	*Terpsiphone paradise*
Flycatcher, White spotted fantail	*Rhipidura albicollis*
Fowl, Red Jungle	*Gallus gallus*
Heron, Grey	*Ardea cinerea*
Heron, Night	*Nycticorax nycticorax*
Heron, Pond or Paddy Bird	*Ardeola grayii*
Hoopoe	*Upupa epops*

English/ Common Name	Zoological Name
Roller or Blue Jay	*Coracias benghalensis*
Shama	*Copsychus malabaricus*
Shikra	*Accipiter badius*
Sparrow, House	*Passer domesticus*
Sparrow, Yellow-Throated	*Petronia xanthocollis*
Stork, White	*Ciconia ciconia*
Sunbird, Purple	*Nectarinia asiatica*
Sunbird, Purple – Rumped	*Nectarinia zeylonica*
Swallow, Common	*Hirundo rustica*
Swallow, Wire-tailed	*Hirundo smithii*
Swift, Crested Tree	*Hemiprocne longipennis*
Swift, House	*Apus affinis*
Teal, Common	*Anas crecca*
Tern, River	*Sterna aurantia*
Vulture, White-backed or Bengal	*Gyps bengalensis*
Wagtail, Grey	*Motacilla caspica*
Wagtail, Large Pied	*Motacilla maderaspatensis*
Weaver Bird, Baya	*Ploceus philippinus*
White-eye	*Zosterops palpebrosa*
Woodpecker, Golden-backed	*Dinopium benghalense*

(अनुलग्नक 02 A)

F. No. 8-56/2009-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 510,
Dated: 17th September, 2010

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Jharkhand,
Ranchi.

Sub:- Diversion of 1026.438 ha of forest land for coal mining from Pakribarwadih Project in favour of M/s. NTPC in Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand.

Sir,

I am directed to refer to the State Govt. letter no. 3/VanBhumi-75/2009/2458/VP dated 06.08.2009 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principle approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 11.05.2010 subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide letter no. dated 16.08.2010, approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 1026.438 ha of forest land for coal mining from Pakribarwadih Project in favour of M/s. NTPC in Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand subject to fulfillment of the following conditions:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.

2. a Compensatory afforestation shall be raised and maintained by the State Forest Department at the project cost.

   b Fencing, protection and regeneration of the safety zone area shall be done at the project cost. Besides this, afforestation on degraded forest land, to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost.

   c Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

3. Following activities shall be undertaken by the User Agency under the supervision of the State Forest Department at the project cost:

   (i) Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented.

   (ii) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.

   (iii) Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.

   (iv) The areas shall be reclaimed keeping in view the international practice of stabilizing the dumps by grading / benching so that angles of repose (normally less than 28 at any given place) are maintained.

   (v) The top soil management plan should be strictly adhered to.

4. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

5. The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.

6. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986.

7. The user agency will make arrangement for free supply of coal to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.

8. The user agency will take up programme for at least 50 m greenbelt along the sides of the Pakwa nallah and Dumuhani nallah from the initial years under the supervision of the State Forest department.

9. The coal evacuation will be done through high speed conveyer of 20 meter width running at n height sufficient to allow all tall wild animals including elephants. The installation of such system will be undertaken under the supervision of the CWLW of the State.

10. The State Govt. to implement the rehabilitation policy of the State with respect to landless as submitted with the compliance report.

11. The user agency will assist the State Government in conservation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State.

12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the

proposal.

13. No labour camps shall be set up inside the forest area.

14. The user agency shall provide fuel wood preferably alternate fuel to the labourers working at the site to avoid damage / felling of trees.

15. The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 years or co-terminus with the mining lease subject to possession of valid lease by User Agency under the MMDR Act, 1957.

16. Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward & back bearings and distance from pillar to pillar.

17. Mining / reclamation schedule shall be implemented by the user agency at their cost as per Environmental Management Plan / phased reclamation programme. The annual report about the progress of reclamation should be submitted to the CCF (Central), Bhubaneshwar.

18. The user agency shall also take up study on soil erosion / soil flow from the over-burden areas with the help of GIS in consultation with the forest department.

19. The user agency shall take up the de-silting of the village tanks within five km area from the mine lease boundary as a Corporate's social responsibility so as to mitigate the impact of siltation of such tanks if any.

20. Any other condition that the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhubaneshwar may impose from time to in the interest of conservation, protection or development of forests.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests Government of Jharkhand, Ranchi.
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Jharkhand, Ranchi.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhubaneshwar.
4. User Agency for information.
5. Monitoring cell of the FC section
6. Guard file.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

(अनुलग्नक 02 B)

No.J-11015/692/2007-IA.II(M)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhawan,
C.G.O.Complex,
New Delhi -110510.

Dated: 19th May 2009

To
Shri A.B.Haldar
Additional General Manager (CM),
M/s National Thermal Power Corporation Ltd.,
Engineering Office Complex,
A-8A, Sector 24, NOIDA – 201301

Sub: Pakri Barwadih Coal Mine Project (15 MTPA) of M/s National Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC) Ltd. located in villages Barkagaon, Itij, Chiruadih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduari, Churchu, Carahara, Sonbarsa, Pakri-Barwadih, Chepa-Khurd, Deora-Kalan, Lakura, Langatu, Keri, Dadikalan, Tehsil Barkagaon, District Hazaribagh, Jharkand - environmental clearance – reg.

Sir,

This has reference to letter No. CC/CM&CW/MoEF/01 dated 27.06.2007 along with application for environmental clearance and subsequent letters dated 16.08.2007, 14.03.2008, and 17.03.2009 on the above-mentioned subject. The Ministry of Environment & Forests has considered your application. It has been noted that the project is for **opening a new coal mine – Pakri-Barwadih Opencast Coal mine Project of 15 million tonnes per annum (MTPA) rated capacity** for its linked Thermal Power Station. The existing project consists of Phase-I of 39 years and comprises of opencast operations only and would be restricted to the explored lease area of 3319.42 ha. Of this area, 643.9 ha is forestland, 1950.51 ha is agricultural land, 159.64 ha is barren and wasteland, 435 ha is grazing land, 101.22 ha is human settlements and 29.15 ha includes roads and seasonal nala. In addition, an area of 68.58 ha is being acquired outside the ML at a distance of 2 km from the ML for township comprising 150 dwellings. There are no National Parks, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserves found in the 10 km buffer zone. Barkagaon Reserve Forest is situated within the core zone and in the buffer zone. Forestry clearance has bee applied for. There are endangered fauna such as Sloth Bear reported in the study area. Elephant has not been reported from the area.. A monolith found within the core zone is not a centrally protected monument. Ghagri nadi flows south of the ML at a distance of 1.5 km from west to east. Hahro nadi flows at a distance of 1.5km south of ML from SW to northern direction. It is proposed to modify the natural drainage by diversion and realignment of the nalas and by construction of an embankment. Of the total mining lease area, 25 ha is for topsoil dump, 632 ha is for external OB dump, 1785 ha is quarry area, 31 ha is for roads, 18 ha is for infrastructure and 797 ha is undisturbed area. The project involves R&R of 17 villages. A land of 141.70 ha is being acquired as R&R site in villages Dhenga and Lakura on the eastern side of the Block. Detailed R&R has been prepared for Phase-1 consisting of 7 villages and involving a total 2221 PAPs – Chirudih (10), Itiz (125), Nagadi (125), Arhara (202), Pakri-Barwadih (634), Dadikalan (665), Chepakalan (460). An area outside the mining area where infrastructure will be located also involves an R&R of a total 1068 land oustees which would also be completed in Phase-I. The balance 10 villages – Sinduari, Sonbarsa, Churchu, Jugra, Chepakhurd, Keri, Langatu, Deoriakhurd, Urub, Barkagaon are to be taken up for R&R in subsequent phases and are under survey.

Mining will be opencast by mechanised method involving shovel-dumper and involves drilling and blasting. **Rated capacity of the mine is 15 (MTPA).** Mineral transportation of coal from the mine to CHP would be by closed conveyors and by rail link to the linked TPP. Railway siding would be provided with Silo Loading System. Ultimate working depth of the mine would be 300m below ground level (bgl). Water table in the study area during pre-monsoon is in a range of 4.24m –14.64 m and in a range of 1.52- 8.54m during post-monsoon. Peak water requirement is 4576 m3/d of

which 526 m3/d is for domestic consumption to be met from ground water, and the of the remaining 4050 m3/d, 3400 m3/d would be from mine pit water and 650 m3/d form recycled water. An estimated 2118 Mm3 of OB will be generated over the life of mine (39 years) of which 1238 Mm3 would be from western quarry (first 25 years) and 860 Mm3 would be from eastern quarry (25th – 39th year). Of the 1238 Mm3 of OB form the westen quarry, 595 Mm3 of ob would be dumped externally in two external OB dumps (A and B) and 643 Mm3 would be stored in external dump C. Max. height of the 3 dumps would be 90m. The entire OB of 860 Mm3 from eastern quarry would be abckfilled over an area of 665 ha and reclaimed into grazing land (223 ha) and agricultural land (442 ha) at the psot mining stage. Ultimate working depth is 300m. Life of mine at the rated capacity of 15 MTPA is 39 years. Public Hearing was held on 16.04.2007. Mining Plan has been approved for 15 MTPA on 25.08.2006. **Capital cost of the project is Rs. 4500 crores.**

2. The Ministry of Environment & Forests hereby accords environmental clearance for the above-mentioned **Pakri Barwadih Coal mine Project** of **M/s NTPC Limited of a production capacity of 15 MTPA in a total lease area of 3319.42 ha** under the provisions of Section 12 of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006, and subsequent amendments thereto and under MOEF Circulars there under subject to the compliance of the terms and conditions mentioned below:

A. Specific Conditions

(i) The environmental clearance is restricted to Phase-1 of 39 years of opencast operations involving 3319.42 ha of ML area only for which exploration has been completed.

(ii) No mining operations shall be undertaken in the forestland within the ML until clearance has been obtained under the provisions of FC Act, 1980.

(iii) The monolith found within the core zone shall not be disturbed by the mining operations and a minimum 500m distance along with thick green belt would be maintained between the eastern quarry and the monolith. A road would be created upto the monolith a park created around it so that the monolith could be visited.

(iv) Mining shall be carried out as per statuette from the streams/nallahs flowing within the lease. Embankment to be constructed shall be based on peak flow data and shall be at least 3m above the HFL. The slope of the embankment shall at least 2:1 towards the ML and shall be stabilised with plantation. The CWPRS would be engaged for the design and study of realignment of the drains/nalas flowing across the ML and creation of embankment, and also obtain approval of the State Government for diversion of the nalas

(v) Topsoil should be stacked properly with proper slope at earmarked site(s) and should not be kept active and shall be used for reclamation and development of green belt.

(vi) OB should be stacked at earmarked three external OB dumpsite within ML area of a maximum height of 90m. A minimum of 500m shall be maintained and thick green belt developed between the habitation and OB dumps particularly that of Barkhagaon. The option of raising the level of grazing land created after backfilling the quarry by 10m or so shall be examined so to reduce the overall OD dump height. Slope stability tests may be undertaken and the feasibility of backfilling depending on the type of cost effective technology available at that stage shall be re-examined. The ultimate slope of the dump shall not exceed 28°. Monitoring and management of reclaimed dumpsite should continue until the vegetation becomes self-sustaining. Compliance status should be submitted to the Ministry of Environment & Forests and its Regional office located at Bhubaneshwar on yearly basis.

(vii) Catch drains and siltation ponds of appropriate size should be constructed to arrest silt and sediment flows from soil, OB and mineral dumps. The water so collected should be utilised

for watering the mine area, roads, green belt development, etc. The drains should be regularly desilted and maintained properly.

Garland drains (size, gradient and length) and sump capacity should be designed keeping 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity should also provided adequate retention period to allow proper settling of silt material.

(viii) Dimension of the retaining wall at the toe of the dumps and OB benches within the mine to check run-off and siltation should be based on the rainfall data.

(ix) The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation from CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System.

(x) Drills should be wet operated only.

(xi) Controlled blasting should be practiced with use of delay detonators. The mitigative measures for control of ground vibrations and to arrest the fly rocks and boulders should be implemented.

(xii) No additional groundwater (bore well) shall be used for mining operations. Additional water if any required for the project shall be used from recycled water or mine discharge water or rainwater collected in rainwater harvesting pits within the CML.

(xiii) Regular monitoring of groundwater level and quality should be carried out by establishing a network of exiting wells and construction of new pelzometers. The monitoring for quantity should be done four times a year in pre-monsoon (May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) seasons and for quality in May. Data thus collected should be submitted to the Ministry of Environment & Forests and to the Central Pollution Control Board quarterly within one month of monitoring. Rainwater structures shall be erected in the core and buffer zone, in case monitoring indicates a decline in water table.

(xiv) The project authorities should meet water requirement of nearby village(s) in case the village wells go dry due to dewatering of mine.

(xv) Sewage treatment plant of adequate capacity shall be installed in the colony. ETP should also be provided for workshop and CHP wastewater. Treated wastewater meeting prescribed norms only shall be recycled for mining operations to the extent possible and permitted to be discharged in to the natural water courses only if it meets the prescribed standards.

(xvi) The total area that shall be brought under afforestation at the time of mine closure shall not be less than 1199 ha which includes reclaimed topsoil soil dump area (25 ha), external OB dump (632 ha), backfilled area (524 ha), along ML boundary, embankment and undisturbed area, along roads and infrastructure, green belt (18 ha), and in township outside the lease by planting native species in consultation with the local DFO/Agriculture Department. The density of the trees should be around 2500 plants per ha.

(xvii) A Progressive Mine Closure Plan shall be implemented by reclamation of 524 ha, of the total quarry area of 1785 ha, which shall be backfilled and afforested by planting native plant species in consultation with the local DFO/Agriculture Department. The density of the trees should be around 2500 plants per ha. Of the total reclaimed backfilled area, 223 ha shall be grazing land and 442 ha shall be agricultural land for utilisation of the villagers.

Of the balance 1261 ha of quarry area, an area of 596 ha of decolaed area/void being converted into a water reservoir shall be gently sloped and the the upper benches of

the reservoir shall be terraced and stabilised with plantation and the remaining 665 ha is for public use for Phase-2 of the project.

(xviii) Besides carrying out regular periodic health check up of their workers ≥10% of the workers identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected to health check up for occupational diseases and hearing impairment, if any, through an agency such as NIOH, Ahmedabad within a period of one year and the results reported to this Ministry and to DGMS.

(xix) A detailed R&R Plan for the life of the project comprising land losers, homestead losers and land and homestead losers, including tribals to be displaced from the project area shall be prepared and implemented in a stipulated time-frame. Phase-I of the R&R comprising of 2221 PAPs shall be implemented within one year. The compensation shall be not less than that specified in the National R&R Policy. Provision shall also be made in the R&R Plan to take care of the land less labourers and the tribals. The total expenditure on R&R shall not be less than Rs. 700 crores, which includes land acquisition (Rs. 30 crores) and R&R (350 crores). Alternate livelihood and skill development programmes and schemes shall be implemented as part of R&R and CSR.

(xx) The project authorities shall carry out a pre-mining socio-economic survey based on the UNDP Human Development Report and monitor the socio-economic status once every three years and maintain records thereof and report in their Annual Report, the socio-economic impact of R&R and CSR activities.

(xxi) For monitoring land use pattern and for post mining land use, a time series of landuse maps, based on satellite imagery (on a scale of 1: 5000) of the core zone and buffer zone, from the start of the project until end of mine life shall be prepared once in 3 years (for any one particular season which is consistent in the time series), and the report submitted to MOEF and its Regional office at Bhubaneshwar.

(xxii) A Final Mine Closure Plan along with details of Corpus Fund should be submitted to the Ministry of Environment & Forests 5 years in advance of final mine closure for approval.

B. General Conditions

(i) No change in mining technology and scope of working shall be made without prior approval of the Ministry of Environment and Forests.

(ii) No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral coal and waste shall be made.

(iii) Four ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring SPM, RPM, SO2, NOx and heavy metals such as Hg, Pb, Cr, As, etc. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board.

(iv) Fugitive dust emissions (SPM and RSPM and heavy metals such as Hg, Pb, Cr., As, etc) from all the sources shall be controlled regularly monitored and data recorded properly. Water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, dump trucks (loading and unloading) points shall be provided and properly maintained.

(v) Data on ambient air quality (SPM, RSPM, SO2, NOx and heavy metals such as Hg, Pb, Cr, As, etc)) shall be regularly submitted to the Ministry including its Regional Office at Bhopal and to the State Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board once in six months.

(vi) Adequate measures shall be taken for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of HEMM, etc shall be provided with ear plugs/muffs.

(vii) Industrial wastewater (workshop and wastewater from the mine) shall be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th May 1993 and 31st December 1993 or as amended from time to time before discharge. Oil and grease trap shall be installed before discharge of workshop effluents.

(viii) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored.

(ix) Environmental laboratory shall be established with adequate number and type of pollution monitoring and analysis equipment in consultation with the State Pollution Control Board.

(x) Personnel working in dusty areas shall wear protective respiratory devices and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
Occupational health surveillance programme of the workers shall be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and to take corrective measures, if needed.

(xi) A separate environmental management cell with suitable qualified personnel shall be set up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the company.

(xii) The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year-wise expenditure shall be reported to this Ministry and its Regional Office at Bhopal.

(xiii) The Regional Office of this Ministry located at Bhopal shall monitor compliance of the stipulated conditions. The Project authorities shall extend full cooperation to the office(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/ information/monitoring reports.

(xiv) A copy of the will be marked to concerned Panchayat/ local NGO, if any, from whom any suggestion/representation has been received while processing the proposal.

(xv) State Pollution Control Board shall display a copy of the clearance letter at the Regional Office, District Industry Centre and Collector's Office/Tehsildar's Office for 30 days.

(xvi) The Project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution control Board and may also be seen at the website of the ministry of Environment & Forests at http://envfor.nic.in. The compliance status shall also be uploaded by the project authorities in their website and regularly updated at least once in six months so as to bring the same in the public domain. The data shall also be displayed at the entrance of the project premises and mines office and in corporate office.

3. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection.

4. Failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

5. The above conditions will be enforced *inter-alia*, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up

remedial measures in case of soil contamination, contamination of groundwater and surface water, and occupational and other diseases due to the mining operations.

(Dr.T.Chandini)
Director

Copy to:

1. Secretary, Ministry of Coal, New Delhi.
2. Secretary, Department of Environment & Forests, Government of Jharkand, Secretariat, Ranchi.
3. Chief Conservator of Forests, Regional office (EZ), Ministry of Environment & Forests, A-31, Chandrashekarpur, Bhubaneshwar – 751023.
4. Chairman, Jharkand State Pollution Control Board, T.A. Division Building (Ground Floor), H.E.C., Dhurwa, Ranchi – 834004.
5. Chairman, Central Pollution Control Board, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi -110032.
6. Member-Secretary, Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources, Curzon Road Barracks, A-2, W-3 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
7. District Collector, Hazaribagh, Government of Jharkand.
8. Monitoring File 9. Guard File 10. Record File

(अनुलग्नक 03)

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.6249 OF 2021

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED (NTPC) ...Appellant(s)

Vs.

TRIPURARI SINGH & ORS. ...Respondent(s)

O R D E R

Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General appearing on behalf of the appellant submits that due to certain unavoidable circumstances, the construction of the conveyor belt could not be completed as per clause 6.3 of the report of the Jharkhand Pollution Control Board (State PCB) as reproduced in paragraph 3 of the impugned order. He requests for time till October, 2023 for completion of the construction of the conveyor belt. There is no challenge to the other conditions of the Report of the State PCB by the appellant.

In view of the above,the appeal is disposed of with a

Signature Not Verified
Digitally signed by
Anita Malhotra
Date: 2023.06.10
16:37:13 IST
Reason:

direction to the appellant to complete the construction of the conveyor belt on or before October, 2023.

.......................J.
(S.ABDUL NAZEER)

.......................J.
(J.K.MAHESHWARI)

New Delhi;
August 8, 2022.

(अनुलग्नक 03 A)

ITEM NO.58 COURT NO.13 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021

(Arising out of impugned final judgment and order dated 08-08-2022 in C.A. No. 6249/2021 passed by the Supreme Court of India)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED (NTPC) Petitioner(s)

VERSUS

TRIPURARI SINGH & ORS. Respondent(s)

(IA No. 155852/2023 - EXTENSION OF TIME and IA No. 192404/2023 - GRANT OF INTERIM RELIEF)

Date : 20-10-2023 This matter was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MAHESHWARI
HON'BLE MR. JUSTICE K.V. VISWANATHAN

For Petitioner(s)
Mr. Tushar Mehta, Solicitor General
Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mr. Shailesh Madiyal, AOR
Mr. Sudhanshu Prakash, Adv.
Mr. Vaibhav Sabharwal, Adv.
Mr. Akshay Kumar, Adv.
Ms. Divija Mahajan, Adv.

For Respondent(s)
Mr. Vikramjeet Banerjee, A.S.G.
Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR
Mr. Piyush Beriwal, Adv.
Mr. S K Gupta, Adv.
Ms. Nidhi Khanna, Adv.
Ms. Chinmaee Chandra, Adv.
Mr. Rajesh Kumar Singh, Adv.
Mr. Ishaan Sharma, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Ahuja
Date: 2023.10.21 16:28:42 IST
Reason:

By this application, the National Thermal Power Corporation Limited has made the following prayer:

> "a) Allow the present application; and
> b) Extend the timeline for completion of the entire Coal Conveying System facilities /CHP [from mine to Railway siding] at Appellant's Pakri Barwadih Coal Mine Project, Barkagaon, Hazaribag, until 31st December, 2024"

Earlier, this Court by its order on 08.08.2022 had extended the timeline for completion of the construction of the conveyor belt till 31.10.2023.

When the application was taken up, response from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as 'MoEF&CC' for brevity) was called for. MoEF&CC has filed an affidavit dated 13.10.2023 wherein after setting out the background, in para 18 they have averred as under:

> "18. That, however, it is pertinent to mention here that the Sectoral Expert Appraisal Committee i.e., EAC appraises proposal for amendment in EC as per the merits of each case subject to observance of applicable environmental safeguards. Applications for extension in timeline for installing mechanized systems are appraised under the category of amendment in EC. As per the direction of the Hon'ble Supreme Court, Ministry can have the instant matter, seeking extension in timeline for installation of mechanized coal transportation system, appraised afresh by the Sectoral EAC upon receipt of such application for amendment in EC. The outcome of such an appraisal shall be made available to the Project Proponent for any further direction regarding the matter by Hon'ble Supreme Court."

MA No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021

Having considered the averments made in the application and the reply of MoEF&CC, we extend the timeline fixed by the order of this Court dated 08.08.2022, till 31.01.2024.

In the meantime, we also give liberty to the applicant to file an appropriate application for amendment of the Environmental Clearance Certificate (EC). On the filing of such an application, MoEF&CC through the Sectoral Expert Appraisal Committee i.e., EAC shall appraise the matter afresh.

The outcome of the appraisal may be placed before this Court after information to the Project Proponent.

List the matter on 29th January, 2024.

(NIDHI AHUJA)
AR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

ITEM NO.39 COURT NO.9 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED (NTPC) Petitioner(s)

VERSUS

TRIPURARI SINGH & ORS. Respondent(s)

IA No. 155852/2023 - EXTENSION OF TIME
IA No. 192404/2023 - GRANT OF INTERIM RELIEF

Date : 29-01-2024 This matter was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MAHESHWARI
HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KAROL

For Petitioner(s) Mr. Tushar Mehta, Solicitor General
Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mr. Adarsh Tripathi, AOR
Mr. Vikram Singh Baid, Adv.
Mr. Ajitesh Garg, Adv.

For Respondent(s) Mr. Anand Varma, AOR
Ms. Adyasha Nanda, Adv.

Mr. Shivam Kumar, Adv.
Mr. Vaibhav Prasad Deo, Adv.
Ms. Mudita Arora, Adv.
M/S. Qua Legal, AOR

Mr. Piyush Beriwal, Adv.
Mr. S K Gupta, Adv.
Ms. Nidhi Khanna, Adv.
Ms. Chinmaee Chandra, Adv.
Mr. Rajesh Kumar Singh, Adv.
Mr. Ishaan Sharma, Adv.
Ms. Muskan Gupta, Adv.
Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Signature Not Verified
Digitally signed by
Jayant Kaur Arora
Date: 2024.01.30
11:34:05 IST
Reason:

No. 155852 of 2023

Having heard learned Solicitor General appearing for the petitioner – NTPC and learned counsel appearing for the respondents,

we are of the considered view that in view of the averments made in the application for extension of time i.e. I.A. No. 155852 of 2023, the time as fixed vide our order dated 20.10.2023 is required to be extended till 31.12.2024. Ordered accordingly.

In view of the above, Misc. Application No. 1824 of 2023, along with I.A. No. 155852 of 2023, is, accordingly, disposed of.

(JAYANT KUMAR ARORA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

(अनुलग्नक 03 B)

सत्यमेव जयते

File No.: J-11015/692/2007-IA-II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
IA Division
***

Dated **02/01/2025**

To,

Sh. Navin Kumar
M/s NTPC Mining Limited
Ntpc Bhawan, Core-7, 7 Institutional Area, Lodhi Road, South East Delhi- 110003
E-mail: env-mines@nml.co.in

Subject: **Pakri Barwadih Coal Mining Project (area 3319.42 Ha having capacity 18 MTPA) by M/s NTPC Mining Limited located at Villages: Barkagaon, Itij, Chiruadih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduari, Churchu, Carahara, Sonbarsa, Pakri – Barwadih; District: Hazaribagh; State: Jharkhand – Grant of Amendment in Environmental Clearance – regarding**

Sir/Madam,

This is with reference to your online application vide proposal No. IA/JH/CMIN/503899/2024 Dated 27.11.2024 along with CAF (Part A, B and C) seeking amendment in Environment Clearance accorded by the Ministry vide letter no. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 19.05.2009 and its subsequent amendment dated 30/10/2024, under the provisions of the EIA Notification, 2006 for the project mentioned above.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) EC Identification No.	EC24A0101JH5982710A
(ii) File No.	J-11015/692/2007-IA-II(M)
(iii) Clearance Type	Amendment in EC
(iv) Category	A
(v) Schedule No./ Project Activity	1(a) Mining of minerals
(vi) Sector	Coal Mining
(vii) Name of Project	Amendment in Environment Clearance (EC) of Pakri Barwadih Coal Mining Project, NTPC Mining Limited
(viii) Location of Project (District, State)	HAZARIBAGH, JHARKHAND
(ix) Issuing Authority	MoEF&CC
(x) EC Date	19/05/2009
(xii) Applicability of General Conditions	NO

(xiii) Status of implementation of the project

3. The proposal was considered by EAC (Coal) in its 19th meeting held during December 10-11th, 2024. The project activity is listed at schedule no. 1(a) - Mining of minerals under Category "A" of the schedule of the EIA Notification, 2006. The minutes of the meeting and all the project documents are available on PARIVESH portal which can be accessed at https://parivesh.nic.in.

4. The instant proposal is for seeking amendment in Environment Clearance granted to M/s NTPC Limited vide letter no. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 19.05.2009, later transferred to M/s NTPC Mining Limited vide letter no. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 02.05.2024 for Pakri Barwadih Coal Mining Project (area 3319.42 Ha having capacity 18 MTPA) located at Villages: Barkagaon, Itij, Chiruadih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduari, Churchu, Carahara, Sonbarsa, Pakri – Barwadih; District: Hazaribagh; State: Jharkhand.

5. Details of all the prior ECs including the EC for which amendment is sought are summarized as below:

S. No.	Details of Letter No.	Details of EC/Expansion EC/ Amendment in EC/ Validity extension/ Transfer of EC	Capacity (MTPA)	Area (Ha)	Date of Issuance	Status of Implementation
1	J-11015/692/2007-IA.II(M)	**Fresh EC**	15 MTPA	3319.42	19.05.2009	Production of 15 MTPA achieved during the year 2023-2024
2	-do-	**Amendment in EC** [Road transportation granted till 28.06.2018]	15 MTPA	3319.42	29.06.2016	Implemented
3	-do-	**Amendment in EC** [Specific Condition nos (iii), (vi) & (ix) and General Condition nos (ix) & (xiii)]	15 MTPA	3319.42	07.12.2017	Being implemented
4	-do-	**Amendment in EC** [Road transportation granted till 28.06.2020]	15 MTPA	3319.42 Ha	14.08.2018	Implemented
5	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 28.06.2022 and auto extended to 28.06.2023 in line with Covid notification of MOEF&CC]	15 MTPA	3319.42 Ha	10.11.2020	Implemented
6	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.10.2023]	15 MTPA	3319.42 Ha	16.08.2023	Implemented
7	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.01.2024]	15 MTPA	3319.42 Ha	09.11.2023	Implemented
8	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.07.2024]	15 MTPA	3319.42 Ha	15.01.2024	Implemented
9	-do-	**Peak Rated Capacity (PRC) Enhancement (1st phase 20%) as per MoEF&CC guidelines dated 11/04/2022**	18 MTPA	3319.42 Ha	06.03.2024	Being implemented
10	-do-	**Transfer of EC**			02.05.2024	Transfer from NTPC

		[Transfer from NTPC Ltd to NTPC Mining Ltd]				Ltd to NTPC Mining Ltd
11	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.10.2024]			16.07.2024	Implemented
12	-do-	**Amendment in EC** [Road transport granted till 31.12.2024 only for 15 MTPA]			30.10.2024	Being Implemented

6. The PP has sought amendment in Environmental Clearance Letter dated 19.05.2009 in EC Specific Condition no. 2A(ix), seeking further amendment for extension of timeline regarding transportation of 4.5 MTPA coal by road using State Highway/ Service Road till 31.03.2025 and thereafter 3 MTPA coal by road using State Highway/ Service Road till 31.03.2026 to Bandag railway siding.

The amendment sought along with the justification furnished by the PP is as below:

Specific/General Condition No.	Details of Conditions as per EC	Amendment Sought	Justification
Specific Condition No.- 2A (ix) of EC dated 19.05.2009 and latest amended vide letter dated 30.10.2024	*The PP is permitted to use Service Road/ State Highway for transportation of **15 MTPA of Coal to Banadag railway siding till 31.12.2024** adopting all the mitigative measure to control dust pollution.*	***Mineral Transportation from CHP to Railway Siding shall be done by closed belt conveyor and Rapid Loading System. PP is permitted to use Service Road/ State Highways for transportation of 4.5 MTPA coal from 01.01.2025 till 31.03.2025 and thereafter 3.0 MTPA coal by road till 31.03.2026 to Banadag railway siding adopting all mitigative measure to control dust pollution."***	**Part II**: 3. Hon'ble Supreme Court had directed vide its order dated 29.01.2024 in Civil Appeal No 6249/2021 to complete the CHP system including RLS by 31.12.2024. In this regard it is pertinent to mention that RLS system which consists of two streams, stream 1 has been commissioned on 15.11.2024 and the stream 2 will be ready by 15.12.2024 in compliance of the Hon'ble Supreme Court direction. 4. The construction of siding being done by railways, consists of seven nos. of rail tracks out of which 3 are ready, also, the electrification and signalling work is under progress. It is likely that yard augmentation work by railways shall be completed by 31.01.2025. After yard augmentation and RLS completion, it shall require three months of time (till 31.03.2025) to synchronize the system with railways which is knowns as "Integrated commissioning". In other words, it may take three months for both RLS streams to reach its rated capacity of 15 MT. 5. Also, it is important to mention that the present design capacity of the CHP & RLS System, is of 15 MT per annum. To enhance the capability of the present system upto 18 MTPA certain modifications and additional conveyor Strems are required for which the action has already been taken and shall be completed by 31.03.2026. 6. The total production/ dispatch target for FY 2024-25 from PBCMP is 18 MMT. For last quarter i.e. Q4 starting from 01.01.2025 till 31.03.2025 the total coal to be dispatch shall be 5.5 MMT to 6.0 MMT. 7. Assuming that it may take 3 more months for both the streams of RLS to reach its rated capacity (15 MMT), the maximum quantity which may be transported through RLS shall be 13.5 MMT resulting

			in a shortfall of 4.5 MMT in Q4 which needs to be transported through road. (3.0 MMT due to design limitation and 1.5 MMT for stabilisation). 8. For FY 2025-26 the shortfall of 3.0 MMT will be there due to design limitation of the present CHP the enhancement of same shall be completed by 31.03.2026. In view of above, it is submitted to kindly grant permission for transportation of the coal by road for 4.5 MTPA (3.0 MTPA beyond CHP design Capacity and 1.5 MTPA for stabilisation of RLS) from 01.01.2025 till 31.03.2025 and thereafter, 3.0 MTPA of coal by road till 31.03.2026.

7. **Certified Compliance Report and Action Taken thereof**: The PP submitted that CCR from Regional office (RO), Ranchi was received on 19.06.2024 vide letter no. 103-425/376 and PP submitted ATR on the same on 26.08.2024.

With respect to the Condition for which amendment is sought, RO has given its observations and has mentioned that, " *during inspection on 30.05.2024 it was observed that coal transportation is still being done by road from Pakri Barwadih coal mine project to Banadag railway siding. It is observed that rapid loading system of the conveyor system is under construction near Banadag railway siding. PP informed that now full efforts are being made to complete the same before 31.12.2024.*"

8. **Details of the Court Cases**: Following court cases are pending on the said project.

Case No.	Court	Brief	Next date of hearing	Decision of court and its compliance
WP (C) 5732/2016	HC of Jharkhand	Writ Petition filed by Bhartiya Suraj Dal against State of Jharkhand and others regarding pollution and diversion of forest land without obtaining the consent of Gram Sabhas under the FRA Act 2006.	Next hearing scheduled on 03.01.2025.	
WP (C) 4036/2021	HC of Jharkhand	Writ Petition has been filed by NTPC against the State of Jharkhand and others against demand of transit fee on 100 % coal production under Jharkhand Forest Produce Transit (Regulation of Transport) Rules 2020 issued by State of Jharkhand.	Listed for hearing in first week of February 2024. No date showing for now. Next date is not given.	
WP (C) 1759/2023	HC of Jharkhand	Writ Petition filed by NTPC against the State of Jharkhand and others to stay the operation, implementation and execution of the letter No. 43, dated 03.01.2023 of Divisional Forest Officer (West), Hazaribagh by which the State of Jharkhand has demanded the payment of Transit Fee for the second time on the same load by stating that NTPC is liable to generate the challan for the second time when there is a change of mode of transportation.	Next hearing date is not given	Hon'ble court vide order dated 06.09.2024 directed not to charge NTPC twice for the same forest produce on the change of mode of transportation for transportation of any forest produce as transit fee. Hon'ble Court has stayed the order till next date of hearing to be held on 21/02/24.
WP (C) 3256/2023	HC of Jharkhand	Writ Petition filed by NTPC against the State of Jharkhand and others		The Hon'ble High Court granted stay on DFO letter vide order

		regarding quashing the letter No. 3426, dated 23.06.2023 of Divisional Forest Officer (West), Hazaribagh by which Forest Deptt. has denied Coal Transportation by Road.		dated 30.06.2023.
WP (C) 3614/2023	HC of Jharkhand	PIL filled by Shri Mantu Soni against State of Jharkhand and Others regarding FC granted to Pakri Barwadih Coal Mining Project on forged document (Consent letter of Van Prabandhan Samittee).	Next hearing date is not given.	· CA filled by NTPC on 18.06.2024. · Rejoinder filled by applicant on 27.06.2024. · Supplementary Counter Affidavit filed by NTPC on 07.08.2024. · Reply of affidavit filed by applicant on 20.08.2024. · Last hearing conducted on 27.09.2024.
OA no 63/2023/EZ (158/2023/PB)	NGT, Kolkata	Filed by Shri Anup Kumar against State of Jharkhand and Others regarding illegal mining in Pakri Barwadih Coal Mining Project. Vide order dated 11.08.2023, NTPC and its MDO (TSMPL) has been made party by the Hon'ble court.	Next hearing is scheduled on 03.01.2025.	· Due to similar nature hearings are being held with Appeal No. 20/2023/EZ filled by NTPC Ltd. · Last hearing held on 12.11.2024. Case to be further heard on 03.01.2025.
Appeal No 20/2023	NGT, Kolkata	Appeal filed by NTPC against State of Jharkhand & Others to stay on DFO's demand letter for payment of Penal NPV with interest in line with MOEF&CC amendment letter dated 25.05.2023 for amendment of condition no-8 of FC.	Next hearing is scheduled on 03.01.2025.	· 1st hearing done on 01.08.2023. Hon'ble NGT stayed on DFO's Demand letter. · Last hearing held on 12.11.2024, stay continued till further order.
W.P.(PIL) 4358/2024	HC of Jharkhand	PIL filed by Shri Ravikant Singh Vs Union of India and others regarding Mining beyond lease and regarding FC granted to Pakri Barwadih Coal Mining Project on forged document (Consent letter of Van Prabandhan Samittee).	Next hearing date not given.	· First Hearing held on 28.08.2024. · CA filled by NTPC on 02.09.2024. · Last hearing held on 20.09.2024.

In addition to the above, the Hon'ble Supreme Court had directed vide its order dated 29.01.2024 in Civil Appeal No 6249/2021 to complete the CHP system including RLS by 31.12.2024. In compliance to the said order, PP informed that RLS system which consists of two streams, stream 1 has been commissioned on 15.11.2024 and the stream 2 will be ready by 15.12.2024 in compliance of the Hon'ble Supreme Court direction.

Observations and deliberation of the Committee

9. The Committee deliberated on various aspects of the proposal submitted and the presentation made by PP. After detailed deliberation, the Committee noted the following:

i. MoEF&CC has granted EC for the Pakri Barwadih Coal Mining Project of M/s NTPC Limited vide letter no. J-11015/692/2007-IA.II(M) dated 19.05.2009 for capacity of 15 MTPA in an area of 3319.42 Ha. Subsequently, various amendments for the same were issued vide letters dated 29.06.2016, 07.12.2017, 14.08.2018, 10.11.2020, 16.08.2023, 09.11.2023, 15.01.2024, 16.07.2024 and 30.10.2024.

ii. Further the Peak Rated Capacity (PRC) enhancement for the project was issued vide letter dated 06.03.2024 for the

capacity of 18 MTPA from 15 MTPA in the existing area of 3319.42 Ha and the same was transferred to M/s NTPC Mining Limited vide letter dated 02.05.2024. Subsequently, an amendment in condition pertaining to transportation of coal was again issued vide letter dated 30.10.2024.

iii. It is observed by the EAC that the project involves total 643.9 Ha of forestland. Stage – II FC has been obtained by the proponent vide letter dated 17.09.2010.

iv. The above projects have been implemented and are already under operation.

v. Specific Condition no. – 2A (ix) of EC stipulated that the coal was to be transported from Coal Handling Plant (CHP) to railway siding by closed conveyor belt. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System. The timeline for this condition was extended till 31.12.2024, vide various amendments as stated above, subject to the order of Hon'ble Supreme Court w.r.t. Misc. Appeal (MA-001824 dated 18.08.2023) in the matter of Civil Appeal no 6249/2022 (NTPC vs Tripuri Singh Ors) filed by the Project Proponent. Now, the PP has again submitted the proposal for amendment in Specific Condition no. 2A(ix) of EC dated 19.05.2009 (last amended vide EC dated 30.10.2024).

vi. The PP submitted that the conveyor belt being constructed is only for the capacity of 15 MTPA and for another 3 MTPA (i.e., 18 MTPA), engineering designing had to be modified to make the changes in the conveyor and siding capacity for 18 MTPA. PP submitted that actions for the same has already been taken and same is proposed to be completed by 31.03.2026.

vii. Committee was informed that the total production target for FY 2024-25 from PBCMP is 18 MTPA. For last quarter i.e. Q4 starting from 01.01.2025 till 31.03.2025 the total coal to be dispatched shall be between 5.5 MTPA to 6 MTPA. Assuming that it may take 3 more months for both the streams of RLS to reach its rated capacity (15 MTPA), the maximum quantity which may be transported through RLS shall be 13.5 MTPA resulting in a shortfall of 4.5 MTPA in Q4 which needs to be transported through road. (3 MTPA due to design limitation and 1.5 MTPA for stabilisation).

viii. PP presented a drone vide to the Committee, of undergoing construction of CHP and Silo. Since, that area has a frequent movement of elephants, the height of conveyor is planned such that, it will give safe passage to elephants.

ix. Committee deliberated on the present scenario of coal transportation and was informed by the proponent, that presently the transportation of coal from mine pit to crusher installed at mine pit head is being done by the mine trucks for the entire quantity of coal being produced and the same is proposed to be done throughout the mine life. Further, some quantity of coal, from crusher installed at mine pit head to stacker/reclaimer, is being transported through closed belt conveyor of 8 km which is within the mine boundary and this will be further transported to Banadag Railway siding through road at a distance of 23 km. And rest of the quantity of coal is directly being transported from crusher to Banadag Railway Siding by road at a distance of 30 km.

x. The Committee deliberated on the actions taken by the PP on the recommendations of the EAC Sub-Committee made during the site visit 20-26th November, 2024. On the recommendation of the sub-committee, the PP has done the mapping of grassing and plantation on 30.11.2024, generated carbon footprint data for PBCMP, display boards highlighting the biodiversity initiatives are being installed, green agronets are being installed in the area of nearby villages, bidding for procurement of CAAQMS has been started and equipment for water testing lab has been procured and the same is under installation.

xi. The Committee opined that out of the 2 nos of CAAQMS being procured, 1 shall be installed in the core zone and another shall be installed in the habitation around the ML area, such as Sirka Village and the data of the same shall be displayed in HoP and EMG office, so that effective monitoring and corrective actions may be taken time to time.

xii. The Committee opined that the Mobile Environment Monitoring Van may be procured and used in the mines.

xiii. The Committee deliberated on the use of e-dumpers being explored and observed that the PP has converted all the diesel operated HEMMs into electrical HEMMs and feasibility of using e-dumper is being tested for now in PBCMP.

xiv. The Committee also deliberated on the plantation activities being done by the PP. Committee is of the opinion that

avenue plantation shall be instantly started and gap plantation on the OB dumps shall be done.

xv. The Committee also enquired about the status of court cases pending on the project. The PP submitted that there are total 6 nos. of cases pending at Hon'ble High Court of Jharkhand and total 2 nos. of cases pending at Hon'ble NGT (EZ), Kolkata. PP also displayed a copy of the Court Order during the presentation of the Court case in the matter of Misc. Appeal No. 1824 of 2023 in Civil Appeal No. 6249 of 2021 (NTPC Ltd v. Tripurari Singh and Others) regarding the extension of the timeline for completion of the closed conveyor belt system. PP submitted that the Hon'ble Supreme Court has extended the timeline for completion of the belt conveyor system till 31.12.2024, vide its order dated 29.01.2024 and the matter was disposed of.

xvi. The committee noted that Pakri Barwadih Coal Mining Project does not fall under critically polluted area and severely polluted area as per CEPI Assessment 2018.

xvii. The Committee took into cognizance that the existing EC of 18 MTPA was accorded for 20% expansion under para 7(ii) of EIA Notification, 2006 as per Ministry's OM dated 11.04.2022. The committee sought clarification regarding requirement of enhanced capacity of CHP and Silo, in case the PP seeks further expansion for the said project in future. The PP submitted that due to huge habitation in that area, it is not feasible for the proponent to go beyond 18 MTPA and PP informed that no further expansion is envisaged.

xviii. Vide Ministry's order dated 18/12/2024, a site visit was conducted by Sub-committee of EAC for Pakri Barwadih Coal Mining Project and submitted their observations/recommendations. Accordingly, M/s NML shall address and comply the following recommendations submitted by the Sub-committee.

a) There are sufficient spaces available at different sites in the mine lease area which needs immediate plantation. The mapping of the Pakri Barwadih mine for grassing and plantation shall be carried out on the stabilized OB and berms. The proponent is instructed to prepare time bound comprehensive plantation plan with native species for protection of the ecology of the surrounding area and post-mining ecological restoration plan. The proponent should submit the detailed plan in tabular format (year-wise for life of mine) for afforestation and green belt development in and around the mining lease area. The proponent should submit the number of saplings to be planted, area to be covered under afforestation and green belt, location of plantation, target for survival rate and budget earmarked for the afforestation & green belt development. In addition to this, the proponent should show on a surface plan (5-year interval for life of mine) of suitable scale the area to be covered under afforestation & green belt clearly mentioning the latitude and longitude of the area to be covered during each 5 years. The capital and recurring expenditure to be incurred needs to be submitted. Plantation plan should be prepared in such a way that 80% of the plantation to be carried out in first 5 years and for the remaining years the proposal for gap filling. The seedling of height not less than 2 meters to be selected and accordingly cost of plantation needs to be decided. In addition to this, plantation in the safety zone at lease boundary the plantation should be planned in such a way that it should be completed within 2 years only. Grassing/plantation as per the above mapping shall be started in February, 2025.

b) The biodiversity initiatives carried in and around the mine lease area shall be highlighted through display boards in the suitable places outside the mine lease area.

c) The proponent shall generate the carbon footprint data for the entire mine lease area.

d) The proponent shall prepare time bound comprehensive action plan for the diversion of nalla(s) from the mine lease area.

e) The proponent shall take adequate precautionary measures as per the MoEFCC OM dated 29.10.2014 to minimize the impact of mining activity on habitations.

f) Comprehensive risk management plan along with mitigation measures for fire events in the coal yards/dumps shall be prepared and complied with.

g) The environment laboratory shall be upgraded with all sophisticated instruments.

h) ETP in the mine area shall be upgraded with online effluent quality monitoring system.

i) No any meteorological data / environmental data recording instruments have been seen at and around mining site. Only one CAAQMS has been installed in the city site. More number of CAAQMS at different sites needs to be installed.

Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) to monitor ambient air quality within the mining lease area shall be installed and connected with the servers of CPCB/SPCB. The proponent shall calibrate the instrument timely and display the monitored data on the digital board at Hop and in the EMG office for effective monitoring and corrective action.

Recommendations of the Committee

10. After deliberations, the Committee **recommended** the proposal for amendment in EC granted vide file no. J-11015/692/2007-IA.II(M) dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024 as detailed below subject to stipulation of additional specific conditions (**Annexure-1**). Other terms and conditions prescribed in EC dated 19.05.2009 and its subsequent amendment shall remain unchanged:

Reference in EC letter dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024	Description as per approved EC & its subsequent amendment dated 30/10/2024	Amendment sought in EC	Recommendation of EAC
Specific Condition No.- 2A (ix)	*The PP is permitted to use Service Road/ State Highway for transportation of **15 MTPA of Coal to Banadag railway siding till 31.12.2024** adopting all the mitigative measure to control dust pollution.*	Mineral Transportation from CHP to Railway Siding shall be done by closed belt conveyor and Rapid Loading System. PP is permitted to use Service Road/State Highways for transportation of 4.5 MMT coal from 01.01.2025 till 31.03.2025 and thereafter 3.0 MMT coal by road till 31.03.2026 to Banadag railway siding adopting all mitigative measure to control dust pollution."	**Agreed** With regard to the changes in specific condition 2A(ix), Committee recommended to amend specific condition 2A(ix) as follows: *"The PP is permitted to use service road/ state highway for transportation of 4.5 MTPA of coal to Banadag Railway Siding till 31.03.2025 only. Thereafter, only 3 MTPA of coal is permitted to transport via service road/ state highway till 31.03.2026 adopting all mitigative measures to control dust pollution. No road transportation of coal will be permitted beyond 31.03.2026."*

Decision of MoEF&CC

11. The undersigned is directed to inform that Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the proposal in accordance with the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and after accepting the recommendations of the Expert Appraisal Committee (Coal) hereby decided for grant of amendment in the EC dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024; as detailed in para 10 above subject to the compliance of the additional terms & conditions / specific conditions at **Annexure-I**.

12. All other terms and conditions mentioned in the Environment Clearance letter no. J-11015/692/2007-IA.II(M) dated 19.05.2009 & its subsequent amendment dated 30/10/2024 shall remain unchanged.

13. The project proponent shall obtain fresh Environment Clearance in case of change in scope of the project, if any.

14. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Sundar Ramanathan)
Scientist 'F'
Tel: 011- 20819378
Email- r.sundar@nic.in

Copy To

1. The Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Secretary, Department of Environment & Forests, Government of Jharkhand, Secretariat, Ranchi.
3. Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, 2nd Floor, Headquarter- Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand – 834 002.
4. The Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board, TA building, HEC complex, PO Dhurwa, Ranchi.
5. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi – 32.
6. The Chairman, Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources, Curzon Road Barracks, A-2, W-3 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi
7. The Regional Director, Central Ground Water Board, Mid-Eastern Region, 6th& 7th Floor, Lok Nayak Jai Prakash Bhawan, Frazer Road, Dak Banglow, Patna- 800011, Bihar.
8. The District Collector, Hazaribagh, Government of Jharkhand.
9. PARIVESH Portal.

Annexure 1

Specific EC Conditions for (Mining Of Minerals)

1. Additional Specific Conditions:

S. No	EC Conditions
1.1	1 nos of CAAQMS must be installed in the core zone and 1 nos of CAAQMS must be installed in the Sirka Village in consultation with JSPCB within 6 months from the date of grant of EC amendment.
1.2	A full-fledged Environment Laboratory must be established by 30.06.2025, which should cater the needs of all three mines of NTPC Mining Limited, i.e., Pakri Barwadih Coal Mining Project, Kerandari Coal Mining Project and Chatti Bariatu Coal Mining Project.
1.3	Avenue plantation shall be instantly started all along the right of way of closed belt conveyor and silos.
1.4	All the recommendations made by the site visit report of the sub-committee held on 20-26th November, 2024 shall be complied with and the compliance status in this regard shall be submitted to concerned Regional Office of MoEF&CC.
1.5	Watershed management plan for Khorra Nallah and Pakwa Nallah exist within the ML area shall be developed and implemented

S. No	EC Conditions
1.6	Carbon emissions need to be assessed and brief plan for carbon emission mitigation shall be submitted by the PP.

Signed by Sundar Ramanathan
Date: 02-01-2025 10:32:39
Reason: Verified and signed

(अनुलग्नक 04)

पृच्छा संख्या–1 का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार वैसी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू कर लिया गया है की विवरणी निम्नवत् है :–

i. **मेसर्स एन0एम0डी0सी0 लिमिटेड (पूर्व आवंटी मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड के टोकीसूद नार्थ सब ब्लॉक) 374.87 हे0** :– वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.2011 द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3145 दिनांक 09.07.2014 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि को विमुक्त किया जा चुका है। जबकि स्टेज–II के शर्त संख्या–09 एवं स्टेज–I के शर्त संख्या–14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को Conservation Plan का कार्यान्वयन करना था जो अभी तक नहीं हुआ है।

ii. **एन0टी0पी0सी0 पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0)** :– वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज–II 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या– 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।

iii. **चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत मगध ओ0सी0पी0 परियोजना (96.72 हे0)** :– इस परियोजना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2010 से अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है तथा राज्य सरकार के पत्रांक 3276 दिनांक 22.06.2015 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि विमुक्त की गई है। इस परियोजना के शर्त संख्या–18 "The user agency to bear the cost of implementation of conservation plan to be prepared in consultation with the CWLW of the State for the Hazaribagh National Park and its buffer zone adjoining CCL mining zone." में उल्लेखित है। उक्त शर्त का अनुपालन खनन कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद लंबित था। जब सी0सी0एल0 द्वारा मगध ओ0सी0पी0 के नयी परियोजना 192.36 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई जिसमें तीन बिन्दु मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 के WLMP से संबंधित था। तब जाकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर समर्पित की गई जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या– 39, ज्ञापांक 1473 दिनांक 29.11.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि खनन कार्य 2016 से ही जारी है।

उपरोक्त अनुभव के आधार पर यह Site Inspection Report में उल्लेख किया गया है। क्योंकि Mining Start हो जाने में वन्यप्राणियों पर दुष्प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है एवं Soil Erosion भी होने लगता है। विलम्ब से Wildlife Plan/CAT Plan के लागू होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी के मद्देनजर यह मंतव्य दिया गया है कि Mining के साथ Wildlife Plan/CAT Plan का कार्य भी प्रारम्भ करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

(अनुलग्नक 05)

दैनिक भास्कर

हजारीबाग 01-11-2022

बड़कागांव में हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, जाम

बड़कागांव | बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास हाइवा ने बाइक सवार युवक 40 वर्षीय राम कुमार महतो (पिता लाल देव महतो) को अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक बड़कागांव पश्चिमी पंचायत विधायक मोहल्ला का रहने वाला था। बड़कागांव पश्चिमी पंचायत मुखिया रंजीत कुमार ने बताया कि रामकुमार अपने बेटे के साथ अपने रिश्तेदार हजारीबाग के यहां से छठ पूजा कर घर वापस आ रहा था। परंतु तेज रफ्तार में आ रही त्रिवेणी सैनिक का हाइवा ने धक्का मार दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हाइवा धक्का मारकर फरार हो गया। बैचिंग प्लांट की तरफ घुस गया। घटना सोमवार रात्रि 8:00 बजे की है। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आवागमन पूर्ण रूप से बाधित कर दिया है। जानकारी मिलते ही बड़कागांव थाना प्रभारी विनोद तिर्की एवं डाड़ी कला थाना प्रभारी मणिलाल सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 02-11-2022

मृतक के परिजन को ₹6 लाख और नौकरी देगी त्रिवेणी सैनिक कंपनी

कंपनी के हाइवा की चपेट में आने से हुई थी रामकुमार महतो की मौत

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

सोमवार देर शाम हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास त्रिवेणी सैनिक कंपनी के हाइवा की चपेट में आने से विधायक मोहल्ला बड़कागांव निवासी 40 वर्षीय राम कुमार महतो के घटनास्थल पर ही मौत हो जाने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 घंटा सड़क जाम रखा। देर रात लगभग 1:00 बजे पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, पश्चिमी पंचायत मुखिया सह संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम, पूर्वी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार साव, सांसद प्रतिनिधि बालेश्वर कुमार, कंपनी के अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में समझौते के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया। इस दौरान हाईवा से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग कार्य को 19 घंटा तक बंद रहा, एनटीपीसी साइट कार्यालय सिकरी में जन प्रतिनिधि मंडल एवं कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद ट्रांसपोर्ट इन कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कंपनी के अधिकारी जनरल मैनेजर सयक पाल ने बताया कि मुआवजा के तौर पर मृतक के परिजन को 6 लाख का चेक बुधवार को दे दिया जाएगा एवं उनके परिजन के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

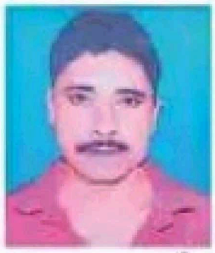

रामकुमार महतो।

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 09-02-2023

कोयला चुनने गई महिला की ओबी से दबकर मौत, मुआवजे के लिए 9 घंटे सड़क जाम किया

त्रिवेणी कंपनी मृतक के परिवार को 6 लाख और नौकरी देगी, ग्रामीणों ने हटाया जाम

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

जलावन के लिए त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग डंप एरिया सोनबरसा में बुधवार सुबह 4:00 बजे कोयला चुनने गई बड़कागांव बसरिया मुहल्ला निवासी 37 वर्षीय महिला सुनीता देवी (पति भुनेश्वर प्रजापति) की ओबी से दबने के कारण मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को लेकर बड़कागांव-हजारीबाग मुख्य पथ को 13 माईल के पास सड़क जाम कर मुआवजे व रोजगार की मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार सुनीता अपने पति भुनेश्वर के साथ घर से सुबह 4:00 बजे त्रिवेणी सैनिक डंपिंग एरिया में कोयला चुनने के लिए सोनबरसा गांव गई थी। चश्मदीद बताते हैं कि सुनीता ऊपर चढ़कर कोयला चुनने लगी और इसी दौरान बड़ा पत्थर का कुछ हिस्सा खिसक गया। उसके ऊपर आ गिरा और दब गई। ग्रामीणों के प्रयास से बाहर निकाला गया परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक का परिवार अत्यंत ही गरीब है। वे अपने पीछे पति समेत तीन पुत्री एवं एक पुत्र छोड़ गई। सूचना पाकर बड़कागांव थाना के एसआई अभय कुमार व प्रशांत कुमार दलबल के साथ स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शांति व्यवस्था में जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम, पंचायत समिति सदस्य रितेश ठाकुर, मुखिया तकरिमुल्लाह खान, सुरेश राणा व अन्य प्रबुद्ध लोग लगे रहे। मृतक के परिजन एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और नौकरी को लेकर सुबह 6:00 बजे से तकरीबन 9 घंटा तक सड़क जाम रखा गया। जिसके कारण भारी संख्या में वाहन रोड के किनारे लगे हुए देखे गए। विधायक अंबा प्रसाद के प्रयास से कंपनी द्वारा मृतक के परिजन को ₹6 लाख एवं एक नौकरी देने की शर्त पर जाम हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया।

एक महीना से सोनबरसा में ओबी का काम बंद है

मामले को लेकर त्रिवेणी सैनिक के अधिकारियों का कहना है कि एक महीना से सोनबरसा में ओबी डंपिंग का काम बंद है। कई बार ग्रामीणों को कोयला चुनने से मना किया गया है। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। जागरूकता के लिए एनटीपीसी के द्वारा पंफलेट भी बंटवाया गया है, ग्रामीणों को जागरूक होने की जरूरत है।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक 1163 दिनांक 13/3/2020

(अनुलग्नक 06)

सेवा में,

श्री अजय कुमार निराला,
ग्राम + पो० + थाना–बरही,
जिला–हजारीबाग।
पिन– 825330
मो० – 9431558802, 0709802131

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदन–सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2020।

महाशय,

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरणी निम्नवत् है:–

प्रश्न	उत्तर
(1) हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अंतर्गत सदर, बड़कागांव, बरही एवं चौपारण वन प्रक्षेत्र अंतर्गत कितने हेक्टेयर में वन भूमि एवं वन अवस्थित है।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार वन भूमि का रकबा 137993.74 हे० है।
(2) उक्त वन क्षेत्रों में कितने प्रकार के वन्य जीव पाये जाते हैं और विवरण करते हैं।	हाथी/नीलगाय/सुअर/लकड़बघ्घा/हिरण/सियार/खरगोश/बन्दर इत्यादि पाये जाते हैं।
(3) उक्त वन क्षेत्रों में अब से पिछले 10 सालों में वन्य जीवों से कितने लोगों को जान–माल, फसल का नुकसान हुआ है और प्रभावित व्यक्तियों को विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया गया है।	पिछले 10 वर्षों में जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति से संबंधित अबतक 1422 (एक हजार चार सौ बाईस) मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया गया है।
(4) सदर, बड़कागांव, बरही एवं चौपारण वन प्रक्षेत्र अंतर्गत पिछले 10 सालों में कितने और किस जाति के वन्य प्राणी को पकड़कर सुरक्षित नेशनल पार्क किस जैविक उद्यान में पहुंचाया गया है।	घायल अवस्था में पाये जाने वाले वन्य प्राणी को समुचित ईलाज कराने के बाद उनके प्राकृतिक प्रवास स्थान पर छोड़ दिया जाता है।

आपका विश्वासी,
(हस्ताक्षर) 13/3/20
जन–सूचना–पदाधिकारी
–सह– सहायक वन संरक्षक
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

3121/m
13/03/20

Ajay kr. Nirala doc

(अनुलग्नक 07)

कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmal.com & dfo-hazaribaghwest@gov.

पत्रांक 5813 दिनांक 11/10/23

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,
सी0सी0एल0, अम्रपाली–चन्द्रगुप्त एरिया,
आकाशदीप , मेन रोड, डकरा,
जिला– राँची, (झारखण्ड), 829201

विषयः– हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखण्ड अन्तर्गत चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना निर्माण हेतु हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 298.42 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– परियोजना पदाधिकारी, चन्द्रगुप्ता खुली खदान परियोजना आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र सी0सी0एल0 का पत्रांक 187 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 191 दिनांक 05.10.2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में भ सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-24/2023-FC दि 22.09.2023 द्वारा पन्द्रह विन्दुओं पर पृच्छा की गई है। जिसमें पृच्छा के कम संख्या Viii. & Xiv के संदर्भ हाथियों का मृत्यु तथा हाथियों के द्वारा क्षति/मुआवजा से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आव कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन

PROJECT OFFICER
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

10/10/23
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 (अबतक) में जंगली हाथियों द्वारा मृत एवं घायल व्यक्तियों से संबंधित मुआवजा राशि का भुगतान की विवरणी

क्र. सं.	विवरण	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24		कुल	
		मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि	मामला	राशि
1	मृत्यु	2	800000	8	3200000	9	3600000.00	5	2000000.00	1	400000	25	10000000.00
2	घायल	1	100000			3	130000.00	2	200000.00	1	100000	7	530000.00
	कुल	3	900000.00	8	3200000.00	12	3730000.00	7	2200000.00	2	500000.00	32	10530000.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल
10/10/23

PROJECT OFFICER
CHANDRAGUPT PROJECT
AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 (अबतक) में जंगली हाथियों द्वारा फसल, भंडारित अनाज, मकान क्षति एवं पशु क्षति से संबंधित मुआवजा राशि का भुगतान की विवरणी

क्र. सं.	विवरण	2019-20				2020-21				2021-22				2022-23				2023-24				कुल			
		मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि	मामला	हे0	क्विंटल	राशि
1	फसल क्षति	106	16.86		337524	665	80.887	0	1617728.00	273	39.596	557120	557120.00	371	65.616		1312320.00	145	25.804		516080.00	1560	228.8	557120	4340772.00
2	भंडारित अनाज	19		43.5	69600	105		265.6	424960.00	76		133.75	214000.00	62		135	215984.00	28		40.60	64960.00	290	0	618.44	989504.00
3	मकान क्षति	35			590000	198			4380000.00	153			2230000.00	144			2220000.00	46			690000.00	576	0	0	10110000.00
4	पशु क्षति	2			6000	13			180000.00	2		18000	18000.00	3			45000.00	3			65000.00	23	0	18000	314000.00
	कुल	162	16.86	43.5	1003124	981	80.887	265.6	6602688	504	39.596	575253.75	3019120	580	65.616	135	3793304	222	25.804	40.6	1336040.00	2449	228.8	575738	15754276.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल
10/10/23

PROJECT OFFICER
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
PIPARWAR-CHANDRAGUPT AREA, CCL

विगत 5 (पाँच) वर्षों मे इस प्रमंडल मे मानव एवं हाथियों की मृत्यु की विवरण।

क्रम संख्या	वर्ष	मानव की मृत्यु	हाथी की मृत्यु
1	2019–20	–	–
2	2020–21	–	–
3	2021–22	03	–
4	2022–23	01	–
5	2023–24	–	–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

14/10/23

(अनुलग्नक 08)

पृच्छा संख्या–1 का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार वैसी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू कर लिया गया है की विवरणी निम्नवत् है :–

i. **मेसर्स एन0एम0डी0सी0 लिमिटेड (पूर्व आवंटी मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड के टोकीसूद नार्थ सब ब्लॉक) 374.87 हे0** :– वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.2011 द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3145 दिनांक 09.07.2014 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि को विमुक्त किया जा चुका है। जबकि स्टेज–II के शर्त संख्या–09 एवं स्टेज–I के शर्त संख्या–14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को Conservation Plan का कार्यान्वयन करना था जो अभी तक नहीं हुआ है।

ii. **एन0टी0पी0सी0 पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0)** :– वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज–II 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या– 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।

iii. **चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत मगध ओ0सी0पी0 परियोजना (96.72 हे0)** :– इस परियोजना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2010 से अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है तथा राज्य सरकार के पत्रांक 3276 दिनांक 22.06.2015 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि विमुक्त की गई है। इस परियोजना के शर्त संख्या–18 "The user agency to bear the cost of implementation of conservation plan to be prepared in consultation with the CWLW of the State for the Hazaribagh National Park and its buffer zone adjoining CCL mining zone." में उल्लेखित है। उक्त शर्त का अनुपालन खनन कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद लंबित था। जब सी0सी0एल0 द्वारा मगध ओ0सी0पी0 के नयी परियोजना 192.36 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई जिसमें तीन बिन्दु मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 के WLMP से संबंधित था। तब जाकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर समर्पित की गई जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या– 39, ज्ञापांक 1473 दिनांक 29.11.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि खनन कार्य 2016 से ही जारी है।

उपरोक्त अनुभव के आधार पर यह Site Inspection Report में उल्लेख किया गया है। क्योंकि Mining Start हो जाने में वन्यप्राणियों पर दुष्प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है एवं Soil Erosion भी होने लगता है। विलम्ब से Wildlife Plan/CAT Plan के लागू होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी के मद्देनजर यह मंतव्य दिया गया है कि Mining के साथ Wildlife Plan/CAT Plan का कार्य भी प्रारम्भ करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

(अनुलग्नक 09)

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,
Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 1210 दिनांक : 23.6.2025

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रदत्त Stage-II के अनुपालन में Annual Compliance Report समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका ज्ञापांक 1874 दिनांक 05.04.2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से समर्पित भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक F.No.8-56/2009FC दिनांक 17.09.2010 द्वारा प्रदत्त Stage-II के Annual Compliance Report का अनुश्रवण आपके सहायक वन संरक्षक एवं प्रयोक्ता अभिकरण के समक्ष दिनांक 09.04.2025 को किया गया एवं निम्नांकित शर्तों का अनुपालन अपूर्ण/नहीं किये जाने की स्थिति पायी गई :–

शर्त संख्या	शर्त की विवरणी	Compliance की स्थिति
1	2	3
2.b.	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area shall be done at the project cost. Besides this, afforestation on degraded forest land, to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अबतक safety zone क्षेत्र का पूर्ण घेरान नहीं किया गया है बल्कि मात्र 6000 मी0 एक घेरान barbed wire से एक स्तरीय किया गया है। इसमें safety zone का द्विस्तरीय fencing किया जाना चाहिए। safety zone का द्विस्तरीय fencing नहीं होने के कारण इसका regeneration भी नहीं हो पा रहा है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लगभग 37000 पौधे safety zone में लगाने की बात कही गई परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से regeneration की स्थिति दयनीय प्रतीत होता है। प्रयोक्ता अभिकरण को संपूर्ण safety zone क्षेत्र में द्विस्तरीय Fencing Chain Link fence से करवाकर इस बरसात में इस क्षेत्र में गहन वृक्षारोपण हेतु निदेश दिया गया था। परन्तु इस संबंध में कोई अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अबतक नहीं भेजा गया। अतः आप स्वयं अथवा सहायक वन संरक्षक के माध्यम से इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर इस शर्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करायें।
(8.i)	*"The user agency shall restore and conserve the Khorra Nalla (west) and Pakwa Nalla (east) watersheds on priority basis under supervision of the forest department and expert hydrologists/agencies and develop their*	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा इसके अनुपालन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि इसका अनुपालन लंबित है। उन्हें पकवा एवं खोर्रा नाला के दोनो ओर 50 मी0 ग्रीन बेल्ट बनाने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिया जा चुका है।

	watershed status as per the Survey of India toposheet no. 73 E/1. A greenbelt of 50 meters on either side of both Khorra Nala and Pakwa Nalla shall be maintained"	आप द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर इस शर्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराये।
19	The user agency shall take up the de-silting of the village tanks within five kms area from the mine lease boundary as a corporate's social responsibility so as to mitigate the impact of siltation of such tanks, if any.	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई पूराने तालाबो का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबो के निर्माण की बात कही गई परन्तु उनके द्वारा कोई सूची प्रस्तुत नहीं किया गया। Disiltation किये गये तालाबो की सूची उनसे माँगा गया था जो अबतक अप्राप्त है। आप प्रयोक्ता अभिकरण से पूरी सूची प्राप्त कर उसका अपने स्तर से जाँचोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त लंबित अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित करवाये एवं नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझे।

आपकी विश्वासी,

23/06/25

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

हजारीबाग।

Speed Post/Online

F. No. IA-J-11014/95/2023-IA-I

(अनुलग्नक 10)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Compliance & Monitoring Division-I.A. Division)
*****

Indira Paryavaran Bhavan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110 003
Email: munna.shah@gov.in
Dated: 20th October, 2023

To,

Dy. General Manager (Envt. Mgmt.)
Pakri Barwadih, PB-NW & Badam CMP
NTPC Ltd.- Hazaribagh-825311
Jharkhand
Email id : NAVINKUMAR03@NTPC.CO.IN

Sub: Action Taken Report (ATR)- Non compliances observed with respect to the project on "PakriBarwadih Coal Mine Project (15 MTPA) of M/s National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) Located in villages Barkagaon, Itij, Chirudih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduri, Churchu, Carahara, Sonbarsa, PakriBarwadih, Chepa-Khurd, Deora-Kalan, Lakura, Langtu, Keri, Dadikalan, Tehsil- Baragaon, Dist- Hazaribagh, Jharkhand."- reg.

Ref: i. Ministry's EC letter No F. No. J-11015/692/2007-IA. II (M) dated 19/05/2009, and amendment letter No. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 29.06.2016, dated 07.12.2017, dated 14.08.2018, dated 10.11.2020.
ii. IRO, Jharkhand Monitoring Report No. 103-425/PT-1331 dated 14.08.2023.

Environmental Clearance (EC) was granted to M/s National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) located in villages Barkagaon, Itij, Chirudih, Urub, Chepa, Kalan, Nagri, Jugra, Sinduri, Churchu, Carahara, Sonbarsa, PakriBarwadih, Chepa-Khurd, Deora-Kalan, Lakura, Langtu, Keri, Dadikalan, Tehsil- Baragaon, Dist- Hazaribagh, Jharkhand, vide letter No F. No -11015/692/2007-IA. II (M) dated 19/05/2009, and amendment letter No. J-11015/692/2007-IA-II(M) dated 29.06.2016, dated 07.12.2017, dated 14.08.2018, dated 10.11.2020 subject to the implementation of the various conditions and environmental safeguards contained therein, and

2. The project was monitored for ascertaining compliance to the conditions stipulated in the aforesaid environmental clearance by the Regional Office of this Ministry at Ranchi on 12.06.2023 which has submitted its report to Ministry vide letter No. 103-425/PT-1331 dated 14.08.2023. **(Copy enclosed).**

Speed Post/Online

3. The monitoring report submitted for the project by RO, Ranchi has been examined in the Ministry and following are observed non-compliances with respect to said EC letter on the basis of review of IRO's report:

i. Violation/non-compliance of the provision of Forest Clearance Act. (Specific Condition: II)

ii. Necessary fund for construction of road upto the Monolith and park around to the state Govt. yet has not been released. (Specific Condition: III)

iii. Siltation ponds, gabions have not been constructed in South West direction, Siltation pond has not been properly maintained, grassing, vegetation, plantations has not been developed near Lathorwa nallah, gabions has not been developed in between slope and nallah, no embankment between dump D of eastern quarry and pakka nallah has been constructed (Specific Condition: IV)

iv. Catch drains and siltation ponds has not been constructed for other portion of top soil dump. (Specific Condition: V)

v. Grassing and vegetation on the slopes of the OB dump has not been developed properly also, the slope of the section has not been submitted. (Specific Condition: VI)

vi. Catch drains and siltation ponds at many places as specified by IRO has not been constructed and maintained. (Specific Condition: VII)

vii. Retaining wall at the toe of the OB dump has not constructed at many places as specified by IRO. (Specific Condition: VIII)

viii. 3-tier avenue plantation has not been developed as per the EC condition. Transportation of Coal has is not being done as per the EC conditions dust emission has not been controlled effectively (Specific Condition: IX)

ix. Inadequate Dust control system to control the dust emission. (Specific Condition: XII)

x. Development of Rainwater harvesting structure wherever feasible. (Specific condition: XIII)

xi. Maintenance of Oil & grease trap and operational status of STP. (Specific Condition: XV) (General condition; VII)

xii. Completion of Plantations in some portions (as specified by IRO) of OB dumps (Specific Condition: XVI)

xiii. Status and completion of R&R Plan (Specific Condition: XIX)

xiv. Implementation of the report of Department of Forestry, wildlife & Environmental Sciences, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh (Specific Condition: XXI)

xv. Date till which eastern quarry of the project was operational. (General Condition: I)

xvi. Installation of CAAQMS near Mining operations area in consultation with JSPCB officials. (General condition: III)

xvii. Fugitive dust emission from all sources has not been controlled properly. Water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, and dump truck has not been adequately maintained. (General Condition: IV)

xviii. Submit the details of proper collection and treatment of Industrial wastewater. (General Condition: VII)

xix. Details of whether funds earmarked for environmental protection measures have been kept in separate accounts. (General Condition: XII)

Uma Shah

Speed Post/Online

4. In view of the foregoing, the Project proponent (PP) is hereby directed to submit the clarification/Action Taken Report (ATR) for observed non-compliance within next 30 days from the date of issuance of this letter. It may be noted that, if no satisfactory reply is received within the prescribed time frame, the Ministry will be constrained to take necessary action as deemed fit and appropriate in the circumstances of the case which inter-alia include issuance of Show-Cause Notice under the provision of section (5) of the Environment (Protection) Act, 1986.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Munna Kumar Shah)
Scientist E

Copy to:

1. Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Env., Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Bungalow No. A-2, Shyamali Colony, Ranchi – 834002.
2. The Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board, T.A. Division Building (Ground Floor), HEC Campus, P.O. Dhurwa, Ranchi - 834004, Jharkhand.
3. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.
4. The Member Secretary, Coal Mining, Ministry of Env., Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003.

(Munna Kumar Shah)
Scientist E

(अनुलग्नक 11)

पत्र संख्या–सू०अ०को०–08 / 2025–2707 /
झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

दयानन्द कुमार,
सरकार के अवर सचिव–सह–
जन सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री मंटू सोनी उर्फ शनिकांत,
पिता–श्री राजेश कुमार,
पता–बड़कागांव, जिला–हजारीबाग,
झारखण्ड–पिन–825311।

राँची, दिनांक– 02/05/25 ई०।

विषय :– सूचनाधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके सूचना आवेदन दिनांक–09.01.2025 के संदर्भ में वांछित सूचना से संबंधित उपलब्ध सूचना सामग्री ***(विभागीय पत्र सं०–2508, दिनांक–24.04.2025)*** की छाया प्रति कुल–51 (इक्यावन) पृष्टो में संलग्न की जाती है।

कृपया सूचनार्थ।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के अवर सचिव
–सह–जन सूचना
पदाधिकारी।

पत्रांक 527 / अ०अ०
अपराध अनुसंधान विभाग

प्रेषक,

महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक – 19.11.24

विषय– आवेदक मंटु सोनी उर्फ शनिकान्त, सा० [illegible] जिला–हजारीबाग, द्वारा समर्पित आवेदन के जाँचोपरान्त आये [illegible] निरोधक ब्यूरो, से जाँच कराये जाने हेतु आदेश के संबंध [illegible]

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आवेदक मन्टु सोनी उर्फ शनिकान्त, सा0+थाना–बड़कागाँव, जिला–हजारीबाग द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड राँची के अपर पुलिस [illegible] पदाधिकारी से करायी गयी। जाँच पदाधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन से [illegible] होता है कि पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हजारीबाग, में बड़े [illegible] अवैध खनन और अतिक्रमण किया गया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उक्त एरिया में अवैध खनन कर कोयला की चोरी की जा रही होगी [illegible] सरकार को राजस्व का नुकसान एवं पर्यावरण तथा वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव [illegible] इसमें पश्चिमी प्रमण्डल आर.एन. मिश्रा के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण एन.टी.पी.सी एवं उसके [illegible] त्रिवेणी सैनिक माईनिंग प्रा. लिमिटेड के अधिकारी को लाभ पहुँचाने के लिए अपने [illegible] आदेशों का गलत व्याख्या तथ्यों को छुपाते हुए सरकार को रिपोर्ट भेजा गया। पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी आर. एन. मिश्रा के रिपोर्ट से सीधा लाभ एन.टी.पी.सी [illegible] त्रिवेणी सैनिक माईनिंग प्रा. लिमिटेड के अधिकारी को हुआ है। इसलिए पूरे [illegible] प्रमण्डल पदाधिकारी के साथ एन.टी.पी.सी. एवं उसके एम.डी.ओ. दोषी है। [illegible] को गुमराह करते हुए गलत रिपोर्ट भेजा गया है। स्थल निरीक्षण के [illegible] दुमुहानी नाला को अवैध खनन किया गया है, उसकी वन विभाग के [illegible] चौड़ाई 20 से 30 मीटर बताई गई है, लेकिन वर्तमान में दुमुहानी नाले को [illegible] जा रही है जिसमें उसकी चौडाई 4 से 5 मीटर कर दी गई है। [illegible] बहुत कम कर दिया गया है। जिससे [illegible]

है कि एस.डी.ओ. त्रिवेणी-सैनिक माईनिंग कंपनी के पदाधिकारी द्वारा निशार खान नामक व्यक्ति से शिकायतकर्ता मंटू सोनी एवं परिवार को [illegible] समझौता कराने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दोषियों के द्वारा जाँच एवं कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए कोई भी प्रयास किया जा सकता है। इसकी जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची से कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उक्त तथ्यों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची से जाँच कराये जाने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।

कृपया सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन्

19/XI

महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

1

पत्रांक—.......46......../

अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

अपर पुलिस अधीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

राँची, दिनांक.....08.../04/2024,

विषयः— **आवेदक मन्टु सोनी उर्फ शनिकान्त, सा. बड़कागांव, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग द्वारा अनुलग्नक सहित समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के सन्दर्भ में सादर सूचित करना है कि भवदीय के निर्देशानुसार आवेदक मन्टु सोनी उर्फ शनिकान्त, सा. बड़कागांव, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग द्वारा अनुलग्नक सहित समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच घटनास्थल पर पहुँचकर किया गया, जो निम्न प्रकार हैः—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का ज्ञापांक—1063 दिनाक 23.03.2022 एवं ज्ञापाक—1855 दिनाक 030.06.2022 के अवलोकन किया गया, जिसमें इनके द्वारा ज्ञापांक 1063 दिनांक—23.03.2022 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्राक—एफ०नं0—8—56/2009 एफ०सी० (पी०टी०) दिनांक—29.01.2019 द्वारा प्रदत्त स्टेज—2, के शर्त 08 के उल्लघंन के आलोक में झारखण्ड सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा का जवाब हेतु दिनांक—16.06.2020 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल द्वारा निरीक्षण में आवेदन में अंकित बिन्दुओं पर दोषी पाये गये व्यक्तियों यथाः—1. श्री प्रशान्त कश्यप, कार्यकारी निदेशक, 2. श्री विक्रम चन्द्र दुबे, अपर महाप्रबन्धक (खनन), 3. श्री रंजीत प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (खनन) तीनों पदाधिकारियों द्वारा एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना बड़कागांव, हजारीबाग—825311 पर वन संरक्षण अधिनियम—1980 के धारा 3ए एवं 3बी की कार्रवाई के पात्र बताया गया। जबकि ज्ञापांक—1855, दिनाक 03.06.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रसगाधीन पत्रांक एन०टी०पी०सी० कोयला खनन परियोजना हजारीबाग(पार्थ मजुमदार तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, एन०टी०पी०सी०) का पत्रांक—1040/पी०बी०/सी०एम०पी०/ ई०एम०जी०/2020/एफ—28/05, दिनाक 18.01.2022 तथा पत्राक—1040/ पी०बी०सी०एम०पी०/ ई०एम०जी०/2020/एफ—28/43,दिनाक—02.06.2022 एवं खनन परियोजना के प्रधान श्री प्रशान्त कश्यप कार्यकारी निर्देशक एन०टी०पी०सी० लिए पकरी बरवाडीह, कोयला खनन परियोजना बड़कागाव, हजारीबाग द्वारा पृच्छा के आलोक में समर्पित जवाब के बाद वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन सरक्षक को समर्पित समान विषय के दूसरे आवेदन ज्ञापांक स०—1855 में यह अंकित किये है कि यह बात सत्य है कि अपयोजनकों द्वारा भारत सरकार के पत्र एफ०नं0—08—56/2009 एफ०सी०, दिनाक—17.09.2010 द्वारा निर्गत

स्टेज 2, के शर्त्त सं0–08 का उल्लघन इस कार्य संबधित विभिन्न नियमो/अधिनियमों में समाविष्ट विरोधाभाषी तथ्यों के आलोक में हुआ है एवं किसी व्यक्ति विशेष को सीधे–सीधे जवाबदेह बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आवेदक द्वारा संलग्न वन प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी अपने जाँच प्रतिवेदन के पारा–2, में यह स्पष्ट किये है कि प्रयोक्ता एजेन्सी पर 37.2 हेक्टेयर में शर्त–08 का उल्लंघन करने के विरूद्ध एफ०सी०ए०सी०–3ए एवं 3बी के कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये विधानसभा झारखण्ड में उठाये गये प्रश्नों का झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा–3बी के आलोक में प्रतिष्ठान के प्रमुख Head Organisation को दोषी माना जाता है एवं कार्रवाई का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, परन्तु कार्रवाई संबंधी निर्णय यहाँ वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा ही ले लिया गया है। साथ ही तत्कालीन वन प्रमण्डल अपने दूसरे प्रतिवेदन झापाक–1063 में Project Monitoring and Planning के पत्राक–224 को बचाव के रूप में निर्गत अनुमति–4, का पालन का उल्लेख किये है अर्थात बिन्दु–4 के आधार पर किसी को दोषी नहीं बताया लेकिन इस पत्र में बिन्दु–1 एवं 2 में जो शर्त लगाया गया था उसे छिपा दिया गया। निसार खान पे० स्व० वाहिद खान, सा० गदोखर, थाना–कटकमसाण्डी, जिला–हजारीबाग द्वारा अपने लिखित बयान में यह बताया है कि अरविन्द देव, पे० स्व० तापेश्वर देव, भूतपूर्व मंत्री मो०–कालीबाडी रोड, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग जो बड़कागॉव के कोई कम्पनी (सैनिक त्रिवेणी) में अच्छे पद पर कार्यरत हैं द्वारा बताया गया कि मन्टु सोनी इन्हें परेशान कर रहा है तो वे समझौता कराने के उददेश्य से आवेदक मन्दु सौनी के मोबाईल पर बात किये थे। उक्त सभी तथ्य दर्शाता है कि तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल श्री आर०एन० मिश्रा द्वारा एफ०सी०एक्ट के स्टेज–2, के शर्त सं0–08 को उल्लघंन करने वाले व्यक्ति (1) श्री प्रशान्त कश्यप, कार्यकारी निदेशक (2) श्री विक्रम चन्द्र दुबे, अपर महाप्रबन्धक (खनन) (3) श्री रंजीत प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (खनन) को बचाने के लिये अपने पद का दुरूपयोग करते हुये गलत रूप से वन सरक्षक को आवेदन प्रस्तुत किये हैं।

उल्लेखनीय है कि संलग्न दस्तावेज का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी आर.एन. मिश्रा ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के अनुसार झापाक–1063 में Project Monitoring and Planning के पत्राक–224 को बचाव के रूप में निर्गत अनुमति–4, का हवाला देते हुए इसे सरकार का विरोधाभासी आदेश बताते हुए किसी को भी दोषी नहीं बताया है। परन्तु उसी पत्र में यह स्पष्ट शर्त सं. 1 एवं 2 में उल्लेखित था कि उपरोक्त आदेश तभी प्रभावी होगा जब भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमति मिल जाएगा। परन्तु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्टेज–2, के शर्तो में संशोधन की अनुमति नहीं मिली थी। इन बिन्दुओं को वन पदाधिकारी द्वारा जान बुझ कर छीपा देना जान प्रतीत होता है। इसके अलावे अम्बा प्रसाद द्वारा विधान सभा में दिनांक 20.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्प सूचि प्रश्न संख्या–20, के सवाल नम्बर–02, में सरकार द्वारा यह स्पष्ट लिखा गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 37.20 हेक्टेयर(100.00 एकड़) में अवैध खनन की पुष्टि हुई है एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित की धारा 3बी. के आलोक में प्रतिष्ठान द्वारा की गई

अपराध के लिए उक्त अवधि में प्रतिष्ठान के प्रमुख Head Organisation को माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि झारखण्ड सरकार द्वारा विधान सभा में दिया गया जबाब के विपरित, पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग आर0एन0 मिश्रा द्वारा आरोपियों के प्रभाव में आकर वरीय पदाधिकारियों को रिर्पोट भेजा गया था, जिससे अवैध खनन के आरोपियों को एफ.सी.एक्ट 1980 की धारा 3ए एवं 3बी. से बचाया जा सके।

इसके अलावे शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र के बिन्दु सं. 6, में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 06 जून 2022 को मेसर्स बलासोर अलॉयज लिमिटेड बनान ओडिशा राज्य IA NO 81251/2022, DAIRY NO 16747/2022 का आदेश पत्र संलग्न किया गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के आवेदन लम्बित है तो इसे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं माना जा सकता, अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना खुदाई की जाती है तो यह अवैध है। इस बिन्दु का स्पष्टीकरण जॉच अधिकारी अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित नहीं किया। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची के श्री संतोष तिवारी Dy. DGF, IRO Ranchi एवं सहायक वन महानिरीक्षक श्री शशि शंकर द्वारा एक जॉच रिपोर्ट भारत सरकार श्री चरणजीत सिंह वैज्ञानिक डी., एफ.सी. डिवीजन, को मिसिल सं. FP/JH/min/38798/2019/717 दिनांक 25.11.2022 को रिपोर्ट भेजा गया, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रयोक्ता अभिकरण एन.टी. पी.सी. के द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज–2, के शर्त सं. 8, का उलंधन करते हुए 156 हेक्टेयर एरिया लगभग 400 एकड़ एरिया में अवैध खनन–अतिक्रमण किया गया है, जो पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा बनाये गए रिपोर्ट से चार गुना ज्यादा है। (Annexure संलग्न है)

उपरोक्त सभी तथ्यों के अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवैध खनन और अतिक्रमण किया गया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उक्त एरिया में अवैध खनन कर कोयला का खनन की चोरी की जा रही होगी, जिससे झारखण्ड सरकार को राजस्व का नुकसान एवं पर्यावरण एवं वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसमें पश्चिमी प्रमण्डल आर.एन. मिश्रा के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण एन.टी.पी. सी एवं उसके एम.डी.ओ. त्रिवेणी–सैनिक माईनिंग प्रा. लिमिटेड के अधिकारी को लाभ पहुँचाने के लिए अपने रिपोर्ट में सरकार के शर्तो एवं आदेशों का गलत व्याख्या तथ्यों को छुपाते हुए सरकार को रिपोर्ट भेजा गया। पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी आर. एन. मिश्रा के रिपोर्ट से सीधा लाभ एन.टी.पी.सी एवं उसके एम.डी.ओ. त्रिवेणी–सैनिक माईनिंग प्रा. लिमिटेड के अधिकारी को हुआ है। इसलिए पूरे प्रकरण में पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी के साथ एन.टी. पी.सी. एवं उसके एम.डी.ओ. दोषी है। इन तीनों के मिलीभगत से सरकार को गुमराह करते हुए गलत रिपोर्ट भेजा गया है। **स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिस दुमुहानी नाला को अवैध खनन किया गया है, उसकी वन विभाग के जॉच रिपोर्ट में औसत चौड़ाई 20 से 30 मीटर बताई गई है, लेकिन वर्तमान में दुमुहानी नाले को डाईवर्ट करने का प्रकिया की जा रही है, जिसमें उसकी चौड़ाई 4 से 5 मीटर कर दी गई है। इस तरह उसके मूल आकार से बहुत कम कर दिया गया है। जिससे उसके मूल रूप को बचाना सम्भव नहीं है।** इस दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि एम.डी.ओ. त्रिवेणी–सैनिक माईनिंग कम्पनी के ए.जी.एम. अरविन्द देव द्वारा निशार खान नामक व्यक्ति से शिकायतकर्ता मंटू सोनी उर्फ शनिकान्त को प्रभावित कर समझौता कराने का प्रयास किया गया

है, जिसके कारण इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दोषियों के द्वारा जॉच एवं कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए कोई भी प्रयत्न किया जा सकता है। इसलिए सरकार के स्तर से उच्च–स्तरीय जॉच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

08/04/24

(दीपक कुमार)
अपर पुलिस अधीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

English Translation of Hindi Rejoinder dated 15.09.2025 page 223 - 265

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

Original Application No.107/2025/EZ

(Earlier O.A. No.206/2025/PB)

Mantu Soni..... Applicant

Vs.

State of Jharkhand.....Respondent

Annexure

Sl. No.	Particulars	Encloser	Page No.
1.	Respondent 03, 04 & 06	Reply	1-43
2.	Annexure - 01	Reply Jharkhand Legislative Assembly	44
3.	Annexure - 01A	office memorandum (EC)	45
4.	Annexure - 01B	Information related to non-availability of record of transportation by road	46
5.	Annexure - 01C	F.C Condition 9 Violation Report	47-58
6.	Annexure - 01D	Interim Inquiry Report	59-61
7.	Annexure - 02	List of wildlife in the area	62-68
8.	Annexure - 02A	Forest Clearance Stage 2 (FC)	69-71
9.	Annexure - 02B	Environmental Clearance (EC)	72-77
10.	Annexure - 03	Supreme Court Order C.A. 6249/2021	78-79
11.	Annexure - 03A	Supreme Court Order Miscellaneous Application No. 1824/2023	80-84

12.	Annexure - 03B	Environmental Clearance (EC) 10th Amendment	85-94
13.	Annexure - 04	Wildlife Management Report in respect of Respondent 04	95
14.	Annexure - 05	NTPC Transportation/Death by OB Paper Cutting	96-98
15.	Annexure - 06	wildlife loss data	99
16.	Annexure - 07	Details of damage to life, property, crops, and grains caused by wild animals and provided compensation	100-103
17.	Annexure - 08	Status report on wildlife management by projects being carried out in the area	104
18.	Annexure - 09	FC Violation Report by Respondent-04	105-106
19.	Annexure -10	EC Condition Violation Report by Respondent- 04	107-109
20.	Annexure -11	Report of the Crime Investigation Department, Jharkhand on the making of a false report by Respondent-03	110-116

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

Original Application No. 107/2025/EZ

(Earlier O.A. No. 206/2025/PB)

Mantu Soni..... Applicant

Vs.

State of Jharkhand..... Respondent

Rejoinder of the applicant to the reply of Respondent no. 03 Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, Ranchi, Respondent no. 04 NTPC Ltd. PAKRI BARWADIH COAL MINING PROJECT and Respondent no. 06 Chief Wildlife Warden, Jharkhand in the Original Application No. 107/2025/EZ before Hon'ble National Green Tribunal (Kolkata).

1. This application has been filed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi by the applicant, Mantu Soni alias Shani Kant, son of Shri Rajesh Kumar, Barkagaon, District Hazaribagh (Jharkhand) - 825311. This is the applicant's right and duty under Article 51(A)(g) of the Constitution. The above Original Application was filed by the applicant through a letter petition dated 23.01.2025. After the Hon'ble Principal Bench, New Delhi, issued a notice in the matter through its order dated 08.05.2025 and transferred the case to the Eastern Zone Bench of the Hon'ble Tribunal at Kolkata. Respondent no. - 04, NTPC Ltd., PAKRI BARWADIH COAL MINING PROJECT has filed an affidavit on 14.07.2025. In light of the order dated 17.07.2025 of the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, respondent no. - 03, Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, and respondent no. - 06, Wildlife Warden, Ranchi, Jharkhand, filed their affidavits before the Hon'ble Court

on 22.07.2025. In light of the Hon'ble Tribunal's order dated 24.07.2025, I am submitting following reply with apologies.

2. That the applicant had filed an application against the respondents before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that condition 9 of the Forest Clearance Stage 2, F. No. 8-56/2009-FC issued by the Government of India (MoEF&CC), which was a mandatory condition for transportation of coal through conveyor system (there was no mention of any type of road and conveyor operating load capacity scale, hence there was no provision for user agency to obtain permission for transportation of coal by road). NTPC, in connivance with the officials of Western Forest Division Hazaribagh and for personal gain, violated the said condition and transported coal through conveyor system and road to Banadag. The coal transportation by road has resulted in the death of dozens of common citizens, and the balance and movement of highly protected, protected and common wild animals have been affected. The wildlife has strayed and entered human habitations and caused damage to human life, property and agriculture.

3. It was stated that the applicant alleged that the respondents had misused and misinterpreted the OFFICE MEMORANDUM issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, on October 27/29, 2020, for ENVIRONMENT CLEARANCE (EC), and had violated condition number 9 of FOREST CLEARANCE Stage-2 F. No 8-56/2009 FC, by obtaining an order from the Hon'ble Supreme Court for relaxation/amendment of conditions based on the ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. It was further stated that FOREST CLEARANCE and ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) are two separate legal subjects, and compliance with the conditions according to the different standards of both divisions is mandatory.

4. That after the applicant filed a complaint against the respondents before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on 17th August, 2024 to the Minister, Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India and Chief Secretary, Government of

Jharkhand on 12th August, 2024 and to the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand on 08/09/2024 from Shri Sunil Bhardwaj, Forest, Environment and Climate Change (Forest Conservation Division), Government of India, New Delhi, Shri Jalaj Kumar, Officer on Special Duty, Principal Secretary, Forest, Environment and Climate Change Department, Government of Jharkhand, was directed on 07/10/2024 to inform the respondent 06 Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand as soon as possible after investigation on the subject matter of the complaint. The same letter also mentioned that on the applicant's complaint, Departmental Letter No. 1174 dated 29/03/2023, Departmental Letter No. 2043 dated 02/06/2023, Departmental Letter No. 2661 dated 14/07/2023, Letter No. 251 dated 25/01/2024, Departmental Letter No. 835 dated 11/03/2024 and Letter No. 3615 dated 06/08/2024 and dated 07/10/2024, the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand had been asked to submit an investigation report regarding the violation of Condition No. 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F. No. 8-56/2009 IFC by the Government of India for the NTPC Pankri Barwadih Coal Project.

Respondents 03, 04, and 06, acting in collusion, concealed facts and filed false affidavits to influence and mislead the Hon'ble National Green Tribunal, Kolkata and Respondents 01 and 05 have not filed any affidavits.

5. **Respondents 3 and 4 present different and contradictory facts on the same subject:** Mr. Maun Prakash, Forest Division Officer, Western Forest Division, Hazaribagh, on behalf of Respondents 3 and 6, and Mr. Birendra Kumar, AGM, on behalf of Respondent 4, have stated in their affidavits filed before the Hon'ble National Green Tribunal that they are filing this affidavit based on the information they have received and the documents available in the interest of justice. However, they have deliberately concealed facts for personal gain (details of reasons described in paragraphs 22A, 228) to influence the course of justice and to mislead and confuse the Hon'ble Tribunal. They have filed this affidavit to suit their convenience. Previously, they have presented different facts regarding the issues raised in the suit before the Hon'ble Jharkhand Legislative

Assembly and the Right to Information Act. Which has been hidden from the Hon'ble Tribunal and an affidavit has been filed by presenting different and contradictory facts to influence the justice, affidavit has not been filed by the Respondents 01 and 05.

6. **Respondents 03 and 04 gave a false reply to the Hon'ble Jharkhand Legislative Assembly, which was also concealed from the Hon'ble Tribunal:** That the then Hon'ble MLA, Shri Lobin Hembrom, had asked Starred Question No. 2 in the Jharkhand Legislative Assembly, inquiring, "Is it true that even after the construction of the conveyor belt, in violation of the conditions of the Forest Clearance, the Forest Department is still issuing transit permits to NTPC for coal transportation by road?" In response to this question, the Forest Department, after consulting the user agency NTPC, gave the following reply to the Jharkhand Legislative Assembly: "The Chief General Manager, Pakri Barwadih NTPC Limited, Respondent-04, has informed through his letter no. 23 dated February 10, 2023, that due to various reasons such as land acquisition and local law and order issues, the conveyor belt has not yet become fully operational. Consequently, they are currently transporting coal by road in light of the provisions of the office memorandum dated 27/29.10.2020 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi (which was valid for EC, not for FC, the details of which are described in the next paragraph). In the above context, transit permits are being issued."

   - The above response, Respondent 3 and Respondent 4, provided false and misleading information to the Hon'ble Jharkhand Legislative Assembly, stating that the conveyor system was not fully functional, without any documented technical report.

   - Since FC Condition No. 9 stipulated the transportation of coal by conveyor system, it did not mention whether the conveyor was functional or not, nor its dimensions, which would have allowed the applicant to transport coal by road.

   - Respondent no. - 03 should have answered the question asked in the Jharkhand Legislative Assembly based on departmental

records. However, they consulted Respondent 4 and then sent the reply to the Assembly.

- The above proves that Respondent no. 3 and Respondent no. 4 are deeply involved in collusion for personal gain. (Detailed reasons are described in paragraphs 22A, 22B). Both Respondents provided completely false answers to the Jharkhand Legislative Assembly.

- It is noteworthy that the above-mentioned reply/document was concealed and not presented to the Hon'ble Tribunal in Kolkata in the affidavit. The respondent in collusion with each other, filed an affidavit concealing the facts and giving a false and misleading reply.

- At the time when Respondent 3, after questioning Respondent 4, provided the reply in the Jharkhand Legislative Assembly, the Hon'ble Supreme Court's order dated 08.08.2022 in Civil Appeal No. CA 6249/2021 in the case of Tripurari Singh and others, directing completion of the conveyor construction by or before October 2023, was in effect. (Paragraph 17, Annexure 3) However, both Respondents deliberately did not submit the said order to the Jharkhand Legislative Assembly. (Annexure 1)

6-A. Mis-interpretation of documents and defence of violation of FC Condition 9 in Jharkhand Vidhansabha by citing OFFICE MEMORANDUM which was valid only for EC :- It is clear from (paragraph 6, Annexure 1) that the question asked in the Hon'ble Jharkhand Vidhansabha was answered by Respondent 3 not by referring to government records but by referring to Respondent 4. The question asked by Hon'ble MLA Lobin Hebram was regarding violation of FOREST CLEARANCE (FC) and the answer was given by citing OFFICE MEMORANDUM valid only for ENVIRONMENT CLEARANCE (EC). In the reply given to the Vidhansabha, coal transportation by road was stated to be based on the OFFICE MEMORANDUM dated 27/29.10.2020 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi. Whereas, Clause 4 of the same notification clearly stated that this notification would be valid only for ENVIRONMENT CLEARANCE (EC). The above facts prove that for personal gain (details mentioned in

paragraph 22A, 22B), Respondents 3 and 4 gave false, incorrect and misleading replies to the Hon'ble Jharkhand Legislative Assembly by misinterpreting the documents. (Annexure – 01A)

7. **Respondent 03, in his reply under the Right to Information Act, stated that the office does not have any records regarding transportation of coal by road after the conveyor system was installed:-** That in response to information number 3, requested by applicant Mantu Soni alias Shani Kant under the Right to Information Act 2005 on 07/10/2022 at the Western Forest Division, Hazaribagh office, "If a departmental order has been issued by the Forest Department permitting NTPC (Respondent 4) to transport coal by road after the commencement of coal transport by conveyor belt from the Pankri Barwadih Coal Project to the Banadag Railway Siding, a copy of the departmental order along with its conditions should be provided," it was stated on 02/11/2022 that "No records are available in this office regarding whether or not to transport coal by road after the commencement of coal transport by conveyor belt from the Pankri Barwadih Coal Project to the Banadag Railway Siding." The above answer has been concealed by Respondent 3 in his affidavit, influencing and misleading the Hon'ble Tribunal and abusing his position.

   - Based on the above information, as of 02/11/2022, Respondent 3 did not have any record of not transporting coal by road after the conveyor system was installed. Then, when and through what means did the Respondent obtain the records that he has submitted in Clauses 13 and 14 of his affidavits regarding the transportation of coal by road before the Hon'ble Tribunal? Why was this record not made available despite the Government of India and the State Government repeatedly requesting an investigation report from Respondent 3 in the matter of violation of FC Condition 9? Details of which are given below.

   - In paragraphs 13 and 14 of his affidavit before the Hon'ble Tribunal, Respondent No. 3 has presented the following arguments regarding the complaint filed by the applicant concerning the violation of FC condition no. 9, and in light of the letter dated 08/09/2024 from Shri Sunit Bhardwaj of the Ministry of Environment, Forest and

Climate Change (Forest Conservation Division), Government of India, New Delhi, Shri Jalaj Kumar, Officer on Special Duty to the Principal Secretary, Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand was directed on 07/10/2024 to instruct the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand (Respondent no. 3) to submit an inquiry report on the subject matter of the complaint as soon as possible after conducting an investigation. A reply to this letter has not yet been provided to the Government of India.

- In the said letter itself, on the complaint made earlier by the applicant, Departmental letter no. 1174, dated 29/03/2023, Departmental letter -2043 dated 02/06/2023, Departmental letter no. 2661 dated 14/07/2023, letter no. 251 dated 25/01/2024, Departmental letter no. 835 dated 11/03/2024 and letter no. 3615 dated 06/08/2024 and dated 07/10/2024, the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, respondent 03 did not make the land available to the Government of Jharkhand and the Government of India for personal benefit.

- The above correspondence has been annexed by the applicant as Annexure 3 to the original application for petition (Annexure 1B).

8. **The site inspection of Respondent 2 confirmed violation of FC Condition 9:** That Respondent 2, in the site inspection report sent to Shri Charanjeet Singh, Scientist 'D' (FC Division) (MOEF &CC), Government of India, by the Integrated Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Harmu, Ranchi, dated 25/11/2022, by Mr. Charanjeet Singh, Scientist 'D' (FC Division), (MOEF &CC), Government of India, states on page 6 that the user agency, NTPC, is transporting coal by road in addition to the conveyor system, which is a partial violation of Condition 9 of the FOREST CLEARANCE Stage-2 F.No. 8-56/2009-FC. This report has also been concealed from the Hon'ble Tribunal by all Respondents in their affidavits. This further proves that the respondents have misled the Hon'ble Tribunal by abusing their position for personal gain and misguided the justice of the Hon'ble Tribunal, which they did not mention in their affidavit. (Details mentioned in paragraphs 22A, 22B)

- This confirms that the conveyor system was commissioned before 25.11.2022 and FC condition no. 9 was violated by respondent 04. The other respondents did not take any action on this for personal gain and the arguments made by respondent 03 in paragraphs 13 and 14 of his affidavit before the Hon'ble Tribunal are false and misleading facts presented to influence the course of justice. (Annexure 1C).

9. **Two-member investigation report of Respondent no. 3 confirms violation of FC Condition 9, suppressed for five months, and concealed from the Hon'ble Tribunal:** In light of the applicant's complaint regarding violation of Condition 9 of the Forest Clearance, a two-member investigation committee was constituted by the Conservator of Forests, Regional Circle, Hazaribagh, vide letter no. 1892, dated 29/11/2024. The investigation committee submitted an interim investigation report to the Conservator of Forests, Regional Circle, Hazaribagh, on 27/02/2025. The investigation team stated in its opinion that the user agency, NTPC, was blatantly violating Condition no. 9 of the Forest Clearance Stage-2 F. No. 8-56/2009-FC. The basic purpose for this condition was imposed to ensure that the movement of wild animals (especially elephants) was not obstructed, but it is still being violated. Due to which the movement of wild animals (especially elephants) has been obstructed and the wild animals stray into human populated areas and are causing damage to the life, property and agriculture of common citizens. A few days ago, elephants strayed into Banadag Railway siding and up to Khirgaon near Hazaribagh city. Dozens of people have died so far in accidents due to coal transportation by road. Besides, forests are being adversely affected, it is true that NTPC Pankri Barwadih Coal Project is transporting coal by road by amending the EC conditions. This has no connection with Condition no. 9 of the Forest Clearance Stage-2 F.No. 8-56/2009-FC. EC and Forest Clearance are two different entities. The standards and objectives of the conditions imposed by both are different. However, the user agency is not complying with the Forest Clearance conditions by amending the EC conditions. The Public Information Officer has not provided proper information to the complainant Mantu Soni alias Shani Kant. Therefore, yours faithfully, the Inquiry Committee recommends strict compliance with Condition no. 9 of FOREST

CLEARANCE Stage-2, F.No. 8-56/2009-FC. The Forest Department is responsible for enforcing this condition. Violation of this condition is punishable under the FOREST CONSERVATION ACT-1980 and the WILD LIFE PROTECTION ACT-1972.

- The above investigation report was submitted on 27.02.2025. However, respondent No. 03 did not make it available to the Hon'ble Tribunal in his affidavit dated 22.07.2025, concealing it.

- There is a strong apprehension that the said report was suppressed in collusion with respondent No. 04 as part of a conspiracy for personal gain and was deliberately concealed from the Hon'ble Tribunal. Respondent no. 03 may attempt or conspire to suppress and conceal this report. The applicant has already informed the Jharkhand Government of this information. A copy of which was also given to the Hon'ble Tribunal.

- **The above report was a confirmation of the investigation into the complaint against Mr. Maun Prakash, Western Forest Division Officer, who filed the affidavit for Respondent no 3. Therefore, he deliberately did not provide the said report in his affidavit and the records given in paragraphs 13 and 14 of the affidavit are different and incorrect. (Annexure 1D)**

10. False & misleading affidavits filed before the Hon'ble Tribunal: That Respondents Nos. 3, 4, and 6 have not mentioned the above facts and crucial evidence (paragraphs 6 to 9, Annexures 1 to 1D) anywhere in their affidavits filed before the Hon'ble Tribunal, which were in the official departmental documents under their control. This also confirms their fraudulent intention to provide different answers/information at various levels to protect their violation of FC Condition 9. And, by deliberately abusing their position, the Respondents have submitted misleading and incomplete evidence in their affidavits for personal gain, misleading the Hon'ble Tribunal, and influencing the judicial process.

11. The State Government is responsible for ensuring compliance with the conditions imposed by the Ministry of Environment, Forests and Climate

Change (MoEF & CC), Government of India, under the Forest Conservation Act, 1980, and the State Government also has a duty under Article 48(A) of the Constitution of India. However, by amending the EC condition, Respondent 3, the Forest Department, and Respondent 4, the user agency, NTPC, are violating Condition 9 of the Forest Clearance Stage 2, F. No. 8-56/2009-FC, dated 17.09.2010, issued by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, under the Forest Conservation Act, 1980. To this end, for personal gain, various information/responses have been submitted at various levels to defend the violation of FC Condition 9. This demonstrates the mala-fide mindset and role of Respondents.

12. **Hon'ble Supreme Court's order in the matter of giving false, wrong and misleading answers in the courts by concealing facts:-** That the facts and evidence mentioned in (paragraphs 6 to 9, Annexures 1 to 1D) prove that the respondents No. 3, 4 and 6 have not mentioned the above facts and important evidence anywhere in their affidavits filed in the Hon'ble Tribunal. Which were deliberately concealed for personal gain through mutual collusion. In such a related matter, the Hon'ble Supreme Court has said in its order dated 11.07.2022 in SUOMOTU CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.3 OF 2021 that:

- The Supreme Court observed that the tendering of affidavits and undertakings containing false statement would amount to contempt of court. A person who makes a false statement before the Court and makes an attempt to deceive the Court, interferes with the administration of justice and is guilty of contempt of Court, the bench comprising Justices UU Lalit and PS Narasimha observed. While considering this case, the court noticed an earlier decision on the question whether tendering of affidavits and undertakings containing false statement would amount to criminal contempt or not Referring to ABCD v. Union of India, the court said:

- "It is thus well settled that a person who makes a false statement before the Court and makes an attempt to deceive the Court, interferes with the administration of justice and is guilty of

contempt of Court. The extracted portion above clearly shows that in such circumstances, the Court not only has the inherent power but it would be failing in its duty if the alleged contemnor is not dealt with in contempt jurisdiction for abusing the process of the Court."

- The Hon'ble Supreme Court has repeatedly held in various cases that filing a false affidavit and concealing material facts constitutes interference in the administration of justice and thus constitutes criminal contempt of court.

- The affidavit filed by the respondents also violates the Contempt of Courts Act, 1971.

- This act of the respondents also violates Sections 229 and 236 of the Indian Penal Code.

The respondents have misled the Hon'ble NGT to protect themselves and to violate the Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972 by concealing the facts regarding amendment in the condition of Environmental Clearance (EC) under Environment Protection Act 1986 in the Hon'ble Tribunal.

13. Density of wildlife in the project area: - That in the Hazaribagh forest range, there is density of wildlife of Schedule 1 which comes under the highly protected category (endangered category), wildlife of Schedule 2 which comes under the protected category and wildlife of Schedule 3 and 4 categories. For the smooth movement and protection of wildlife, a mandatory condition of transporting coal through conveyor system was imposed on respondent 04 in condition number 09 of FOREST CLEARANCE. Thus, the Wildlife Protection Act 1972 is also applicable in the said condition. The list of wildlife is attached. (Annexure -02)

14. Conditions of Forest Clearance granted under the Act 1980:- That it is mentioned in the first paragraph of FOREST CLEARANCE Stage 2,

F.No 8-56/2009-FC dated 17.09.2010 under the Forest Conservation Act 1980 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for NTPC Pakri Barwadih Coal Project at Barkagaon in Hazaribagh District of Jharkhand State that.

- I am directed to refer to the State Govt. letter no. 3/Vanl3humi-75/2009/2458/VP dated 06.08.2009 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principal approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 11.05.2016) subject to fulfilment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principal approval and has requested the Central Government to grant final approval.

  Its condition number 9 stipulated that coal should be transported through a conveyor system to facilitate the movement of wildlife, especially elephants. It clearly stated that:

  - "9. The coal evacuation will be done through high-speed conveyer of 20-meter width running at n height sufficient to allow all tall wild animals including elephants. The installation of such system will be undertaken under the supervision of the CWLW of the State"

  - There is no mention of any road or conveyor loading capacity or standard for smooth operation of the conveyor to allow it to transportation of coal by road.

  - The above statement makes it clear that the said condition is under the Forest Conservation Act, 1980 and is also applicable to the Wildlife Protection Act, 1972, as the condition of coal transportation through a conveyor system was given for the smooth movement of wildlife.

- The affidavits filed by Respondents 3 & 6 in Paragraphs 13 and 14 of the affidavits filed before the Hon'ble Tribunal in defence of the violation of the above condition, and the side statement given by Respondent 4 in Paragraph H, are subject to the conditions of Environmental Clearance (EC) under the Environment Protection Act, 1986. Clause 5 of the affidavit clearly states that the said conditions do not mention the effectivity of the conditions under the Forest Conservation Act, 1980. (Annexure - 02 A)

15. Respondents 3, 4 and 6 have tried to defend themselves by misinterpreting Condition No. 2A (ix) of the EC in violation of FC Condition No. 9, but have concealed Condition No. 5 of the EC from the Hon'ble Jurisdiction:- That in the case No. OA No. 107/2025 of the Hon'ble National Green Tribunal (EZ), Kolkata, the Forest Division Officer, Shri Maun Prakash, Western Forest Division, Hazaribagh, on behalf of Respondents 3 and 6, has admitted in Clause 13 and 14 of his affidavit and Respondent No. 4 has admitted in Clause H of his affidavit that the transportation of coal by road by the User Authority NTPC is being done by amending Specific Condition No. 2A (ix) of the Environmental Clearance (EC) received from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India on 09.05.2009, in which the 10th amendment has been made so far. It is mentioned below.

- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation from CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System.

- (There is no mention of the loading capacity or smooth operation of any road or conveyor that would permit coal transportation by road.)

- It is also important to note that the respondents have deliberately concealed the facts mentioned in Clause 5 of the Environmental Clearance (EC) dated 09.05.2009 received from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, as stated in the Hon'ble Tribunal.

- The above conditions shall be governed by, among others, the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

- It is clear from the above that the said condition of EC is not effective and is not applicable to the conditions imposed under the Forest Conservation Act, 1980.

(Annexure 02 B)

16. It is clear from the details mentioned in clauses 14 and 15 that the respondents 03, 04 (NTPC) and 06 are violating condition 9 of Stage 2 Forest Clearance (FC) dated 17.09.2010 granted to the Hon'ble Tribunal under the Forest Conservation Act, 1980 by amending the condition of Specific Condition No. 2A (ix) of ENVIRONMENT CLEARANCE (EC). Whereas in clause 5 of the same EC it is clearly stated that it is not applicable to condition No. 9 of Stage 2 granted under the Forest Conservation Act, 1980. Which has been deliberately concealed by the respondents for personal gain to influence the justice of the Hon'ble Tribunal.

The Hon'ble Supreme Court has also been mis-leaded and contempt is being committed by respondent No. 04 NTPC.

17. The Hon'ble Tribunal had ordered Respondent 04 to construct the conveyor belt within three months, but took two years' time from the Supreme Court:- That the Hon'ble Tribunal, Kolkata, in its order dated 06.01.2021 in Tripurari Singh vs. Ministry of Railways, 0A no. 61/2019/EZ, had ordered Respondent No. 04 NTPC to direct the user agency to construct the conveyor belt within three months. Against the

said order, Respondent 04 filed an appeal in the Hon'ble Supreme Court for amendment of Specific Condition No. 24 (ix) of the Environmental Clearance (EC) dated 19.05.2009 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (which is not referred to condition no. 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F. No. 8-56/2009-FC). The Respondent filed **Civil Appeal No. C.A 6249/2021** in the case of **Tripurari Singh and others**. On the above appeal, the Hon'ble Supreme Court, in its order dated 08.08.2022, had ordered completion of the conveyor construction by or before October 2023. Thus, Respondent 04 obtained an order from the Hon'ble Supreme Court by amending the EC condition and concealed FC condition No. 09 (Clause 15, Annexure 02 A), which was a mandatory condition for transporting coal through the conveyor system for the smooth movement of wildlife, from the Hon'ble Supreme Court and did not obtain any amendment or exemption from the Ministry on the same. And it has been violating it till date.

(Annexure 03)

18. Respondent 04 constructed the conveyor system before the time stipulated by the Hon'ble Supreme Court: - That as per the order of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. C.A no. 6249/2021 dated 08.08.2022 (Annexure 03) in the case of Tripurari Singh and others, Respondent 04 NTPC had constructed the conveyor system before October 2023. This is confirmed by information number 1 and 2 of letter no. 3643 dated 2/11/2022 under the Right to Information Act 2005 (paragraph Annexure 01B). In which the information was sought as to "Is the Forest Department issuing permission permits for the transportation of coal from NTPC's Pakri Barwadih Coal Project to Banadag Railway Siding using conveyor belts and trucks?" Yes or No? In reference to both the above information, it was accepted that "The Forest Department is issuing permission permits for the transportation of coal from NTPC's Pakri Barwadih Coal Project to Banadag Railway Siding using conveyor belts and trucks." This makes it clear that in light of the order of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 6249/2021 (paragraph 17, Annexure 3), the conveyor system was completed by 2/11/2022, before October 2023, and was operating smoothly. The completion of the conveyor system is confirmed by letter No. 717, dated 11/02/2022, of the Integrated Regional Office, Haram Chowk, Ranchi, Ministry of Environment, Forest

and Climate Change, Government of India. This is also true from 25/11/2022. Page number 6 of which states that the user agency is also transporting coal by road along with the conveyor system. This partial violation of condition number 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2 F.No 8-56/2009 FC is also confirmed by (paragraph 9 Annexure 01C), which was reported to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. This certifies that the conveyor system was already installed before 25.11.2022.

19. Even after the conveyor system was built, respondent 4 misled the Supreme Court and obtained the order: - It is proved from (paragraph 8 Annexure 1B) and (paragraph 9 Annexure 1C) that the conveyor system was commissioned in November 2022, for which the Forest Department is issuing permission permit. Even after that, respondent 4, through the user agency NTPC, again filed **Miscellaneous Application No. 1824/2023 in CA No. 6249/2021 in the Hon'ble Supreme Court** and misled the Hon'ble Court. The Hon'ble Supreme Court accepted this request and passed this interim order on 20.10.2023.

a) Allow the present application; and

b) Extend the timeline for completion of the entire Coal Conveying System facilities /CHP [from mine to Railway siding] at Appellant's Pakri Barwadih Coal Mine Project, Barkagaon, Hazaribag, until 31st December, 2024"

c) Earlier, this Court by its order on 08.08.2022 had extended the timeline for completion of the construction of the conveyor belt till 31.10.2023.

After this, by misleading the Hon'ble Supreme Court, an order was obtained from the Hon'ble Supreme Court in its order dated 29.01.2024 to completely rebuild the conveyor system by 31 December 2024.

(Annexure 03A)

The above details clearly show that respondent-4 NTPC user agency, filed a false affidavit in the Supreme Court, seeking an order to transportation of coal by road from October, 2023 to December 31, 2024, to serve its own selfish interests. The conveyor system was commissioned in November 2022, as confirmed by (paragraph 8, Annexure 018) and (paragraph 9, Annexure-01C).

20. **After the expiry of the time period as per the order of the Hon'ble Supreme Court, Respondent 04 is committing contempt of the Hon'ble Supreme Court by getting amended condition in EC from MOEF & CC: -** That Respondent 04 user agency NTPC filed **Miscellaneous Application No. 1824/2023 in CA No. 6249/2021 in the Hon'ble Supreme Court** and obtained the order upto **31st December 2024** from the order dated 29.01.2024 by the Hon'ble Court. (Paragraph 19, Annexure 3A) After the expiry of the time period of the above order, the User Agency did not approach the Hon'ble Supreme Court again and instead got the tenth amendment in Specific Condition No. 2A (ix) of the Environmental Clearance (EC) dated 19.05.2009 from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and is transportation of coal by road.

- This is contempt of the Hon'ble Supreme Court and a deliberate attempt to mislead the Hon'ble National Green Tribunal.

- Despite this, the user agency is still transporting coal by road from the mining site to the railway siding, despite the above amendment.

- This is resulting in failure to achieve the objective for which FC Stage - 2 Clause no. 9 was imposed to transport coal by conveyor system and for which the Hon'ble Supreme Court had passed the order on 29.01.2024.

- The reason given for Respondent 4 seeking amendment to the EC condition was that coal should have been transported by road from the mining site.

- However, Respondent 4, in connivance with Respondents 1, 2, 3, 4, 5, and 6, is transporting coal by road from the mining site to the railway siding for personal gain.

(Annexure-3B)

21. Respondent 04 concealed and misled the Hon'ble Court regarding Condition No. 9 of Stage 2 of Forest Clearance dated 17.09.2010 under the Forest Conservation Supreme Act 1980:- That in the Hon'ble Supreme Court, Respondent 04 NTPC in Civil Appeal No. C.A. No. 6249/2021 in the case of Tripurari Singh and others and Miscellaneous Application No. 1824/2023 (Annexure 3 and 3A) deliberately concealed and misled the Hon'ble Supreme Court the material fact regarding Condition No. 9 of Stage 2 of Forest Clearance, F. No. 8-56/2009-FC dated 17.09.2010 under the Forest Conservation Act 1980 granted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Whereas Specific Condition No. 2A(ix) was equivalent to the condition.

- The main haul road of 5 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main appro Specific condition No.- 2A (ix) was equivalent.

- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation from CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7 km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System ach roads and haul roads. Mineral transportation from CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System.

- FC Condition 9 mandated that coal be transported using a conveyor system to protect wildlife. This requirement is

enforceable under the Forest Conservation Act of 1980 and the Wildlife Protection Act of 1972. This mandatory requirement was imposed with the protection of forests, wildlife, and human-wildlife relations in mind. However, the user agency ignored this requirement and, for personal gain, repeatedly misled the Hon'ble Courts and violated their orders.

Concealing the massive irregularities in transportation of coal by road in violation of condition no. 09 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F. No. 8-56/2009-FC, the respondents no. 03, 04 and 06 have given misleading reply in their affidavit to mislead the Hon'ble Tribunal on the important points and evidence in the Original Application No. 107/2025/EZ.

22. In the case of felling trees in forest land and transporting coal by road, Respondent 3 filed a forest suit against Respondent 4, based on the applicant's complaint. Respondent 3 failed to act and did not respond to the Tribunal.

- That respondent 04 states in clause F of his affidavit that he is transporting coal through state highways and rural roads, which is outside the forest land. Whereas, no reply has been given by respondent 03, 04 and 06 on the evidence mentioned and attached in clause 8 of ANNEXURE 2 of the original application of OA 107/2025/EZ.

- This includes a forest case registered under the Forest Conservation Act, 1980, against the officials and agencies of respondent 04, in which Mr. Birendra Kumar, who filed an affidavit in the Hon'ble Tribunal on behalf of respondent 04, is also named as an accused.

- The respondents have not answered this in their affidavit. The user agency NTPC (Respondent no. 04) and the transporter agencies working under it are accused in

complaint cases number 29/2021 dated 30.12.2020, 33/2021 dated 24/12/2020, and 35/2021 dated 27/12/2020, based on a complaint by the applicant Mantu Soni alias Shani Kant for cutting down trees and transporting coal through forest roads, and violating the Indian Forest Conservation Act, 1980. All these cases allege violation of Section 33 of Bihar Amendment Act 1989 and the Indian Forest Act, 1927.

- Furthermore, in addition to complaint case 3192/2020 dated 20/11/2022 under Sections 33 and 52 of the Bihar Amendment Act, 1989 of the Indian Forest Act, 1927, and complaint case 3221/2022 dated 23/11/2022 under Sections 33(1)(b)(c) and 63(c) of the Indian Forest Act, 1927, and forest offense report number 4812 dated 18/09/2024 regarding the cutting of five thousand Sal wood poles, registered under Sections 33 and 52 of the Bihar Amendment Act, 1989 of the Indian Forest Act, 1927, no action has been taken by the defendant no. 06 so far.

- In the above case, the Forest Department, respondent number 03, has shown negligence and indifference, or has deliberately refrained from taking action. Furthermore, respondent number 03 is colluding with respondent number 04 in committing illegal acts by misusing their position and fulfilling personal interests, thereby violating and disregarding rules, laws, and orders of the Hon'ble Supreme Court, and also disregarding Article 48A of the Constitution.

22 A. Respondent 04 has not responded to the Hon'ble Tribunal in his affidavit on the irregularities in transportation of coal by road by two - three wheelers: -

- That the respondents No. 03, 04 and 06 did not answer the facts and evidence in their affidavits mentioned in

Para 6 and 7 of ANNEXURE-2 of the applicant's original application in OA 107/2025/EZ.

- In which a letter was written to the District Mining Office, Hazaribagh, by the Director of Mines and Geology Department, Jharkhand, Ranchi, vide letter No. 2549/M.
- Ranchi, dated 09/10/2018, informing about the transportation of coal from NTPC's Pankri Barwadih Mining Project to Banadag Siding by two-three motor passenger and motor car through e-transport challan (including challan and vehicle number) as verified through JIMMS system.

- After this, Mr. Nitesh Gupta, District Mining Officer, Hazaribagh, vide letter no. 27/Mining, dated January 7, 2019, and letter no. 248/Mining, dated March 5, 2019, requested the Barkagaon police station to take necessary action by registering an FIR under relevant rules and sections against the individuals/companies involved in the coal transportation using fake vehicle challans.

- However, even after six years passed, the case has not been registered, in violation and contempt of the orders of the Hon'ble Supreme Court in W.P (Cr) 68/2008 and Cri. Misc. Petition **no. 1844/2008**, **Lalita Kumari and Uttar Pradesh and others.**

22 B. Respondents did not respond to the Hon'ble Tribunal regarding the irregularities in the transit permit issued by Respondent 03 against Respondent 04: - That the Forest Department, respondent 03, had detected several irregularities in the coal transportation of Respondent 04 NTPC, which were detected only during one-time surprise inspection. (If regular inspections had been conducted, many irregularities would have been revealed.) The Hazaribagh Western Forest Division Officer had written a letter to the Additional General Manager, Coal Dispatch Department, NTPC, in his office letter No. 3659, dated October 18, 2021. In this letter,

during a surprise inspection of the counter file of the transport permit issued by NTPC on August 30, 2021, and some of the counter files dated August 31, 2021, several discrepancies were detected, which are as follows.

(a) No specimen signature is found on the transport permits issued from JHAA 112501 to JHAA 1125700, authorized by your letter no. 1040/PBCMP/CD/2020/913 dated 19 October 2020, which makes your letter no. 1040/PBCMP/CD/2020/913 dated 19 October 2020 invalid. Such acts fall under the category of forest offences.

(b) The maximum distance of the distance points from the loading point of the transport permit is 30 km. The maximum validity period of the transport permit for this distance should be 6 hours. However, in some permits, the validity period is given from 24 hours to 30 hours, which is not correct. The following permits, Transport Letter No. JHAA1125667, JHAA1125669 through JHAA115686, and Permit No. JHAA1125692, all have validity periods of 24 to 30 hours, which is not correct as per the rules.

(c) In clause 8 of the Transport Permit, it is also not in accordance with the rules that the authorized officer who issued the Transport Permit was not mentioned.

(d) The permit numbers JHAA1125501 to JHAA1155528 on August 31, 2021 at 11:16 am and the subsequent issuance of permit numbers JHAA1125528 to 550 on August 31, 2021 at 05:04 in issuance of permits JHAA1125501 to JHAA115550 in am is not legal.

- On the same date, the plaintiff was asked to explain the rationale for granting an earlier date in the transport permit. The Forest Department has not taken any legal action, and no surprise inspection, detailed, and

impartial investigation has ever been conducted against such serious irregularities.

- This confirms the collusion of Respondent 03, the Forest Department, with Respondent 04, the user agency, NTPC, for personal gain. This is why, along with the user agency, the Forest Department has filed a misleading and false affidavit in the **Hon'ble Tribunal.**

22 C. In the Hon'ble Tribunal, the respondents 03, 04 and 06 gave incomplete reply to the Hon'ble Tribunal on the Wildlife Management Plan to hide the loss of wildlife and to influence the justice: -

- That Respondent No. 4 states in Clause E of his affidavit that he has deposited ₹135.67 crore in the CAMPA account for the Wildlife Management Plan.

- Respondents No. 3 and No. 6 also stated in the last paragraph of para 15 of their affidavits that the user agency, NTPC has deposited the amount in the CAMPA account of the Department.

- **The respondents have cleverly given an incomplete and misleading reply to the Hon'ble Tribunal. Because when the above-mentioned amount was deposited and what schemes were implemented on it. They have deliberately tried to hide this fact which is as follows:**

- Mining operations were started in 2016 by respondents 3, 4 and 6 without working on the Wildlife Management Plan and respondent 4 deposited Rs. 135.67 crore of amount in the CAMPA account for the Wildlife Management Plan and in 2023.

- In this regard, the then Forest Division Officer, Western Forest Division, Hazaribagh, wrote a letter dated

21/12/2023, based on information available within the division. In this letter, the following information was written regarding the user agency:

- NTPC Pakri Barwadih (1026.438 Hectare): Stage 11 of the forest land diversion proposal was completed in 2010. The user agency submitted a Site-Specific Wildlife Management Plan in 2023, which was approved by the Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi, Office Order No. 33, Letter No. 1006, dated 03/08/2023, while mining has been ongoing since 2016. Despite the approval, no funds have yet been received from CAMPA for mitigation.

(Annexure-4)

22 D. Respondent 4 has made an amendment stating that electrification and signalling work is underway and is transporting coal through the entire route: That Respondent 4 has stated in paragraph G of the affidavit that in light of the notification dated 02.01.2025 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, coal is being transported through covered trucks by road. However, he has concealed the fact that the said amendment was taken by him citing the reason that-

- 4. The construction of siding se being done by railways, consists of seven nos. of rail tracks out of which 3 are ready, also, the electrification and signalling work is under progress. It is likely that yard augmentation work by railways shall be completed by 31.01.2025. After yard augmentation and RLS completion, it shall require three months of time (till 31.03.2025) to synchronize the system with railways which is knowns as "Integrated commissioning". In other words, it may take three months for both RLS streams to reach its rated capacity of 15 MT.

- According to the reason given by Respondent no. 4, the user agency should have transported coal by road only to the extent where its construction work is incomplete.

- However, it is transporting coal by road from the mining site to the road siding. This is an abuse of the said condition amendment and an attempt to mislead the Hon'ble Tribunal.

- While Specific Condition No. 2A (ix) of the Environmental Clearance (EC) and Condition No. 9 of the Forest Clearance (FC) stipulate that coal be transported only by conveyor system, no basis has been given for transporting coal by road, such as loading capacity, increasing mining capacity, increasing production capacity, or any other reason.

22 E. Respondent 04 filed a false affidavit to the Hon'ble Tribunal on the death of villagers during coal transportation by road –

- That respondent No. 4 has falsely claimed in Clause 1 of his affidavit that NTPC has directly denied any death in an accident during coal transportation by road.

- While the applicant has attached in Clause 9 of Annexure 2 of the original application of OA 107/2025/EZ a news item dated 02.12.2022 in the national daily newspaper "Dainik Bhaskar" in which at the beginning of the news item, Sunil Bhuiya, a resident of Chepakala in the Paryanjana area, died after being hit by a Hiva truck belonging to Triveni Sainik Transporting Company, which is the MDO of NTPC, and a news item dated 02.11.2022 in which Triveni Sainik, a subsidiary of NTPC, has given a job and a compensation of Rs. 6 lakh to the family of the deceased in the road accident.

- In this matter also, an attempt has been made by respondent 04 to mislead the Hon'ble Tribunal by submitting a false affidavit.

- In another development, the news item published in Dainik Bhaskar newspaper dated 09.02.2023 titled "**Woman who went to collect coal dies after being crushed in OB**" confirms that the respondent 04 had caused the death of the woman.

22 F. Respondent 04 has misled the Hon'ble Tribunal by presenting false facts without any basis, truth and instructions of MOEF-CC and has attempted to conceal the evidence –

- Respondent 4 has filed his affidavit in paragraphs F through J, citing facts based on his own hypotheses, without authoritative documents, regarding coal transportation by road. This is evident from the following points:

- On one hand, Respondent 4 has been seeking amendments to the conditions from the Hon'ble Supreme Court and the Ministry of Energy (MoEF&CC) by falsely citing legal provisions regarding conveyor systems, railway tracks, etc., while at the same time, he is presenting his own hypothetical theory of coal transportation by road before the Hon'ble Tribunal, without any departmental documents. This reflects his own failure.

- The standards, regulations, and assessments for road transportation of coal for any coal mining project are decided in the Central Board meeting, based on the inspection and recommendations of technically competent officers of the Ministry of Energy (MoEF&CC). However, Respondent 4 is attempting to mislead the

Hon'ble Tribunal by presenting his own fabricated arguments.

- The user agency, granted FC approval for twenty years and EC conditions, failed to fulfill the conditions for 14 years. They themselves are violating the conditions for transporting coal by road, sometimes citing incomplete conveyor systems, sometimes not fully functioning conveyors, sometimes not having built railway tracks, and sometimes lack of legal procedures and land acquisition, in collusion with the Forest Department, to serve their own selfish interests.

- While the order for coal transportation by road has never been made under the conditions of environmental clearance or forest clearance. Therefore, their argument appears to be an unauthorized, impractical, and irresponsible attempt to mislead the Hon'ble Tribunal and influence the course of justice for personal gain.

22 F. Respondents 03 and 06, concealing the facts mentioned in condition 9 of FC and condition 5 of EC, gave incomplete and misleading facts to the Hon'ble Tribunal, details of which are given below-

- That Mr. Maun Prakash, who filed affidavit in the Hon'ble Tribunal on behalf of respondent 03 and respondent 06, in clause 9 of his affidavit has mentioned "The approval under the forest Conservation Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986." mentioned in clause 6 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F. No 8-56/2009 FC dated 17.09.2010.

- It is not clear whether the above point applies to FC Condition 9, nor is it clear in what context. FC conditions apply under the Forest Conservation Act, 1980, and EC conditions apply under the Environment Protection Act, 1986. The standards and parameters for both are

different. Since the above condition was imposed for the easy movement and protection of wildlife, the Wildlife Protection Act, 1972, also applies.

- In clauses 13 and 14 of the affidavit filed by Shri Maun Prakash on behalf of the respondents 03 and 06 in the Hon'ble Tribunal, the defence of transporting coal by road has been taken by citing the 10th amendment in Specific Condition No. 2A (ix) of the Environmental Clearance (EC) received on 09.05.2009 from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

- It is also to be specifically mentioned that the facts mentioned in clause 5 of the Environmental Clearance (EC) received on 09.05.2009 from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India have been deliberately concealed by Shri Maun Prakash in the Hon'ble Tribunal. Which is mentioned.

- The above conditions shall be governed by, among others, the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

- It does not mention that the said condition is not effective and is not applicable to the conditions imposed under the Forest Conservation Act, 1980. When Clause 5 of the EC clearly states under which law the condition will be applicable, it is self-evident that the respondents have wrongly concealed the said clause. The EC condition is being misinterpreted and misused (described in para 15, Annexure 2AB).

Respondent 04 NTPC and other coal projects operating under the Western Forest Division were opened for mining operations without implementing the Wildlife Management Plan for the sake of personal

gain, which caused huge damage to wildlife, human life, agriculture and ecology.

23. It is stated that the Hazaribagh forest area contains Schedule I wildlife, which falls under the highly protected category (endangered species), Schedule II wildlife, which falls under the protected category, and wildlife of Schedule III and IV categories. A detailed account and the report of the then Divisional Forest Officer mention the damage and objections arising from the mining activities initiated by respondents 03 and 06 in the said area without proper wildlife management. These are as follows:

23A. That through a Right to Information request dated 13.03.2020, it was stated in paragraph 3 that "in the last ten years, compensation has been paid to affected persons in 1422 cases related to loss of life and property due to wild animals."

- This confirms the violation of the Wildlife Protection Act, 1972, and the resulting damage caused by respondents 03 and 06 failing to implement the Wildlife Management Plan for personal gain, and also confirms the disruption of the ecological balance of wildlife. Page 32 of 116 (Annexure 6)

23B. This refers to a report from the office of the Divisional Forest Officer, West Forest Division, Hazaribagh, vide letter number 5813 dated 11.10.2023, which provides details of compensation amounts related to deaths and injuries caused by wild elephants within the West Forest Division from the year 2019 to 2024.

- A total of ₹10,000,000.00 was paid for the 32 deceased individuals and ₹530,000.00 for the 7 injured, total ₹ 10,530,000.00.

- Furthermore, details of compensation paid for damage to crops, stored grain, houses, and livestock caused by wild elephants from 2019 to 2024 are provided. There were a

total of 1560 cases of crop damage, affecting 228.8 hectares of land and resulting in a loss of 557,120 quintals for which ₹ 4,340,772.00 was paid in compensation.

- The data provided includes 290 cases of stored grain damage amounting ₹ 98,950.00 for to 618.44 quintals, and 576 cases of house damage ₹ 10,110,000.00 and furthermore, a total of 23 cases of livestock damage were reported to 18,000 quintals amounting ₹ 314,000.00.

- This confirms the impact of the violation of the Wildlife Protection Act, 1972, and the failure of respondents 03 and 06 to implement the Wildlife Management Plan for personal gain, resulting in losses to government revenue, human life, agriculture, and wildlife. It also confirms the disruption of the ecological balance of wildlife.

(Annexure 7)

24. It is noted that within the Hazaribagh forest division, three coal block projects of the user agency NTPC, namely the Pankri Barwadih Coal Project, Chatti Bariatu Coal Project, and Keredari Coal Block Project, as well as other coal blocks are located and operating by CCL and other companies. These projects received Forest Clearance and environmental approval between 2009 and 2013. However, no concrete work has been done on the Wildlife Management Plan. The respondent, NTPC, has made a clear statement regarding forest conservation in this regard.

- This pertains to the Wildlife Management Plan, and according to information available with the then Divisional Forest Officer, Western Forest Division, Hazaribagh, in a letter dated 21/12/2023, it was noted that mining operations had commenced in certain

projects without a Wildlife Plan/CAT Plan. The details are as follows:

- M/s NMDC Limited (formerly allotted to M/s Essar Power Limited, Tokisud North Sub-block) 374.87 hectares: Final approval for the forest land diversion proposal was granted by the Government of India vide letter dated 28.12.2011, and the forest land included in the project has been released by the State Government vide letter no. 3145 dated 09.07.2014. Whereas, according to condition number 09 and condition number 14 of Stage 1, the user agency was required to implement the Conservation Plan, which has not yet been done. The details of which are described in the paragraph below.

- NTPC Pakri Barwadih (1026.438 hectares): The Stage II approval for the diversion of forest land for this project was granted in 2010. The user agency submitted the Site-Specific Wildlife Management Plan in 2023, which was approved by the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi, vide office order number 33, memo number 1006 dated 03.08.2023. However, mining has been operational since 2016. Even after the approval, no funds have been received from CAMPA for mitigation measures.

- Magadh OCP Project (96.72 hectares) under Chatra South Forest Division: Final approval for this project was granted by the Government of India vide letter dated 18.10.2010, and the forest land included in the project was released by the State Government vide letter number 3276 dated 22.06.2015.

- This is mentioned in condition number 18 of the project: "The user agency shall bear the cost of implementation of the conservation plan to be prepared in consultation with

the Chief Wildlife Warden (CWLW) of the State for the Hazaribagh National Park and its buffer zone adjoining the CCL mining zone."

- Compliance with the said condition remained pending even after the commencement of mining operations. When CCL submitted a proposal to the Government of India for the diversion of 192.36 hectares of forest land for the new Magadh OCP project, the Government of India discussed certain points, three of which related to the WLMP of Magadh OCP (96.72 hectares).

- Subsequently, the user agency prepared and submitted a Wildlife Management Plan, which was approved by the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi, vide office order number 39, memo number 1473 dated 29.11.2023. However, mining operations have been ongoing since 2016.

- The final paragraph of the above report states that this observation is based on experience and is mentioned in the Site Inspection Report. This is because the adverse effects on wildlife and soil erosion begin as soon as mining operations commence. A delay in implementing the Wildlife Plan/CAT Plan prevents the objectives from being achieved. In light of this, it is suggested that arrangements should be made to begin the implementation of the Wildlife Plan/CAT Plan concurrently with the mining operations so that its objectives can be fulfilled. (Annexure 8)

Respondent No. 04, the user agency NTPC was granted Forest Clearance and Environment Clearance for 20-year mining lease however failed to fulfil and blatantly violated the terms and conditions 14 years, citing various misleading reasons for personal gain.

25. That the respondent No. 04, NTPC, had obtained Forest Clearance (FC) in the year 2010 and Environment Clearance (EC) in the year 2009. However, even after almost 14 years, they have failed to comply with the conditions, citing various misleading reasons for their personal gain, and are ruthlessly violating them. This is evident from the letter No. 1210 dated 23.06.2025 written by the Regional Chief Conservator of Forests, Hazaribagh to the Divisional Forest Officer, Hazaribagh. The details are as follows:

- It is noted that the user agency, respondent 04 NTPC, has not yet fully enclosed the safety zone area as per condition number 2.6 of the FOREST CLEARANCE (FC) Stage-2, but has only fenced approximately 6000 meters with a single layer of barbed wire. The safety zone requires comprehensive two-tiered fencing. Due to the lack of two-tier fencing in the safety zone, its regeneration is also not taking place. The implementing agency stated that approximately 37,000 saplings were planted in the safety zone, but the photographs show a deplorable state of regeneration. The implementing agency was directed to construct a two-tier chain-link fence around the entire safety zone area and undertake intensive tree plantation in this area during this monsoon season. However, no compliance report has been submitted by the implementing agency so far. The fencing, protection, and regeneration work of the safety zone will be carried out from the project cost. In addition, afforestation will also be carried out on an area one and a half times of the safety zone, on damaged forest land to be selected also from the project cost. Therefore, you were asked to conduct a site inspection of this area, either personally or through the Assistant Conservator of Forests, to ensure full compliance with this condition.

- It was noted that regarding condition 8.1 of FOREST CLEARANCE (FC) Stage 2, which stipulated the creation of a 50-meter green belt along the banks of the Pakwa and Khuri Nala, the user agency, NTPC, did not provide any

response regarding its compliance. It is clear that compliance is pending. They have also been directed by the undersigned to create a 50-meter green belt on both sides of the Pakwa and Khurs Nala.

- Furthermore, regarding condition 19 of FOREST CLEARANCE (FC) Stage 2, the user agency's representative stated that they had undertaken the renovation of several old ponds and the construction of new ones, but no list was provided. A list of the desilted ponds was requested from them, which is still awaited. You are requested to obtain the complete list from the user agency, verify it at your level, and ensure that a compliance report is submitted.

(Appendix 9)

26. The user agency, respondent 04 NTPC, has failed to fulfil several important conditions even after receiving the Environment Clearance (EC) in 2009. These conditions relate to public interest, wildlife protection, safety, and public welfare. Despite this, respondent 04, citing various misleading reasons to serve its private interests, has not fulfilled these conditions even after approximately 14 years. Regarding this matter, Mr. Munna Kumar Shah, Scientist "E" in the Compliance & Monitoring Division - I.A Division of the MOEF & CC, wrote a letter to respondent 04 on October 20, 2023, the main points of which are as follows:

"3. The monitoring report submitted for the project by RO, Ranchi has been examined in the Ministry and following are observed non-compliances with respect to said EC letter on the basis of review of IRO's report:

- i. Violation/non-compliance of the provision of Forest Clearance Act. (Specific Condition: II)

- ii. Necessary fund for construction of road upto the Monolith and park around to the state Govt. yet has not been released. (Specific Condition: III)

- iii. Siltation ponds, gabions have not been constructed in South West direction, Siltation Pond has not been properly maintained, grassing, vegetation, plantation has not been developed near Lathorwa nallah, gabions has not been developed in between slope and nallah, no embankment between dump D of eastern quarry and pakka nallah has been constructed (Specific Condition: IV)

- iv. Catch drains and siltation ponds have not been constructed for other portion of top soil dump. (Specific Condition: V)

- v. Grassing and vegetation on the slopes of the OB dump has not been developed properly also, the slope of the section has not been submitted. (Specific Condition: VI)

- vi. Catch drains and siltation ponds at many places as specified by IRO has not been constructed and maintained. (Specific Condition: VII)

- vii. Retaining wall at the toe of the OB dump has not constructed at many places as specified by IRO. (Specific Condition: VIII)

- viii. 3-tier avenue plantation has not been developed as per the EC condition. Transportation of Coal has is not being done as per the EC conditions dust emission has not been controlled effectively (Specific Condition: IX)

- ix. Inadequate Dust control system to control the dust emission. (Specific Condition: XII)

- x. Development of Rainwater harvesting structure wherever feasible. (Specific condition: XIII).

- xi. Maintenance of Oil & grease trap and operational status of STP. (Specific Condition: XV) (General condition; VII)
- xii. Completion of Plantations in some portions (as specified by IRO) of OB dumps (Specific Condition: XVI).

- xiii. Status and completion of R&R Plan (Specific Condition: XIX)

- xiv. Implementation of the report of Department of Forestry, wildlife & Environmental Sciences, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh (Specific Condition: XXI).

- xv. Date till which eastern quarry of the project was operational. (General Condition: 1) xv.
- xvi. Installation of CAAQMS near Mining operations area in consultation with JSPCB officials. (General condition: III) xvi.

- xvii. Fugitive dust emission from all sources has not been controlled properly. Water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, and dump truck has not been adequately maintained. (General Condition: IV).

- xviii. Submit the details of proper collection and treatment of Industrial wastewater. (General Condition: VII).

- xix. Details of whether funds earmarked for environmental protection measures have been kept in separate accounts. (General Condition: XII)

"4. In view of the foregoing, the Project proponent (PP) is hereby directed to submit the clarification/Action Taken Report (ATR) for observed non-compliance within the next 30 days from the

date of issuance of this letter. It may be noted that, if no satisfactory reply is received within the prescribed time frame, the Ministry will be constrained to take necessary action as deemed fit and appropriate in the circumstances of the case which inter-aralia include issuance of Show-Cause Notice under the provision of section (5) of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Appendix 10)

27. The allegations and lawsuits mentioned by Respondent 04 in his affidavit against the applicant are incomplete, misleading, and deliberately distorted, written maliciously without concrete evidence and lacking knowledge of the current status of the cases. This is because all of these cases are under investigation by the Criminal Investigation Department of Jharkhand. Some of these cases have been proven false, and I have been acquitted in others. It is important to mention here that Respondent 04 has been misusing his influence to implicate me and other affected individuals in false cases, so that he can suppress and conceal the irregularities occurring within the project area and continue to fulfil his personal interests. The collusion and personal gain of Respondent 03 and Respondent 04 can be understood from the aforementioned facts in the Criminal Investigation Department's report.

- It is particularly noteworthy that after I complained about the illegal activities of respondent 04, an official of Triveni Sainik Mining Private Limited, the company carrying out mining operations under respondent 04, attempted to bribe and manipulate the applicant (me).
- This has been confirmed in the investigation report sent by the Criminal Investigation Department, Ranchi, to the Government of Jharkhand for action, based on my complaint against Respondent 03 and Respondent 04.

- The Criminal Investigation Department, in its investigation report sent to the Government of Jharkhand for action, confirmed that Respondent 03 and Respondent 04, in

collusion, illegally mined the Dumuhani drain, which was originally 20 to 30 meters wide on average, in violation of the FC conditions of the mining lease, reducing its width to merely four to five meters and obstructing its flow. It also confirmed that Respondent 03, in collusion with others and for personal gain, created a fraudulent report to cover up these actions. This confirmation is included in the report sent by the Criminal Investigation Department to the Government of Jharkhand for necessary action.

- The Crime Investigation Department's report stated that Respondent 03 had altered his initial report and submitted a second report to protect Respondent 04.

- • The Crime Investigation Department's report also confirmed that Respondent 03 had deliberately concealed and misinterpreted points from the Jharkhand government's Water Resources Department guidelines in his report to shield Respondent 04.

(Annexure 11)

28. The respondent, NTPC, claims to be a Government of India company and the number one company in the country for producing record amounts of coal to meet the nation's energy needs. However, the aforementioned facts, evidence, and testimonies prove that NTPC, in collusion with the local district administration and forest department, has been continuously misleading the Hon'ble Supreme Court, tribunals, and other institutions by presenting false information at every level, disregarding the mandatory conditions imposed by the Government of India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC), which were put in place to protect human welfare, wildlife, and ecological balance. This is clearly evident from the details provided above.

29. With the permission of the Hon'ble Tribunal, I would like to submit further documentary evidence regarding the irregularities occurring in other coal projects in the area, including the one currently involving Respondent 04. These irregularities include the creation of forged documents to obtain No

Objection Certificates from the MOEF&CC and the submission of fraudulent documents under the Forest Rights Act. Respondent 03 has misled the Hon'ble Tribunal and the Hon'ble Supreme Court, obtaining orders through deception and using them for personal gain. This is contrary to the judicial process and against the principles of natural justice.

30. I declare that all the above-mentioned details and evidence are true and authentic to the best of my knowledge. I am presenting them before the Hon'ble Tribunal with full responsibility and with due respect and a sense of justice.

31. This counter-affidavit is being submitted in good faith and in the interest of justice and public welfare. You are requested to kindly excuse and accept any unintentional legal errors or omissions in this counter-affidavit, considering it as an effort made towards human welfare, wildlife and ecological welfare.

Yours faithfully

Mantu Soni alias Shani Kant
S/o Sh. Rajesh Kumar
Barkagoan, Dist.- Hazaribagh, Jharkhand
Pin – 825311
Mob: 9504268699

Date: 15.09.2025